For More Newspapers And Magazines Join Paid Group Whatsapp To 8969469464
www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
गुरुवार 8 फरवरी, 2024

दैनिक जागरण

एक बार आरंभ होने के बाद कोई भी कार्य आसान हो जाता है

## क्षेत्रवाद पर प्रहार

राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते समय प्रधानमंत्री ने वैसे ही कांग्रेस को निशाने पर रखा, जैसे उन्होंने लोकसभा में रखा था। अपने संबोधन में उन्होंने कर्नाटक की पूरी सरकार की ओर से दिल्ली में किए जा रहे विरोध प्रदर्शन का जिक्र किए बिना उसे देश को बांटने की एक साजिश करार देकर कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला ही किया। उन्हें यह हमला इसीलिए करना पड़ा, क्योंकि उक्त प्रदर्शन में खुद कर्नाटक के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। उन्होंने यह प्रदर्शन इसलिए किया, ताकि यह साबित कर सकें कि केंद्र सरकार कर्नाटक के वित्तीय हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि इस आरोप का खंडन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने टैक्स बंटवारे के मसले को तूल देना आवश्यक समझा और इसीलिए वह अपने उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और अन्य मंत्रियों के साथ दिल्ली प्रदर्शन करने आ गए। ध्यान रहे कि डीके शिवकुमार के भाई और कांग्रेस के सांसद डीके सुरेश ने अंतरिम बजट को लेकर यह कहा था कि दक्षिण का पैसा उत्तर में बांटा जा रहा है और यदि ऐसा ही होता रहा तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश की मांग करनी पड़ सकती है। यह क्षेत्रवाद के साथ अलगाववाद को जानबूझकर हवा देने के अलावा और कुछ नहीं। इस प्रवृत्ति पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने यह सही कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के चलते देश को तोड़ने के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने यह स्पष्ट करने में भी संकोच नहीं किया कि हमारा टैक्स हमारा पैसा जिस भाषा में बोला जा रहा है, वह देश के लिए नया खतरा पैदा करने वाला है।

समझना कठिन है कि जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे डीके सुरेश के बयान पर आपत्ति जता चुके थे, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री दिल्ली में प्रदर्शन करने क्यों चले आए? यदि कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि उसके मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रदर्शन करने लगें। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने यही किया। यदि कोई राज्य सरकार टैक्स बंटवारे को लेकर संतुष्ट नहीं तो उसे धरना-प्रदर्शन का सहारा लेने के बजाय वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री से संवाद करना चाहिए। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए ऐसा नहीं किया। इससे यही पता चलता है कि राष्ट्रीय दल होने के बाद भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री किस तरह क्षेत्रीय दलों के नेताओं की तरह व्यवहार करने लगे हैं। यह अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह क्षेत्रवाद की राजनीति पर प्रहार किया, वैसे ही उन्होंने लोकसभा में अल्पसंख्यकवाद की राजनीति को भी निशाने पर लिया था, क्योंकि यह प्रश्न किया जा रहा था कि किसानों, महिलाओं, युवाओं के कल्याण की योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए क्या है? इस तरह के प्रश्न देश को बांटने वाली राजनीति को ही रेखांकित करते हैं।

## समान नागरिक संहिता

भारत के संविधान के निर्माण के समय संविधान सभा ने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रहित में देश में समान नागरिक संहिता उपयुक्त समय पर बनाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी विभिन्न मामलों की सुनवाई में समान नागरिक संहिता लागू करने के पक्ष में उचित टिप्पणी कर चुका है। बावजूद इसके स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता को लेकर किसी स्तर पर प्रभावी पहल नहीं हो पाई। लंबी प्रतीक्षा के बाद अब मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड ने यह कदम उठाने का साहस दिखाया। प्रदेश में सत्तारूढ़ धामी सरकार ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का जनता से वादा किया। दोबारा सत्ता संभालते ही धामी कैबिनेट ने पहली ही बैठक में संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने को विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया। समिति से ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार ने देरी नहीं लगाई और विधानसभा सत्र में इसका विधेयक भी प्रस्तुत कर दिया। दो दिन की चर्चा के बाद सदन में यह पारित हो चुका है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए सिविल कानून समान होंगे। संहिता में महिला अधिकारों को अधिक संरक्षित किया गया गया है तो विवाह और विवाह विच्छेद को पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। लिव इन रिलेशनशिप में भी कानूनी दायरे के भीतर दोनों पक्षों के हित सुरक्षित किए गए हैं। ऐसे ही तमाम प्रविधान किए गए हैं। राजनीतिक गलियारों में धामी सरकार की इस पहल के चाहे जो निहितार्थ निकाले जाएं, लेकिन यह कदम अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनने जा रहा है। वे भी इसी तरह अपने यहां समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। इससे पूरे देश में बेहतर माहौल का निर्माण होने के साथ ही केंद्र सरकार के स्तर पर भी इसके लिए राह तैयार होगी। कुल मिलाकर राज्य की समान नागरिक संहिता की पहल के दूरगामी परिणाम सामने आएंगे।

# घातक असर वाला इजरायल-हमास संघर्ष

शिवकांत शर्मा

**समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है**

इजरायल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को रोकने के लिए एक और प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। हालांकि इस प्रस्ताव की शर्तों को देखते हुए तत्काल कोई सहमति बनने के आसार कम ही दिखते हैं। इस लड़ाई को छिड़े हुए करीब चार महीने पूरे होने को हैं। इसमें 27,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति और कूटनयिक प्रयासों के बावजूद यह लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन हमलों के रूप में लेबनान, यमन, सीरिया, इराक और जार्डन समेत आसपास के दस देशों में फैल चुकी है। यमन के ईरान समर्थक हाउती आतंकियों के हमलों से लाल सागर से होने वाला समुद्री व्यापार लगभग ठप हो गया है। जहाजों को अफ्रीका का चक्कर काटकर यूरोप-अमेरिका जाना पड़ रहा है, जिससे कीमतें बढ़ रही हैं।

अमेरिका में यह चुनावी वर्ष है और यूरोप में चल रही यूक्रेन और रूस की लड़ाई में यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पा रहा है। ऐसे समय में अमेरिका ऐसी किसी और लड़ाई में नहीं उलझना चाहता, जिससे रूस को यूक्रेन की और जमीन हथियाने और यूरोप में दबदबा कायम करने का अवसर मिल जाए। यही कारण है कि अमेरिका ने सीरिया में जार्डन की सीमा पर स्थित अपने सैन्य अड्डे पर 28 जनवरी के ड्रोन हमले का जवाब तत्काल देने के बजाय सोच-विचार कर देने का निश्चय किया। ड्रोन हमले में अमेरिका के तीन सैनिक मारे गए थे और 30 से अधिक घायल हुए थे। यद्यपि ईरान ने हमले में अपनी प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका से इन्कार किया, फिर भी अमेरिका का मानना है कि यह हमला सीरिया में सक्रिय जैनाबियून ब्रिगेड और फतेमियून डिविजन के या इराक में सक्रिय इस्लामी प्रतिरोध मोर्चे के किसी गुट ने किया है, जिन्हें प्रशिक्षण और हथियार ईरान का इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड देता है। अमेरिकी रक्षामंत्री लायड आस्टिन ने स्वीकारा कि हमास-इजरायल युद्ध के बाद से इराक और सीरिया में स्थित अमेरिकी ठिकानों पर 160 हमले हुए हैं। अपनी नाक बचाने के लिए अमेरिका ने ईरान समर्थित इस्लामी प्रतिरोध गुटों के ठिकानों पर जवाबी हवाई हमले किए, परंतु वह लड़ाई को फैलाना नहीं चाहता। इसीलिए वह अपने अरब मित्र देशों के साथ मिलकर लंबे युद्धविराम के एक सौदे पर काम कर रहा है।

अमेरिका के साथ-साथ मिस्र की दिलचस्पी युद्धविराम में सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्वेज नहर उसकी आमदनी का प्रमुख स्रोत है और लाल सागर का व्यापार ठप होने से स्वेज नहर से होने वाली आमदनी कम हो गई है। इसीलिए हमास नेता इस्माइल हानिया ने पिछले दिनों काहिरा जाकर नए युद्धविराम प्रस्ताव पर दो दिनों तक विचार किया। इस सौदे में दो बड़ी अड़चनें हैं। हानिया की मंशा है कि बंधकों की रिहाई और युद्धविराम के बाद इजरायल गाजा से हट जाए और अंतरराष्ट्रीय सेना की देखरेख में फलस्तीन के राजनीतिक समाधान की बातचीत शुरू हो। नेतन्याहू गाजा से हमास की हस्ती मिटाए बिना वहां से नहीं हटना चाहते।

संभव है कि दबाव में आकर नेतन्याहू और हानिया थोड़े दिनों के लिए कोई सौदा कर लें, लेकिन वह टिकाऊ नहीं होगा। नेतन्याहू का गठबंधन ऐसे कट्टरपंथी जायनिस्ट दलों के समर्थन पर टिका है, जो जार्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन पर यहूदियों का दैविक अधिकार मानते हैं। जबकि हमास जार्डन नदी से समुद्र तक फैली जमीन को फलस्तीनी और इजरायल को उस पर कब्जा करके बैठा देश मानता है। स्थायी युद्धविराम होते ही इजरायल में चुनाव की मांग उठेगी, जिसमें नेतन्याहू का हारना लगभग तय है। यदि लड़ाई जारी रहती है और नेतन्याहू गाजा से हमास की जड़ें उखाड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो हमास का राजनीतिक अस्तित्व उसी तरह समाप्त हो जाएगा, जैसे सीरिया से इस्लामिक स्टेट का हुआ था।

इजरायल हमास युद्ध एक नाजुक दोराहे पर है। एक रास्ता बंधकों के बदले लंबे युद्धविराम की ओर जाता है। इसका प्रयोग अमेरिका और अरब देश मिलकर सुलह की ऐसी रूपरेखा तैयार करने में कर सकते हैं जिसके सहारे अरब या अंतरराष्ट्रीय देखरेख में गाजा और पश्चिमी किनारे पर नया फलस्तीनी शासन कायम हो सके। इजरायल को सुरक्षा से जीने का भरोसा मिल सके और फलस्तीनियों को स्वतंत्रता से जीने और अपनी सरकार बनाने का हक मिल सके। ऐसा होने पर इजरायल और सऊदी अरब के संबंधों के बढ़ने की प्रक्रिया बहाल हो सकेगी और अमेरिका की प्रस्तावित भारत-पश्चिम एशिया कारिडोर योजना भी आगे बढ़ सकेगी। इसमें दो बड़ी अड़चनें हैं। गाजा में हुए भारी संहार और विनाश के बाद हमास जैसे संगठनों को दोबारा पनपने से कौन रोकेगा? दूसरी बड़ी अड़चन है वे यहूदी बस्तियां, जिन्हें इजरायल ने पिछले 57 वर्षों के कब्जे के दौरान फलस्तीनियों के पश्चिमी किनारे पर बसाया है। क्या इजरायली सरकार उन्हें वहां से हटा पाएगी? दूसरा रास्ता युद्धविराम की जगह सीमित और लक्षित युद्ध जारी रखने की ओर जाता है, जिस पर नेतन्याहू अड़े रहना चाहते हैं, क्योंकि उनका राजनीतिक अस्तित्व उसी पर टिका है। वह हमलों को तब तक नहीं रोकना चाहते, जब तक हमास का पूरी तरह सफाया नहीं हो जाता। इस रास्ते का सबसे बड़ा खतरा यही है कि इतने व्यापक संहार और विनाश के बाद फलस्तीनियों के साथ-साथ अरब देशों में भी इजरायल और पश्चिम के प्रति रोष की भावना फैल सकती है, जो हमास जैसे संगठनों के लिए जमीन तैयार करेगी। पश्चिमी किनारे और लेबनान में रोष पहले से ही उबाल पर है। हिजबुल्ला के किसी राकेट से इजरायली बस्ती को बड़ी क्षति होते ही इजरायल को अपनी उत्तरी सीमा पर भी लड़ाई में कूदना पड़ सकता है। यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थक प्रतिरोधी गुट अमेरिकी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। किसी जहाज या अड्डे को कोई बड़ी क्षति हुई तो अमेरिका को भी युद्ध में उलझना पड़ सकता है। लाल सागर का रास्ता बंद होने से विश्व व्यापार को वैसे ही क्षति हो रही है। समूचे पश्चिम एशिया में लड़ाई फैलने से ईरान के युद्ध में उतरने और तेल की कीमतों में उबाल का भी खतरा है। ऐसी भयावह आशंकाओं को देखते हुए भलाई इसी में लगती है कि इजरायली जनता ही अपनी सरकार को बदले या फिर उस पर युद्धविराम का दबाव डाले। अमेरिका के प्रसिद्ध राजनयिक हेनरी किसिंजर ने ठीक ही कहा था, 'इजरायल की कोई विदेश नीति नहीं है, सिर्फ घरेलू राजनीति है।'

(लेखक बीबीसी हिंदी के पूर्व संपादक हैं)

response@jagran.com

हाउती विद्रोहियों के हमलों से प्रभावित हो रहा समुद्री व्यापार। एएफपी

# विकृत इतिहास लेखन के दुष्परिणाम

हरेंद्र प्रताप

**इस्लामी हमलावरों के रक्तरंजित इतिहास के बावजूद वामपंथी हमेशा उनका महिमामंडन ही करते रहे**

अयोध्या में श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इन दिनों पूरा देश राममय है। इन्हीं प्रभु श्रीराम को काल्पनिक बताकर नकारने के लिए वामपंथी इतिहासकारों ने क्या-क्या तिकड़में नहीं कीं। हिंदुओं के आराध्य देवों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगाने के लिए कई पुस्तकें तक लिखी डालीं, जो दुर्भाग्य से बाद में हमारे स्कूल-कालेजों के पाठ्यक्रमों का हिस्सा बन गईं। 'प्राचीन भारत में विज्ञान और सभ्यता' नामक पुस्तक में प्रभु श्रीराम के बारे में वामपंथी इतिहासकार आरएस शर्मा ने लिखा कि 'पुराणों की परंपरा के आधार पर श्रीराम का जन्म अयोध्या में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व हुआ था, पर खोदाई से यह सत्य सामने आया कि उस समय वहां मानव की कोई बस्ती थी ही नहीं।' आरएस शर्मा ने अपने इसी तर्क के आधार पर अपनी पुस्तक में 'प्रभु श्रीराम को काल्पनिक पात्र' घोषित कर दिया था। आजाद भारत में शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत के बारे में जो कुछ पढ़ाया जाता रहा, वे सब पुस्तकें वामपंथियों ने लिखी थीं। इस कारण आरएस शर्मा द्वारा लिखित 'प्राचीन भारत' तथा सतीश चंद्रा द्वारा लिखित 'मध्यकालीन भारत' को पढ़कर तैयार हुईं पीढ़ियां न केवल अभारतीय होती रहीं, बल्कि वे भारत को हीन भाव से भी देखने लगीं। इन वामपंथियों ने अपनी पुस्तकों में प्रभु श्रीराम, श्रीकृष्ण और अर्जुन को इतिहास का काल्पनिक पात्र घोषित कर दिया था।

पहले अयोध्या में श्रीराम मंदिर और अब वाराणसी के ज्ञानवापी का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए वैज्ञानिक सर्वे में वहां प्राचीन काल में भव्य मंदिर होने के प्रमाण सामने आ रहे हैं। इस्लामी आक्रांताओं ने भारत के मंदिरों को तोड़ा और बलात मत परिवर्तन कराया। इस्लामी हमलावरों का इतिहास रक्तरंजित है, पर वामपंथियों ने उनको महिमामंडित किया। उनके द्वारा तोड़े गए आस्था के केंद्रों का भी आरोप वामपंथियों ने साजिशन हिंदुओं पर लगा दिया। सतीश चंद्रा ने 'मध्यकालीन भारत' में लिखा है कि हिंदुओं ने बौद्ध और जैन मंदिरों को न केवल तोड़ा, बल्कि उन्होंने बलपूर्वक कब्जा किया। सतीश चंद्रा के अनुयायी आंखें खोलकर देख लें कि न्यायालय में आज हिंदुओं की तरफ से लड़ने वाले वकील पिता-पुत्र हरिशंकर और विष्णु 'जैन' हैं। आरएस शर्मा, सतीश चंद्रा, रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा और इरफान हबीब द्वारा लिखी पुस्तकें माध्यमिक से लेकर उच्चतर स्तर तक पढ़ाई जाती रहीं। इनकी पुस्तकों को पढ़कर तैयार हुई पीढ़ियां इस देश और इसकी सच्चाई को नकारने के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार हैं। इसका जीवंत उदाहरण वामपंथी हैं।

22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद वामपंथियों की प्रतिक्रिया उनके विकृत सोच को प्रकट करती है। एक वामपंथी ने अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा वाली 'मूर्ति' के बारे मे लिखा, 'रामलला के हाथ में धनुष-तीर दिखलाना अपराध है। पांच साल के बालक के हाथ में शस्त्र-जुवेनाइल एक्ट के अनुसार कार्रवाई हो।' संभव है आने वाले दिनों में वामपंथी अपने लोगों को सक्रिय करके इस पर बहस भी छेड़ दें। वे इस विषय को प्रचारित कर सकते हैं कि बच्चे श्रीरामलला की मूर्ति देखकर हिंसक हो सकते हैं। अतः उसे हटाया जाए। अयोध्या में खोदाई से ही पता चला था कि वह एक प्राचीन मंदिर था। आखिर आरएस शर्मा ने किस खोदाई के आधार पर यह लिखा कि ईसा से 2000 वर्ष पूर्व वहां कोई मानव बस्ती थी ही नहीं। दुर्भाग्य देखिए कि उनसे इसका प्रमाण मांगे बिना उनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती रहीं। अगर प्रभु श्रीराम काल्पनिक थे तो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को सबसे पहले ठुकराने वाले वामपंथी नेता का नाम उनके माता-पिता ने सीताराम येचुरी क्यों रखा? माता-पिता का प्रभु श्रीराम-माता सीता के प्रति जो आस्था थी, उसको नकारने का साहस वामपंथी विषवमन का सबसे बड़ा प्रमाण है। अयोध्या में प्रभु श्रीराम के जन्मस्थान के बारे में फैसला आ जाने के बाद भी 'बाबरी मस्जिद' कह कर भारत के मुसलमानों को भड़काने का असफल प्रयास चल रहा है। भारत के संविधान और पूजा स्थल कानून का हवाला देकर अयोध्या के बाद अब ज्ञानवापी की सच्चाई को भी नकारा जा रहा है।

अयोध्या, मथुरा और काशी की बात करने पर सेक्युलर जमात बाबर-अकबर और औरंगजेब को सेक्युलर बताने का चाहे जितना भी षड्यंत्र कर ले, लेकिन वह सफल नहीं होगा। वह इससे मुंह नहीं मोड़ सकता कि औरंगजेब एक बेहद बर्बर शासक था। उसने अपने भाई दारा शिकोह का सिर काटकर उसे पिता शाहजहां के सामने पेश किया था। उसने तमाम मंदिर तोड़े और सिख गुरुओं को निर्ममता से मारा। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में पुरातत्व सर्वेक्षण का मामला न्यायपालिका के तहत विचाराधीन है, लेकिन इसे न्यायालय में लटकाने के सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि हमें मुगलों से कुछ भी लेना-देना नहीं है, पर जब भी मुगलों के काले कारनामों पर से पर्दा उठता है तो उनके बचाव में वह सामने आ जाते हैं। इबादतगाह को तो बदला जा सकता है, पर पूजा स्थल को नहीं। न्यायालय में जाकर सच्चाई को सामने लाने के लिए हिंदू सर्वे या खोदाई की मांग कर रहे हैं। समय का तकाजा है कि हिंदुओं के प्रमुख पूजा स्थलों को वापस किया जाए। यह समय की मांग है कि अगर मुगलों की बर्बरता पर से पर्दा उठता है तो उसमें बाधाएं न डाली जाएं। सच सामने आना ही चाहिए। इसके साथ ही सरकार और देश का प्रबुद्ध वर्ग आगे आकर वामपंथी इतिहासकारों की पुस्तकों को पाठ्यक्रमों से हटाने की पहल करें। तभी भारत अपने मूल स्वभाव के साथ आगे बढ़ सकेगा।

(लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं)

response@jagran.com

हमलावरों का महिमामंडन। फाइल

ऊर्जा

## सत्ता की सार्थकता

संस्कारों का निर्माण युगों की साधना से होता है। संस्कार दृढ़ता एवं विनम्रता का परिचायक है। संस्कारवान या ज्ञानी व्यक्ति जब सत्ता पर आरूढ़ होता है तो विवेकशून्य नहीं होता और परमार्थ एवं आदर्श निर्माण के मार्ग से किंचित भी विचलित नहीं होता है। न ही मदांध हो अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए पद एवं शक्ति का दुरुपयोग करता है। वहीं सत्ता की बागडोर संभालते ही अज्ञानी या संस्कारहीन व्यक्ति ईश्वर-विमुख हो अहंकार के घोड़े पर सवार होकर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघने को विवश हो जाता है।

ईश्वर किसी भी मनुष्य को सत्ता एवं शक्ति महज संसार के कल्याण एवं स्वयं के आत्मोत्थान के लिए प्रदान करते हैं। इन दुर्लभ अवसरों का उपयोग जो गुणीजन समाज एवं राष्ट्र की जीवनीशक्ति के लिए करते हैं, वे इतिहास में अमिट हो जाते हैं, जबकि स्वार्थी एवं अज्ञानी इसका उपयोग स्वयं एवं अपने परिजनों के कल्याण के लिए कर अपने पद तथा कद को कलुषित करते हैं। कोई भी प्रतिभा तभी फलीभूत होती है जब उसका लक्ष्य लोक-कल्याण हो। स्वार्थ केंद्रित सत्ता अथवा साधना अपनी शक्ति के क्षरण के लिए अभिशप्त होती है। निःस्वार्थ साधना अथवा सत्ता का सदुपयोग सत्ताधारी को शाश्वत यश एवं सम्मान का भागी बनाता है। वहीं जब कोई व्यक्ति सत्ता में आने के बाद विध्वंस का कारण बनता है तो वह दैवीय अनुकंपा से मिले इस दुर्लभ जीवन अवसर का दुरुपयोग करता है। इसके दंडस्वरूप उसके भावी जीवन की संपूर्ण सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। अतः सत्ता की सार्थकता राष्ट्र एवं लोक हित में है। अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता से मानवता, परमार्थ एवं उन्नत समाज के कल्याण में है। सत्ता का दुर्लभ अवसर पाकर भी राष्ट्र के लिए कुछ विशिष्ट एवं उल्लेखनीय न कर पाने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समय एवं इतिहास कभी क्षमा नहीं कर सकता।

प्रो. दिनेश चमोला 'शैलेश'

# सर्जरी से प्रसव का बढ़ता चलन

देवेंद्रराज सुथार

**विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज विश्व में पांच में से एक बच्चा सर्जरी के माध्यम से जन्म लेता है**

भारत में सिजेरियन यानी आपरेशन से डिलीवरी (प्रसव) की संख्या बढ़ रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-पांच के मुताबिक देश में सिजेरियन के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं की तादाद में वृद्धि देखी गई है। जहां राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-चार में 2015-16 के दौरान आपरेशन के जरिये बच्चे को जन्म देने वाली महिलाओं का आंकड़ा 17.2 प्रतिशत था, वह 2019 से 2021 के बीच बढ़कर 21.5 प्रतिशत पर पहुंच गया। शहरी क्षेत्रों में तो यह 32.3 प्रतिशत पर पहुंच गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 17.6 प्रतिशत दर्ज किया गया है। यह वृद्धि एक चुनौती खड़ी करती है। खासकर तब जब निजी स्वास्थ्य क्लीनिक ऐसे प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की तुलना में पसंदीदा विकल्प बनते जा रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व स्तर पर पांच में से एक बच्चा सिजेरियन के माध्यम से पैदा होता है। आने वाले दशकों में यह आंकड़ा बढ़कर एक तिहाई होने की संभावना है। भारत भी इस प्रवृत्ति से अछूता नहीं है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम जैसे राज्यों में सिजेरियन प्रसव में वृद्धि दर्ज की गई है, जहां निजी क्लीनिकों को सरकारी सुविधाओं की तुलना में प्राथमिकता मिल रही है। सर्जरी के बाद कुछ जटिलताएं अक्सर बनी रहती हैं, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महिलाओं को प्रभावित करती हैं। यह आर्थिक बोझ भी पैदा कर रही है, क्योंकि सिजेरियन डिलीवरी में निजी अस्पतालों में सामान्य जन्म की तुलना में 10 गुना अधिक खर्च होता है। हालांकि सिजेरियन का विकल्प चुनने के कुछ वैध कारण भी हैं, जैसे चिकित्सा आवश्यकता या मां की पसंद। यह कुछ अस्पतालों के लाभ के उद्देश्यों से जुड़ी हुई भी प्रतीत होती है।

यह भी निर्विवाद है कि सिजेरियन डिलीवरी शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करने और शिशुओं में जन्मजात मानसिक विकलांगता के मामलों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि सिजेरियन डिलीवरी की बढ़ती प्रवृत्ति परिवारों पर बोझ डालती है। नेचर मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन अनावश्यक सिजेरियन प्रक्रियाओं को कम करने के महत्व पर जोर देता है। यह जरूरी है कि सरकार स्वस्थ गर्भवती माताओं में सामान्य प्रसव के लाभ के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अभियान चलाए। यह महिलाओं को मातृ स्वास्थ्य साक्षरता के साथ सशक्त बना सकता है, जो अंततः माताओं और शिशुओं दोनों के लिए एक स्वस्थ भविष्य में योगदान कर सकता है। माताओं और नवजात शिशुओं के हितों की रक्षा करने के लिए यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि चिकित्सकीय रूप से आवश्यक होने पर ही सिजेरियन डिलीवरी की जाए।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### जरूरी है जमीनी हकीकत का विश्लेषण

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में 'जगमोहन सिंह राजपूत' ने शिक्षा के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की महत्वपूर्ण जानकारी दी है। यूं तो शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार आर्थिक संसाधनों और शिक्षकों के अनुशासन पर विशेष ध्यान देती है, पर इसके साथ-साथ भारत के ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत पर भी सरकार को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होने पर अक्सर शिक्षकों पर गाज गिरती है, पर कोई यह नहीं देखता कि बच्चों के अभिभावक ही उनकी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। विद्यालय भेजने से ज्यादा जरूरी उनके लिए जीविकोपार्जन और खेती-बाड़ी का काम होता है। कहीं-कहीं तो यह भी देखने को मिला है कि सरकार की तरफ से बच्चों के यूनिफार्म आदि के लिए मिलने वाले धन का उपयोग अभिभावक अन्य जरूरतों को पूरा करने में कर लेते हैं और बच्चों को बिना यूनिफार्म के ही स्कूल जाना पड़ता है। सरकार की ओर से सरकारी स्कूलों में एप और स्मार्ट क्लास के जरिये पढ़ाने के आदेश दिए गए हैं, पर उन विद्यालयों का क्या जो आज भी आधारभूत सुविधाओं जैसे अच्छी सड़कें, अच्छा विद्यालय परिसर, जल, फर्नीचर, बिजली आदि से वंचित हैं। जहां मोबाइल का नेटवर्क तक सही नहीं आता क्या वहां डिजिटल शिक्षा पद्धति अपनाई जा सकती है? इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता सिर्फ भारी-भरकम बजट देने से या शिक्षकों के ऊपर तलवार लटकाने से नहीं बढ़ेगी, इसके लिए जरूरत है एक बेहतरीन विकास संचार की, जिसके जरिये जमीनी हकीकत का विश्लेषण हो सके। अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक हों। शिक्षकों को भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार होने की आवश्यकता है। भारत के बेहतर भविष्य के लिए सरकारी तंत्र की सक्रियता और अभिभावकों की शिक्षा के प्रति निष्क्रियता का अंत आवश्यक है।

सोनल वर्मा, प्रयागराज

### समाज की जरूरत हैं शिक्षक

'शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की चुनौती' शीर्षक से जगमोहन सिंह राजपूत का आलेख पढ़ने को मिला। सबसे पहले यह देखा जाना चाहिए कि जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं उनको पढ़ाना आता भी है या नहीं, उनको विषय का ज्ञान है या नहीं, शिक्षक की जिम्मदारी वे जानते हैं या नहीं। पहले के शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले खुद पढ़ते थे। समाज में शिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी है। उनके ऊपर ही छात्रों का भविष्य निर्भर है। आज छठी कक्षा के छात्र को दूसरी कक्षा का ज्ञान भी नहीं है। निःसंदेह यह शिक्षकों की निष्क्रियता को दर्शाता है। ऐसे में शिक्षकों को और जवाबदेह होने की जरूरत है। शिक्षक वही बनाया जाए जिसको पढ़ाना आता हो। उनकी बहाली में एक ही प्रक्रिया की जानी चाहिए। उनको किसी विषय पर पढ़ाने को कहा जाए। अगर वे पढ़ा पाएं तभी उनकी बहाली हो। शिक्षक कोई नौकरी नहीं है यह समाज की जरूरत है। देश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। समाज का हित होगा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।

अशोक कुमार दुबे, पटना

### वास्तविक रत्न हैं आडवाणी

'इसलिए भारत के रत्न हैं आडवाणी' शीर्षक आलेख में बलवीर पुंज ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने को बिल्कुल सही फैसला बताया है। वास्तव में आडवाणी जी ने भारत की राजनीति में शुचिता और ईमानदारी के लिए सर्वस्व अर्पण किया है। आज जब देश की राजनीति और नेताओं का एक विकृत स्वरूप लोगों की मानसिकता में एक स्थायी आकार ले चुका है उस समय लालकृष्ण आडवाणी जैसा नेता एक उदाहरण और आशा की किरण के रूप में सामने अवस्थित हो जाता है। देश की आजादी के बाद यदि किसी राजनेता ने भारतीय समाज को जनजागरण के एक नए और ऐतिहासिक दौर में प्रवेश कराया तो वह आडवाणी ही हैं। आडवाणी का सम्मान देश का सम्मान है।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, यूपी

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

********

**3.67** प्रतिशत का योगदान ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि फंड में, जिस धनराशि से पेंशन के लिए भी प्रविधान किया जाता है।

कर्मचारी भविष्य निधि

# न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का प्रश्न

**कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) 1995 के अंतर्गत, ऐसे कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्य हैं, उनके लिए न्यूनतम पेंशन का प्रविधान वर्ष 1995 में किया गया था, जिसे वर्ष 2014 में बढ़ाते हुए न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया गया गया। कुछ कर्मचारी संगठन पिछले कुछ समय से मूल पेंशन की रकम में वृद्धि एसं अन्य मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग कर रहे हैं**

निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली पेंशन की रकम को बढ़ाए जाने की हो रही है मांग। प्रतीकात्मक

डा. अश्विनी महाजन
प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत अभी अर्हता प्राप्त सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह मात्र की पेंशन का प्रविधान है। मजदूर संगठनों द्वारा बार-बार यह मांग की जा रही है कि सभी सदस्यों के लिए इससे कहीं अधिक पेंशन का प्रविधान होना चाहिए। अलग-अलग संगठनों ने इसके लिए अलग-अलग पेंशन राशि की मांग की है। इस संबंध में देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ की मांग है कि सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और पेंशन अंतिम आहरित वेतन का आधा तय किया जाना चाहिए। साथ ही, ईपीएस इस मामले में कोई अपवाद नहीं होना चाहिए।

देश में कर्मचारियों के लिए उनके नियोक्ता के हिसाब से अलग-अलग प्रकार की सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का प्रविधान है। एक तरफ 2004 से पूर्व में नियुक्त सरकारी कर्मचारी हैं, जिन्हें सरकार उनकी पूरी सेवा अवधि के बाद अंतिम वेतन के आधे के बराबर मासिक पेंशन के रूप में प्रदान करती है। वहीं वर्ष 2004 के बाद नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम का प्रविधान है, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा भविष्य निधि में योगदान दिया जाता है, जिसे नई पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है, और उसी संचित निधि में से योगदान पर आधारित पेंशन देने का प्रविधान है। नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारी भी पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन की मांग कर रहे हैं और कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली भी कर दी है।

निजी क्षेत्र के कर्मचारी ईपीएफओ के अंतर्गत आते हैं। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा राशि ईपीएफओ में जमा की जाती है और इस प्रकार से हर कर्मचारी द्वारा जमा कुल राशि पर हर साल घोषित दर के हिसाब से ब्याज लगाया जाता है। अपने सेवा काल के दौरान जमा की गई राशि और साथ ही ब्याज पर भुगतान सेवानिवृत्ति या नौकरी छोड़ने या छूटने पर कर्मचारी को कर दिया जाता है। वर्ष 1995 से ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी जमा राशि और ब्याज के अलावा न्यूनतम पेंशन का प्रविधान किया गया और उसे बाद में एक हजार रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाया गया। इसके बाद कर्मचारियों की निरंतर यह मांग रही है कि यह राशि अत्यंत कम है और इसमें वृद्धि होनी चाहिए।

नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा गैर ईपीएफओ कर्मचारियों एवं मजदूरों व छोटे व्यापारियों के लिए नई शुरुआत की गई है। गैर ईपीएफओ कर्मचारियों व मजदूरों के लिए एक राष्ट्रीय पेंशन योजना के रूप में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना प्रारंभ की गई है। व्यापारी और स्व-रोजगार युक्त व्यक्तियों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था है। इन दोनों योजनाओं में 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रतिमाह तक मासिक योगदान करना होगा। एक बार जब लाभार्थी 18-40 वर्ष की प्रवेश आयु में योजना में शामिल हो जाता है, तो लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर ग्राहक को, जैसा भी मामला हो, पारिवारिक पेंशन के लाभ के साथ तीन हजार रुपये की सुनिश्चित मासिक पेंशन डीबीटी द्वारा प्राप्त होगी। यह भी प्रविधान किया गया है कि यदि किसी ग्राहक ने लगातार योगदान का भुगतान नहीं किया है, तो उसे निर्धारित दंड शुल्क के साथ संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करके अपने योगदान को नियमित करने की अनुमति दी जाएगी।

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं स्वरोजगार युक्त लोगों को दी जाने वाली पेंशन का भुगतान मोटे तौर पर तब करना होगा, जब वर्तमान में इसके लिए जिन 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों ने सदस्यता ली है। यानी इस योजना के लिए राशि का प्रविधान कम से कम 20 वर्ष से पहले नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि ईपीएफओ के सदस्यों को यदि ऊंची पेंशन देनी पड़े तो उसकी देनदारी तुरंत ही ईपीएफओ के संचित फंड पर पड़ेगी और इतनी पेंशन देने के बाद ईपीएफओ की संचित राशि धीरे-धीरे समाप्त हो सकती है। ऐसे में ईपीएफओ में योगदान देने वाले कर्मचारियों को भविष्य में उनकी राशि वापिस करने में कठिनाई हो सकती है।

केंद्र सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ईपीएस, 1995 के तहत पेंशन फंड एक एकत्रित फंड है। पेंशन निधि में व्यक्तिगत खाते नहीं रखे जाते हैं। ईपीएस, 1995 के सदस्य सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर उनकी पात्रता के आधार पर निकासी लाभ या पेंशन के लिए पात्र हैं। 31 मार्च 2019 तक फंड के एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार पेंशन फंड घाटे में है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा वर्तमान में नियोक्ता के योगदान के रूप में वेतन के 1.16 प्रतिशत के रूप में लगभग आठ हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है। इसके अलावा न्यूनतम पेंशन के एक हजार रुपये के भुगतान के लिए लगभग एक हजार करोड़ रुपये का योगदान दिया जा रहा है। इसलिए न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाए जाने के बाद बजट से बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी और पूरा बोझ केंद्र सरकार पर पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार ईपीएफओ में इस पेंशन को बढ़ाने का निर्णय लेती है तो उसे उसी अनुपात में इसका बोझ उठाना होगा।

**सुप्रीम कोर्ट का निर्णय** : सुप्रीम कोर्ट ने चार नवंबर 2022 के अपने निर्णय में 15 हजार से ऊपर के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन स्कीम, 1995 के अंतर्गत यह निर्देश दिया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए नियोक्ताओं का योगदान 8.33 प्रतिशत की बजाय 9.49 प्रतिशत रहेगा। इस अतिरिक्त राशि का भुगतान केंद्र सरकार करती है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारियों का योगदान इस योजना में वेतन का 12 प्रतिशत रखा गया था। इस संबंध में जिन कर्मचारियों की पात्रता पाई गई, उनके संबंध में उन्हें डिमांड नोटिस जारी कर दिए गए। इस संबंध में विकल्प उन्हीं कर्मचारियों द्वारा भरे जा सकते हैं, जो एक सितंबर 2014 को या उससे पूर्व सेवा में थे। इस संबंध में 17.5 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का ऊंची पेंशन देने का निर्णय सभी कर्मचारियों के लिए नहीं माना गया था। एक सितंबर 2014 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना में शामिल नहीं किए गए। हालांकि कर्मचारी इस बात के लिए सहमत नहीं हैं।

वस्तुतः वर्तमान में ईपीएस, 95 स्कीम के अंतर्गत 15 हजार से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन एक हजार रुपये रखी गई थी, लेकिन 2014 से 2024 के बीच जीवन लागत में भी काफी वृद्धि हुई है, इसलिए कर्मचारियों की अधिक पेंशन की मांग न्यायोचित दिखाई देती है। लेकिन यह समझना होगा कि वर्तमान में जब सरकार एक हजार रुपये की दर से पेंशन प्रदान करती है तो उसका आंशिक भार केंद्र सरकार पर पड़ता है। इसलिए यदि पेंशन की राशि बढ़ाई जाती है तो भी केंद्रीय बजट पर इसका भार उसी अनुपात में बढ़ेगा। ऐसे में यह सामान्य निर्णय नहीं है, इसके लिए सरकार को आकलन करना पड़ेगा। इस संबंध में सरकार द्वारा एक एक्च्युरियल फर्म की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है जो पेंशन स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने के प्रस्तावित फैसले के आर्थिक पक्ष का आकलन करेगा। ऐसे संकेत हैं कि ईपीएफओ और पूर्व एक्च्युरियल के वित्तीय प्रभाव के आकलन में काफी अंतर है। इसलिए ऐसा लगता है कि एक्च्युरियल द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन का सरकार के प्रस्तावित निर्णय पर अनुकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस संबंध में कर्मचारियों को पेंशन में वृद्धि हेतु कुछ समय तो लग सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि पेंशन राशि के संबंध में सरकार कर्मचारियों के पक्ष में सोच रही है और यह बात सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों से भी स्पष्ट हो रह है। परंतु संभवतः कर्मचारियों को इसके लिए कुछ प्रतीक्षा करनी होगी।

## कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का मसला

पेंशन से संबंधित मामले में इस विषय का एक दूसरा आयाम भी है। हाल में कुछ इस तरह की चर्चाएं हुई हैं कि जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होने के कारण कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जाए। वैसे सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जाती है तो युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर घट सकते हैं, इसलिए किसी भी सरकार के लिए यह कदम लोकप्रिय नहीं होगा। लेकिन यह भी जरूरी है कि कार्यक्षम लोगों को उनके लिए उपयुक्त रोजगार की व्यवस्था हो। उम्र बढ़ने को विकास और योगदान के समय के रूप में भी देखना होगा। कौशल को अद्यतन करने, नए कौशल हासिल करने और विकसित कार्यबल के साथ जुड़े रहने के लिए निरंतर सीखने के अवसरों का समर्थन करना होगा। अधिक आयु वाले लोगों को नई प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, ताकि वे नई प्रौद्योगिकी के साथ अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे सकें। वैसे हम उनकी ताकत और अनुभव का लाभ उठा सकते हैं। ज्ञान साझा करने और मार्गदर्शन के लिए अनुभवी लोगों को युवा सहकर्मियों के साथ जोड़ कर परामर्श और ज्ञान हस्तांतरण का कार्य किया जा सकता है। उनका उपयोग रणनीतिक योजना और समस्या-समाधान के लिए किया जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक नए व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। उसके लिए संसाधन और सहायता प्रदान करके वरिष्ठ उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी होगी, जहां उनके कौशल की मांग अधिक है। उदाहरण के लिए, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक सेवाएं, वृद्ध वयस्क देखभाल, भावनात्मक समर्थन और सामुदायिक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके अतिरिक्त युवा पीढ़ी के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और सलाहकारों के रूप में उनके अनुभव का उपयोग का उपयोग हो सकता है। उनके कौशल और ज्ञान कला, शिल्प, कहानी कहने और ऐतिहासिक संरक्षण को समृद्ध करने में भी उनकी भूमिका हो सकती है। (डा. अश्विनी महाजन)

खरी-खरी

## पलटीश बाबू की जय

डा. सुरेश कुमार मिश्रा

जब कोई गेंद किसी दीवार से टकराती है, तो टकराव में दोनों सतहों पर परमाणुओं और अणुओं की परस्पर क्रिया शामिल होती है। ये परमाणु और अणु विद्युत चुंबकीय बलों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जो उनकी स्थिति, अभिविन्यास और बंधन ऊर्जा निर्धारित करते हैं। इन विद्युत चुंबकीय अंतःक्रियाओं की ताकत और प्रकृति परमाणुओं और अणुओं के प्रकार, साथ ही उनके आवेशों, द्विध्रुवीय क्षणों और अन्य गुणों पर निर्भर करती है।

टक्कर के दौरान गेंद और दीवार के परमाणुओं एवं अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क होने वाली विकृति की प्रकृति और सीमा निर्धारित करते हैं। जब गेंद दीवार से टकराती है, तो गेंद की सतह और दीवार की सतह संपर्क में आती है और दोनों सतहों में परमाणुओं व अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय बल उनके परस्पर क्रिया और विरूपण का कारण बनते हैं। विरूपण में शामिल बलों की दिशा और परिमाण के आधार पर संपीड़न, झुकने, कतरनी या अन्य प्रकार के तनाव शामिल हो सकते हैं।

टकराव के दौरान संग्रहीत और जारी होने वाली ऊर्जा की मात्रा विरूपण की प्रकृति और सीमा पर निर्भर करती है, जो बदले में गेंद व दीवार के अणुओं के बीच विद्युत चुंबकीय संपर्क पर निर्भर करती है। यदि विरूपण लोचदार है तो गेंद अपनी कुछ मूल गतिज ऊर्जा के साथ वापस उछलती है। यदि विरूपण बेलोचदार है, तो टक्कर के दौरान गेंद से दीवार पर स्थानांतरित की गई कुछ ऊर्जा गर्मी या अन्य रूपों के रूप में नष्ट हो जाएगी। यहां ऊर्जा का मतलब यह है कि पलटाव कम ऊर्जावान होगा, और गेंद अपनी कुछ मूल गतिज ऊर्जा खो देगी।

वैसे मुझे पता है कि आपको ऊपर बताई गई बातें समझ में नहीं आई हैं। इसलिए इसे आसान उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यहां गेंद को पलटीश कुमार, दीवार को चुनाव, परमाणु और अणुओं को सरकारी जांच एजेंसियां, चुंबकीय बल को स्वार्थ, दिशा और परिमाण को सीटों की संख्या, मूल स्थिति को वापसी-पलटने के गुण और फेंकने-पकड़ने वाले को कुर्सी का भूखा समझ लें, आपको गेंद वापसी एवं पलटने का माजरा समझ में आ जाएगा।

## पोस्ट

अपने खिलाफ बातें मैं अक्सर खामोशी से सुनता हूं। जवाब देने का हक मैंने वक्त को दे रखा है।
नवजोत सिंह सिद्धू@sherryontopp

जयंत चौधरी लोकसभा में फिलहाल जीरो सीट के साथ राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। राजनीति में सबसे बड़ा खतरा होता है अप्रासंगिक होने का। यही खतरा उन्हें भाजपा की ओर लेकर जा रहा है।
अरविंद चोटिया@arvindchotia

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार को समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के लिए इतिहास में याद रखा जाएगा। साथ ही उन मंत्रियों, पक्ष-विपक्ष के विधायकों को भी याद रखा जाएगा, जिन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के दौरान सदन में वक्तव्य दिए!
अजीत सिंह राठी@AjitSinghRathi

कर्नाटक सरकार टैक्स बंटवारे की आड़ में केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है। अलग दक्षिण भारतीय देश के लिए कोई भी आंदोलन इसी तर्ज पर खड़ा होगा। भाजपा उत्तर में जितनी मजबूत होगी, दक्षिण में यह मुहिम भी उतनी परवान चढ़ेगी। इससे भ्रष्ट दक्षिण भारतीय नेताओं को ईडी के साथ सौदेबाजी करने में भी सहायता मिलेगी।
मनु जोसेफ@manujosephsan

## जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या संप्रग शासन के समय की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र लाया जाना चाहिए?**

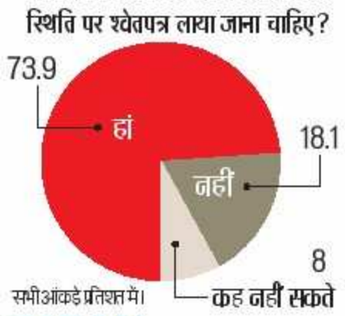


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या लोकसभा चुनाव में भाजपा अपने बलबूते 370 सीटें हासिल कर सकती है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

## जनपथ

सोचें पुत्र अजीत के जाऊं किसके साथ,
बीजेपी या फिर सपा थामूं किसका हाथ।
थामूं किसका हाथ एक पाएगा सत्ता,
दूजा लटका आज कि जैसे सूखा पत्ता।
उन्हें देख अखिलेश बाल अब अपना नोचें,
दिखता फ्यूचर डार्क यही चिंता में सोचें।
– ओमप्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

# जांच आयोग की रिपोर्ट, लीपापोती का जरिया

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में पिछले दस वर्षों में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में सैकड़ों लोगों की जान गई, लेकिन किसी भी घटना में दोषियों को सजा न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने ऐसी हर घटना के लिए आयोग का गठन किया, आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंपी, लेकिन वर्षों से वे जांच प्रतिवेदन केवल धूल खा रहे हैं। किसी भी न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर नहीं रखा गया। यदि हम मान लें कि विधानसभा में आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होती तो शायद चर्चा से कोई ऐसा रास्ता निकलता कि आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था। मंगलवार के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में भयावह विस्फोट हुआ तो फिर सवाल उठ खड़ा हुआ है कि इस लापरवाही की सजा दोषियों को मिलेगी या नहीं। हरदा में भी अब तक 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की मध्य प्रदेश में यह पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी झाबुआ जिले के पेटलावद, बालाघाट और दमोह में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है, लेकिन शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं पड़ा। हालात यह हैं कि वर्ष 2015 में पेटलावद विस्फोट की जांच पूरी कर रिपोर्ट गृह विभाग को छह अप्रैल 2016 को ही सौंप दी गई, लेकिन अब तक न तो कोई कार्रवाई की गई है और न ही इस तरह के घटनाक्रम को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए। इसका ही परिणाम है कि मंगलवार को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट ने कई लोगों की जान ले ली। बालाघाट जिला मुख्यालय से सात किमी दूर ग्राम खैरी में स्थित एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सात जून 2017 को तेज धमाका हुआ था। इस विस्फोट में 26 लोगों की मौत हुई थी। धमाका इतना तेज था कि बाहर खड़ा फायर ब्रिगेड का वाहन भी जल गया था। धमाकों की आवाज पांच किमी दूर तक सुनाई दी थी। शवों के चीथड़े दो किमी दूर तक गिरे थे। पटाखा फैक्ट्री चार साल से बिना अनुमति के संचालित की जा रही थी। इससे पहले 2015 में किरनापुर तहसील में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी, एक दर्जन लोग घायल हुए थे। वहीं दमोह में भी अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाके से सात लोगों की जान जा चुकी है। दमोह के कोतवाली थानांतर्गत नया बाजार में बड़े पुल के पास अवैध पटाखा फैक्ट्री में 30 अक्टूबर 2023 को विस्फोट हुआ था। इस हादसे में फैक्ट्री मालिक अभय उर्फ छुट्टन गुप्ता सहित सात लोगों की मौत हो गई थी। मजिस्ट्रियल जांच के बाद रिपोर्ट तो आई, लेकिन जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हरदा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद का मंजर। नईदुनिया

12 सितंबर 2015 की सुबह झाबुआ जिले के पेटलावद की एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 79 लोगों की मौत और 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मकान में अवैध रूप से रखी जिलेटिन राड और डेटोनेटर में विस्फोट के चलते चारों ओर लाशों का ढेर लग गया था। इसमें मुख्य आरोपित पेटलावद निवासी राजेंद्र कांसवा को बनाया गया था, जिसकी इस विस्फोट में मौत बताई गई थी। पेटलावद विस्फोट घटना की जांच के लिए जबलपुर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर्येंद्र कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया था। सक्सेना द्वारा जांच पूरी कर जांच प्रतिवेदन छह अप्रैल 2016 को गृह विभाग को भेजा गया था, तब से अब तक इस पर गृह विभाग में कार्यवाही ही प्रचलन में है। सक्सेना ने इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए सुझावों भी दिए थे, लेकिन उन्हें अमल में नहीं लाया गया। अदालत से सारे आरोपित भी बरी हो गए और सरकारी अधिकारियों को सरकार ने बचा लिया। ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए।

वस्तुतः इन दिनों राजनेताओं की निर्भरता एसपी-कलेक्टर और बड़े अधिकारियों पर बढ़ गई है। उनकी मनमर्जी से ही अधिकारियों को मनमाफिक पोस्टिंग मिलती है। यही कारण है कि कुर्सी बचाए रखने के लिए वे लोकसेवक के बजाय राजनेताओं के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कभी कोई कलेक्टर पटवारी का रिकार्ड चेक नहीं करता है। किसी भी एसपी का रात्रि में गश्त देखने शहर में राउंड लगाना हो, थाने का औचक निरीक्षण करना हो, यह उनकी प्राथमिकता में नहीं है। प्रशासनिक मुखिया के पद राजनीतिक हो गए हैं, वे सरकार की हां में हां ही करते रहते हैं। मुख्य सचिव हो या पुलिस महानिदेशक, कोई राजधानी के बाहर नहीं निकलना चाहता है। यही वजह है कि हम जिस सुशासन की बात करते हैं, वह मात्र सपना जैसा ही है। सरकार को चाहिए कि कानून का राज स्थापित करने के लिए अधिकारियों में भी जिम्मेदारी का भाव पैदा करे, लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करे, ऐसे हादसों को रोका जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

# प्राथमिकताएं और दाने भुनाने का आग्रह

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

कुपित थे इंद्रदेव लंबे समय से। हिमाचल में कई बार ऐसा प्रतीत हुआ कि यलो अलर्ट भी ठगा गया। अंततः द्रवित हुए बादल। धरती को पानी मिला, पहाड़ों ने चांदी का मुकुट पहन लिया। प्यासी धरती के लिए दो बूंदें भी अमूल्य होती हैं।

इसी बीच विधायक प्राथमिकता बैठक का दो दिवसीय वार्षिक कार्य भी संपन्न हुआ। इसमें विधायक अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री को बताते हैं। प्राथमिकताओं को आवश्यक आवश्यकताएं भी कहा जा सकता है। वर्षों से विधायक प्राथमिकता बैठकें हो रही हैं और आश्चर्य यह होता है कि अब तक विधायक सड़कों, जल निकासी योजनाओं, पेयजल योजनाओं, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी के विषयों में फंसे हैं, जबकि प्रत्येक सरकार यह दावा करती है कि जितना विकास उसके कार्यकाल में हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। प्राथमिकता बैठकें ही दशकों से अपूर्ण कार्यों की शरणस्थली नहीं हैं, अपितु प्रशासन जनता के द्वार, जनसंवाद, सरकार आपके द्वार, जनमंच आदि में भी ऐसे कई दृश्य सामने आते हैं जो सत्यापित करते हैं कि कोई अपूर्ण मांग पूरी जिजीविषा के साथ अब भी सांसें ले रही है और फिर उसी मंच तक आई है, जहां से उसे आश्वासन मिल चुके हैं। इस सबमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मंत्री जी की परंपरागत डांट का रूट भी निश्चित होता है... मंत्री से जिलाधीश, जिलाधीश से एसडीएम और एसडीएम से आगे वहां तक, जहां तक कोई तो है सुनने वाला। ऊना के सलांगड़ी में सरकार जब जनता के द्वार पहुंची तो वहां ओडिशा में अपने बलिदानी पुत्र का स्मारक बनाने की प्रार्थना लेकर एक वृद्ध छोटे लाल खड़े थे। 11 वर्ष पूर्व जब वाम उग्रवाद से भिड़ते हुए सुरेंद्र कुमार ने आत्मोत्सर्ग किया था, घोषणा की थी वीरभद्र सिंह सरकार ने कि स्मारक बनेगा। बलिदानी के पिता कहते हैं, उन्होंने कोई मांग नहीं की थी। सरकार ने स्वयं घोषणा की थी। उन्हें ओडिशा सरकार ने बुलाया है कि सम्मान करना है। यहां कई बार प्रशासन जनता के द्वार पहुंचा, कई जनमंच हुए, पर बलिदानी के पिता की आंखें अब तक सूनी दहलीज बनी हुई हैं।

कुल्लू के करशाला में हिमपात में फंसी हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस। जागरण आर्काइव

इसलिए जब कोई विधायक अपनी प्राथमिकता बताता है तो उनके माध्यम से वस्तुतः एक दर्पण भी उपलब्ध करवाता है जिसमें उसका चेहरा सामने आता है, दृष्टि दिखती है। धरातल से जुड़ाव दिखता है। इस संदर्भ में नया यह हुआ है कि चिट्टे के आतंक की बात विधायक प्राथमिकता बैठक तक आई। सबने कहा कि यह नगरों तक ही नहीं, घरों तक आ गया है। हिमाचल प्रदेश को चिट्टे से खतरा है, यह स्वयं कानून बनाने वाले कह रहे हैं तो आशा की जानी चाहिए कि कानून और सख्त होंगे। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री तो कई बार कह चुके हैं कि हिमाचल की जेलों में जगह नहीं बची है, चिट्टे से जुड़े इतने लोग अंदर हैं। यहां विषय फिर मांग और आपूर्ति के कोण पर नहीं ठहर पाता। नशे की आपूर्ति को रोकने के लिए तो कई एजेंसियां सक्रिय हैं, किंतु मांग कम हो, उसकी तरफ ध्यान बहुत कम है। स्तर सरकारी हो या गैर सरकारी। इस सबके बावजूद सकारात्मक पक्ष यह है कि विधायकों को यह विषय प्राथमिकता वाला अनुभव हुआ।

एक विधायक ने नए जिले बनाने का आग्रह उठाया है। संसार एक वैश्विक गांव बन रहा है, राष्ट्राध्यक्ष तक इंटरनेट के माध्यम से आभासी बैठकें कर रहे हैं और यहां परामर्श यह है कि कांगड़ा के चार टुकड़े किए जाएं। जो प्रदेश डा. यशवंत सिंह परमार के समय से केंद्र की सहायता पर निर्भर है, जहां वित्तीय संकट इतना है कि गारंटियां तो दूर, रोजमर्रा का काम कठिन हो रहा है, वहां नए जिलों की मांग वही दाने भुनाने के आग्रह जैसा है जो जेब में हैं ही नहीं। कोई कह सकता है कि यह कांगड़ा का कद बराबर करने की युक्ति है, इसलिए कांगड़ा के टुकड़े न किए जाएं। कोई यह भी कह सकता है कि चूंकि छोटी इकाई को प्रशासित करना सरल होता है, इसलिए जिले बनाए जाएं। सच यह है कि कांगड़ा ने बड़ा होकर, 68 विधानसभा सीटों में से 15 सीटों वाला जिला होकर क्या पा लिया जो छोटे जिले नहीं पा सके? प्राथमिकताओं में नए जिलों का गठन आवश्यक आवश्यकता प्रतीत नहीं होता। राहत देनी है तो चंबा के सिहुंता जैसे क्षेत्रों को दें जो चंबा से दूर हैं और कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के पास हैं। गठन के बजाय पुनर्गठन की बात होती तो व्यावहारिक होती।

अब मौसम बदल जाएगा, किंतु एक प्राथमिकता यह भी होनी चाहिए कि एक अच्छे हिमपात के बाद पूर्व आपदा प्रबंधन पर जोर दिया जाए। बर्फ के गोलों से खेलना एक बात है और उन्हीं गोलों में फंसकर किसी पर्यटक को 14 किलोमीटर के लिए सात हजार रुपये देने पड़ें तो इससे पर्यटन का प्रचार नहीं हो सकता। आशा है अगली बार प्राथमिकताएं और वास्तविक होंगी।

********

शिक्षा सबसे मजबूत औजार है, जिसका उपयोग आप इस दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। - नेलसन मंडेला

**लोकसभा में पारित होने के बाद लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 का कानून बनना लगभग तय है। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून बन जाने पर यह राज्य सरकारों के लिए भी एक मॉडल का काम करेगा और वे इसे अपनाने में तत्परता दिखाएंगी।**

## परीक्षार्थियों के हित में

लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक, 2024 का लोकसभा में पारित होना सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पिछले कई वर्षों से देखी जा रही अनियमितताओं को दूर करने के लिहाज से एक बहुप्रतीक्षित एवं परीक्षाओं पर युवाओं के भरोसे को बहाल करने वाला कदम है। यह इसलिए भी जरूरी था कि केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के माध्यम से सरकारी परीक्षाओं के संचालन में शामिल विभिन्न संस्थाओं द्वारा अपनाए गए अनुचित तरीकों या किए गए अपराधों से निपटने के लिए अब तक कोई ठोस कानून नहीं है। विधेयक में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और अनियमितताएं पाए जाने पर अधिकतम दस साल की सजा और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना शामिल है। खास बात यह है कि विधेयक में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि परीक्षार्थियों को कोई नुकसान न हो, अलबत्ता इसमें संगठित अपराधों और नौकरी दिलाने का दावा करने वाले गिरोहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान किया गया है। अफसोस की बात है कि वैश्वीकरण को अपनाए इतना वक्त गुजर जाने और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के आह्वान के बाद भी देश के युवाओं में सरकारी नौकरी का आकर्षण कम नहीं हुआ, बल्कि महामारी के अनुभव के बाद बढ़ा ही है। नौकरी के स्थायित्व, नियमित सैलरी और पेंशन जैसी सुविधाओं के लालच में युवा एक अदद सरकारी नौकरी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, तो दूसरी तरफ सरकारी पदों की मांग और पूर्ति के बीच बढ़ते अंतराल का फायदा उठाने के लिए कई गिरोह पैदा हो जाते हैं, जिनके जाल में ये युवा फंसते हैं। इस मुद्दे की गंभीरता का पता इससे भी चलता है कि यह राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के हालिया विधानसभा चुनावों में भी काफी हावी रहा था। एक शोध के अनुसार, हालिया वर्षों में 16 राज्यों में पेपर लीक के कम से कम 48 मामले सामने आए, जिससे सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया बाधित हुई। यह सबसे ज्यादा कष्टकारी उन परीक्षार्थियों के लिए होता है, जो अपना पैसा, समय और ऊर्जा पढ़ाई में लगा रहे होते हैं। हालांकि कानून बनने पर यह केवल अखिल भारतीय स्तर की केंद्रीय परीक्षाओं पर लागू होगा, जिनमें धांधली के मामले अपेक्षया कम ही सामने आते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून बन जाने पर यह राज्य सरकारों के लिए एक मॉडल का काम करेगा और वे भी इसे अपनाने में तत्परता दिखाएंगी।

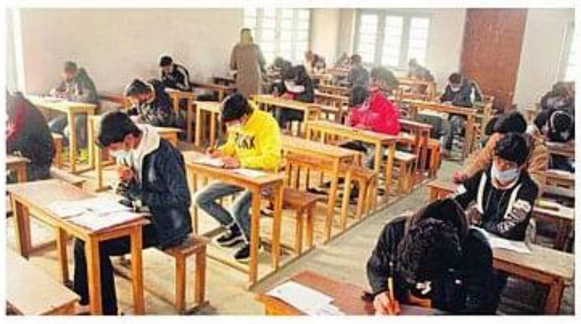

## आखिर त्रूदो को परेशानी क्या है

**मनमौजी त्रूदो की खुफिया सेवाओं का भारत पर कनाडा के लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने का आरोप हैरान नहीं करता, क्योंकि मनगढ़ंत और बेबुनियाद आरोप लगाने की इसी आदत के चलते उन्होंने अमेरिका, चीन और विश्व की कई बड़ी शक्तियों के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं।**

दीपक वोहरा
पूर्व राजनयिक

रामायण में भगवान राम के भरोसेमंद सखा हनुमान जी को अपनी महान शक्ति को भूलने का श्राप मिला है। भालुओं के राजा जामवंत उन्हें याद दिलाते हैं और बाकी की कहानी सब जानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि शताब्दी के तीसरे दशक में भारत अच्छाई की शक्ति के रूप में उभर रहा है और इसकी प्रतिष्ठा आसमान छू रही है। न केवल इसकी अर्थव्यवस्था फल-फूल रही है, बल्कि इसकी वैज्ञानिक क्षमता और नए डिजिटल भविष्य की दिशा में इसका नेतृत्व भी स्पष्ट है। विकासशील दुनिया भारत के नेतृत्व को स्वीकार करती है और उसका अनुकरण भी करना चाहती है। शक्तिहीन होती पाश्चात्य शक्तियां इससे भयभीत हैं। भारत की नीति हमेशा स्वतंत्र एवं स्वायत्त रही है। जाहिर है, खुद को ब्रह्मांड का मालिक मानने वाले देश हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चूंकि अब कोई जामवंत नहीं है, नशे के आदी विदूषकों के राजा (त्रूदो) ने, जो वैश्विक मंच पर जगह बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, अपनी खुफिया सेवाओं को भारत के खिलाफ हास्यास्पद आरोप लगाने का फरमान जारी किया।

सबसे पहले उसने यह बेतुका आरोप लगाया कि भारत ने उसके वफादार व्यक्ति की हत्या कर दी है। उसने दुनिया भर को इसके बारे में बताया। लेकिन जब उसका ज्यादा असर नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी खुफिया सेवाओं को भारत पर कनाडा के चुनाव में हस्तक्षेप करने और उसकी लोकतांत्रिक संस्थानों को नष्ट करने की योजना बनाने के आरोप लगाने का आदेश दिया। कोई पूछ सकता है कि इसका सबूत क्या है?

खैर, कनाडा में भारतीय प्रवासियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो भारत-हितैषी उम्मीदवारों को वोट दे सकता है। वे भारतीय मूल के कनाडाई नागरिक हैं और कनाडा के कानून के तहत ही उन्हें कनाडाई नागरिकता मिली है। लेकिन त्रूदो विलाप करते हुए कहते हैं, 'हम कानून के राज में विश्वास करते हैं, लेकिन गैर-श्वेत कनाडाई लोगों ने अब तक कनाडाई झंडे को नहीं अपनाया है।' लेकिन त्रूदो ने क्या कभी इसकी वजह सोची है? कनाडा भारतीय मूल के प्रवासियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हालांकि विदूषक त्रूदो शेखी बघारते हैं कि वे लोकतांत्रिक और सबको समान अवसर देने वाले लोग हैं, पर वास्तविकता में वे नस्लवादी हैं। कनाडा एक छोटी शक्ति वाला बड़ा देश है, और उसे सम्मान व प्रशंसा पाने की प्रबल इच्छा है। इसलिए वह अंतरराष्ट्रीय मामलों में अपनी नाक घुसेड़ता है, और विवेकशील लोग उसकी आंखों में खटकने लगते हैं। तमिल विद्रोह के दौरान कनाडा ने श्रीलंका पर मानवाधिकारों के उल्लंघनों के बारे में खूब शोर मचाया, जवाब में, श्रीलंका ने भी लिट्टे आतंकवादियों को शरण देने का उन पर आरोप लगाया।

श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाहगाह मिल गई है और वह भारत के खिलाफ त्रूदो की टिप्पणियों से 'हैरान नहीं' हैं, क्योंकि 'अपमानजनक और बेबुनियाद आरोप' लगाना उनकी आदत है। विदूषक त्रूदो पाकिस्तान (खासकर बलूचिस्तान और खैबर क्षेत्र) में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के बारे में चुप हैं, क्योंकि प्रमुख कनाडाई कंपनियां वहां खनन में शामिल हैं। 1980 के दशक में एक कनाडाई खनन कंपनी बंद हो गई, जब यह साबित हुआ कि इंडोनेशिया में सोने के विशाल भंडार की खोज के बारे में उसने बेशर्मी से झूठ बोला था। अपने सहयोगियों के समर्थन के बिना कनाडा की सेना भूटान जितनी ही मजबूत है। उसने यूक्रेन से जिन हथियारों का वादा किया, वह अब तक बन भी नहीं पाए हैं।

आधुनिक इतिहास में पहली बार एक संपन्न, बड़े और कम आबादी वाले पश्चिमी देश के प्रधानमंत्री ने सबसे ताकतवर विकासशील देश से अपने रिश्ते को यह आरोप लगाकर खत्म कर दिया कि उसने, उसके सबसे प्रिय आतंकवादी, जो भारतीय मूल का कनाडाई नागरिक था, की कनाडा की धरती पर हत्या कर दी। उन्होंने इस घटना को वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लेकिन भारत ऐसा क्यों करना चाहेगा, उसे इससे क्या हासिल होगा? त्रूदो इसका जवाब नहीं देंगे कि क्या वह व्यक्ति भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेरर-फंडिंग में शामिल था, और क्या उसने कनाडा में असॉल्ट राइफल लहराते हुए अपने वीडियो पोस्ट किए थे? इसलिए भारत के विदेश मंत्री ने नवंबर, 2023 में लंदन में कहा कि कनाडा चाहता है कि हम उसकी धरती पर एक कनाडाई की हत्या की जांच में 'सहयोग' करें, लेकिन वह हमें यह भी बताने में असमर्थ है कि वह किस तरह के सहयोग की अपेक्षा करता है।

कनाडा की अहंकारी विदेश मंत्री, जिसने भारत को धमकी दी थी कि वह आतंकी की हत्या में भारत की संलिप्तता के बारे में अपने सहयोगियों से बात करेंगी, अब भारत की प्रतिक्रिया से हिल गई हैं और भारत से निजी तौर पर इस मसले पर बात करना चाहती हैं। तो अब आगे क्या होगा? मैं पिछले पचास वर्षों से कूटनीति में हूं। राष्ट्रों के बीच भरोसा कायम करने में दशकों लग जाते हैं। लेकिन रिश्ते खराब करने के लिए कुछ गलत बयान ही काफी होते हैं।

भारत एक परिपक्व और शक्तिशाली लोकतंत्र है। विदेश नीति को लेकर विभिन्न दलों में यहां आम सहमति है। त्रूदो ने कई प्रमुख शक्तियों के साथ अपने रिश्ते खराब किए हैं। उन्होंने पुतिन को बेवजह गालियां दीं, चीनी नेता ने कनाडाई मीडिया को उनकी गोपनीय चर्चाओं के बारे में जानकारी देने के लिए 2022 में बाली में सार्वजनिक रूप से अपमानित किया और जब उन्होंने जी-7 शिखर सम्मेलन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मजाक उड़ाया, तो अमेरिका भी नाराज हो गया था।

जब एक अमेरिकी-कनाडाई आतंकवादी ने एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी, तो त्रूदो ने कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो अगर कुछ अप्रिय हुआ, तो क्या इसे त्रूदो के कानून के मुताबिक कार्रवाई की स्वतंत्रता माना जाए? भारत-कनाडा संबंधों को सुधारने में दशकों लगेंगे। कनाडा हमारी विदेश नीति के रडार पर बहुत नीचे है। त्रूदो भारत पर रिश्ते तोड़ने का भी आरोप लगा सकते हैं, तो हम इसमें आखिर क्या कर सकते हैं! ओटावा एक समय वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के लिए अच्छी पोस्टिंग थी। लेकिन फिलहाल वह भारतीय कूटनीतिज्ञों के लिए अच्छी जगह नहीं रह गई है। उम्मीद है, इस बार मोदी फिर चुनाव जीतकर सत्ता में लौटेंगे। यदि तब तक त्रूदो का नशा उतर जाए, तो वह उन्हें बधाई दे सकते हैं। हो सकता है, इससे रिश्ते में थोड़ी गर्मजोशी आए।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

श्रीराम शर्मा

**जीवन की सफलता और समृद्धि आत्मभाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य आत्मा का अनुभव करने लगता है, तो उसकी आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है, जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है।**

### ज्ञान ही जीवन का प्रकाश स्तंभ

*जिज्ञासा भाव के कारण ही मनुष्य अब तक इतना ज्ञान और साधन संपन्न बना है। सचमुच ज्ञान ही जीवन का प्रकाश स्तंभ है। जानकारी की अनेक वस्तुओं में से 'अपने आप की जानकारी' सर्वोपरि है। हम बाहरी अनेक बातों को जानते हैं या जानने का प्रयत्न करते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि हम स्वयं क्या हैं? स्वयं का ज्ञान प्राप्त किए बिना जीवन क्रम अनिश्चित और कंटकाकीर्ण हो जाता है। सच्ची सुख-शांति का राजमार्ग एक ही है और वह है 'आत्मज्ञान'। शरीर भाव में मनुष्य इतना तल्लीन हो गया है कि वह खुद को शरीर ही समझने लगा है। वर्ण, वंश, व्यवसाय या पद शरीर का होता है। शरीर मनुष्य का एक परिधान है, औजार है, परंतु भ्रम और अज्ञान के कारण वह इस शरीर के स्वार्थ तथा अपने स्वार्थ को एक कर लेता है। इसी गड़बड़ी में जीवन अनेक अशांतियों, चिंताओं और व्यथाओं का घर बन जाता है।*

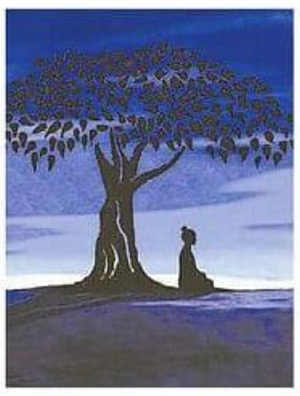

*यह ठीक है कि मनुष्य शरीर में रहता है, पर यह भी ठीक है कि वह मात्र शरीर नहीं है। जब प्राण निकल जाते हैं, तो शरीर ज्यों का त्यों रहता है। उसे थोड़ी देर रखा रहने दिया जाए, तो लाश सड़ने लगती है, दुर्गंध उत्पन्न होने लगती है। देह वही है, पर प्राण निकलते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर में निवास तो करता है, पर वस्तुतः वह शरीर से भिन्न है। इस भिन्न सत्ता को आत्मा कहते हैं। वास्तव में यही मनुष्य है। शरीर आत्मा का मंदिर है। उसकी स्वस्थता, स्वच्छता और सुविधा के लिए कार्य करना उचित एवं आवश्यक है, परंतु केवल शरीर के ही बारे में सोचना अहितकर है। उसे ही अपना स्वरूप मान लेना और अपने वास्तविक स्वरूप को भुला देना ठीक नहीं है। यह भूल-भुलैया का खेल जीवन को बड़ा कर्कश और नीरस बना देता है।*

*आत्मा शरीर से पृथक है। शरीर और आत्मा के स्वार्थ भी पृथक हैं। शरीर के स्वार्थों का प्रतिनिधित्व इंद्रियां करती हैं। दस इंद्रियां और ग्यारहवां मन यह सदा ही शारीरिक दृष्टिकोण से सोचते और कार्य करते हैं। स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया वस्त्र, सुंदर-सुंदर मनोहर दृश्य, मधुर श्रवण, रूपवती स्त्री आदि नाना प्रकार के भोग-विलास इंद्रिय की आकांक्षा हैं। इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने में प्रायः सारा जीवन लगता है। जब ये इच्छाएं अधिक उग्र हो जाती हैं, तो मनुष्य किसी भी प्रकार से उनकी तृप्ति करने की ठान लेता है और उचित-अनुचित का विचार छोड़कर जैसे भी बने, स्वार्थ साधने की नीति पर उतर आता है। यही समस्त पापों का मूल है। इसलिए जीवन की वास्तविक सफलता और समृद्धि आत्मभाव में जागृत रहने में है। जब मनुष्य स्वयं आत्मा का अनुभव करने लगता है, तो उसकी इच्छा, आकांक्षा और अभिरुचि उन्हीं कामों की ओर मुड़ जाती है, जिनसे आध्यात्मिक सुख मिलता है। जब मनुष्य परोपकार, परमार्थ, सेवा, सहायता, दान, उदारता, त्याग, तप से भरे हुए पुण्य कर्म करता है, तो हृदय को बड़ा ही संतोष, आनंद एवं उल्लास महसूस होता है। और आत्मा की आवाज सुनने वाले और उस पर चलने वाले सदा पुण्यकर्मी होते हैं।*

### सद्कर्मों से आत्मिक सुख...

सूत्र

*आत्मा को सुख सद्कर्मों से मिलता है। लोक और परलोक में आत्मिक सुख-शांति सद्कर्मों के ऊपर ही निर्भर है। आत्मज्ञान रखने वाले व्यक्ति सदा आनंदमयी स्थिति का रसास्वादन करते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक एवं पुण्य प्रतिष्ठा से भरा पूरा बनाने का राजमार्ग यह है कि हम स्वयं को शरीर भाव से ऊंचा उठाएं और आत्मभाव में जागृत हों।*

## दूसरा पहलू

सिरदर्द का एक कारण माइग्रेन है। 15 से 49 साल की महिलाओं में सिरदर्द का यह मुख्य कारण है।

### औरतों को ही ज्यादा सिरदर्द क्यों होता है?

**महिलाओं** को पुरुषों की तुलना में ज्यादा सिरदर्द होता है। हाल ही में अमेरिका में हुए एक राष्ट्रव्यापी सर्वे में जब औरतों से पूछा गया कि पिछले तीन महीनों में कभी उन्हें मामूली सिरदर्द भी हुआ या नहीं, तो पुरुषों की तुलना में तीन गुना महिलाओं ने कहा कि उस दौरान उन्हें मामूली नहीं, बहुत तेज सिरदर्द होता था। विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में सिरदर्द ज्यादा होने का एक कारण हार्मोन से संबंधित है। लेकिन तमाम तरह के सिरदर्द का कारण यह नहीं है। बल्कि भिन्न कारण से कुछ सिरदर्द से पुरुष ही ज्यादा परेशान रहते हैं।

मेलिंडा वेन्नर मोनियर

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को माइग्रेन से होनेवाला सिरदर्द दो से तीन गुना ज्यादा होता है। और इस सिरदर्द से तीस साल और उससे ऊपर की महिलाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं।

सिरदर्द का एक कारण माइग्रेन है। 15 से 49 साल की महिलाओं में सिरदर्द का यह मुख्य कारण है। माइग्रेन से होनेवाला सिरदर्द सामान्य भी होता है और भीषण भी। यह चार घंटे से 72 घंटे तक रह सकता है।

ब्रिटेन स्थित बार्ट्स ऐंड लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन ऐंड डेंटिस्ट्री में सिरदर्द की विशेषज्ञ डॉ. एनी मैक्ग्रोवर कहती हैं कि किशोरावस्था से पहले लड़के और लड़कियां माइग्रेन से होनेवाले सिरदर्द का समान रूप से अनुभव करते हैं। लेकिन किशोरावस्था में पहुंचने के बाद माइग्रेन से होनेवाला सिरदर्द किशोरियों और महिलाओं को ही ज्यादा होता है। न्यूयॉर्क सिटी स्थित अल्बर्ट आइंस्टीन कॉलेज ऑफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. जेलेना पावलोविक कहती हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को माइग्रेन से होनेवाला सिरदर्द दो से तीन गुना ज्यादा होता है। और इस सिरदर्द से तीस साल और उससे ऊपर की महिलाएं ज्यादा पीड़ित होती हैं।

इसका कारण संभवतः यह है कि इस उम्र की महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक तनाव ज्यादा झेलना पड़ता है। इनमें नींद संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं।

इसका कारण संभवतः यह है कि काम के अलावा इस उम्र की महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक तनाव ज्यादा झेलना पड़ता है। पुरुषों की तुलना में ऐसी महिलाओं में नींद संबंधी समस्याएं ज्यादा होती हैं। फिर थकावट के कारण भी सिरदर्द ज्यादा होता है। वैज्ञानिक अध्ययन बताता है कि माइग्रेन से होनेवाले सिरदर्द में एस्ट्रोजन बड़ी भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, अनेक महिलाएं माहवारी से पहले या माहवारी के दौरान माइग्रेन से होनेवाले सिरदर्द का अनुभव करती हैं। माइग्रेन के अलावा तनाव से होनेवाला सिरदर्द भी महिलाओं को ज्यादा होता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि ज्यादा धूम्रपान करने वाले और अधिक शराब पीनेवाले पुरुष भी भीषण सिरदर्द का अनुभव करते हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब तमाम तरह के सिरदर्द का उपचार है।

©The New York Times 2024

## आंकड़े

### देश में विदेशी पर्यटक

हमारे देश में सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक दुनिया के सबसे विकसित माने जाने वाले देश अमेरिका से आते हैं, उसके बाद पड़ोसी बांग्लादेश से।

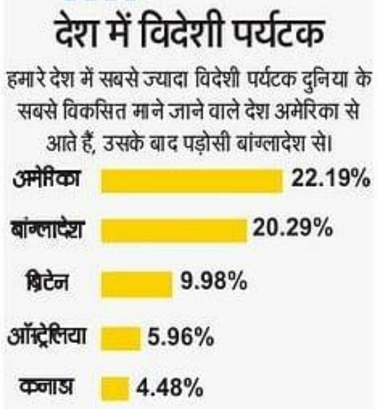


स्रोत : पर्यटन मंत्रालय

**प्रभु ईसा ने कहा, 'इस बीमार व्यक्ति को यदि मैं तड़पता छोड़कर प्रवचन करने जाता, तो मेरी आत्मा कचोटती रहती। इसीलिए मैंने सेवा कार्य को प्राथमिकता दी।'**

### कथनी-करनी एक हो

अंतर्यात्रा
शिवकुमार गोयल

ईसा को अपने भक्तों के बीच प्रवचन करने जाना था। वह घर से प्रवचन स्थल की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने एक व्यक्ति को सड़क के किनारे बैठा देखा। वह पेट में दर्द के कारण कराह रहा था।

उसकी हालत देखकर ईसा वहीं रुक गए। उन्होंने उसे अपनी गोदी में लिटाया। पीने के लिए ठंडा पानी लाकर दिया। फिर उसे पास के चिकित्सालय में इलाज कराने के लिए ले गए। चिकित्सक से दवा दिलाई तथा उसकी सेवा-सुश्रुषा में लगे रहे।

जब वह समय पर प्रवचन समारोह में नहीं पहुंचे, तो आयोजक तथा अन्य शिष्य उन्हें खोजने चल पड़े। उन्होंने चिकित्सालय के लॉन में प्रभु ईसा को एक व्यक्ति की सेवा करते हुए देखा। उन्होंने पास जाकर विनम्रता से कहा, 'प्रभु, आपका प्रवचन सुनने के लिए हजारों व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं। मगर आप एक साधारण व्यक्ति की सेवा में जुटे हुए हैं। ऐसा आपने क्यों किया?'

प्रभु ईसा ने जवाब दिया, 'इस बीमार व्यक्ति को मेरी ज्यादा जरूरत है। यदि मैं इसे तड़पता छोड़कर प्रवचन करने पहुंच जाता, तो मेरी आत्मा ही मुझे कथनी-करनी के अंतर के लिए कचोटती रहती। इसीलिए मैंने सेवा कार्य को प्राथमिकता दी।' सभी शिष्यजन ईसा की कथनी-करनी को एक देखकर गद्गद हो उठे।

*(अमर उजाला आर्काइव से)*

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 15 अप्रैल, 1955

### पश्चिम बंगाल में जमींदारी प्रथा खत्म

बंगाल में आज जमींदारी प्रथा का खात्मा

कलकत्ता, १४ अप्रेल। बंगाल की १५० वर्ष पुरानी जमींदारी प्रथा कल पश्चिमी बंगाल के नव वर्ष पर समाप्त करदी जायगी। इस दिन ८०-८५ लाख किसान भूमि का स्वामी हो जायगा और चार लाख एकड़ भूमि उन किसानों को मिल जायगी जो भूमि विहीन हैं। बंगाल

**पश्चिम बंगाल की 150 वर्ष पुरानी जमींदारी प्रथा आज से खत्म हो गई। आज 80-85 लाख किसान भूमि के स्वामी बन जाएंगे और चार लाख एकड़ भूमि भूमिहीन किसानों को दी जाएगी। राज्य सरकार जमींदारों को 20 करोड़ रुपये हर्जाना देगी।**

## मंगल को पृथ्वी बनते देर नहीं लगेगी

**वर्तमान भौतिकवादी तौर-तरीकों के साथ इंसान अगर मंगल पर बस भी जाता है, तो उसे भी वह पृथ्वी की तरह बिगाड़ते देर नहीं लगाएगा।**

स्टीवन तिंगे — विज्ञान

प्राचीन काल से ही मंगल ग्रह एक मिथक की तरह मानवीय प्रेरणा और आकर्षण का केंद्र रहा है। अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए यह शोध का एक दिलचस्प विषय भी रहा है और परग्रहीय जीवन की खोज का एक वैध उम्मीदवार भी। 1960 के दशक से ही मंगल अंतरिक्ष अभियानों का एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है। लेकिन अब पहली बार नासा ने निजी क्षेत्र से वाणिज्यिक मंगल मिशन पर प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं।

इन मिशनों में लाल ग्रह पर विभिन्न पेलोड ले जाने से लेकर संचार सेवाएं प्रदान करने की बात हुई है, पर अंतरिक्ष यात्रियों को वहां भेजने पर अब तक कोई बात नहीं हुई है। मगर क्या लोग वाकई मंगल ग्रह पर जाना चाहते हैं? सवाल यह भी है कि लोगों को मंगल की धरती पर उतारने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है? तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए?

1960 के बाद से मंगल ग्रह पर अब तक करीब

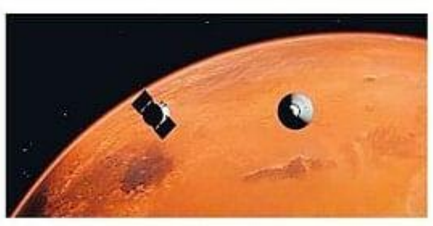

50 मिशन भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 31 कामयाब रहे हैं, जो बुरा औसत नहीं है। 2016 में शिआपरेल्ली लैंडर की दुर्घटना जैसी विफलताएं भी मिली हैं। इसमें संदेह नहीं कि इन मिशनों से मंगल ग्रह के बारे में प्रचुर जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसके वायुमंडल, कक्षा और भूविज्ञान के अलावा यहां की सतह से दरवाजों और चेहरे जैसी अद्भुत छवियां भी दिखी हैं। हालांकि वैज्ञानिक इन सभी छवियों को चट्टानें ही बता रहे हैं, लेकिन इस ग्रह को लेकर आम लोगों की बढ़ती रुचि से पता चलता है कि यह हमारी कल्पनाओं में किस कदर व्याप्त है। एक सामान्य अंतरग्रहीय अंतरिक्ष मिशन की लागत करीब एक अरब अमेरिकी डॉलर होती है। यानी पिछले कुछ वर्षों में दुनिया की तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों ने मंगल ग्रह पर करीब 50 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं और ये सिर्फ कैमरे, रोवर्स और लैंडर्स भेजने के लिए हैं, लोगों को वहां भेजना तो अगले स्तर की बात होगी। दशकों से नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने अंतरिक्ष मिशनों पर भारी रकम खर्च की है।

लेकिन 2020 के दशक में अंतरिक्ष क्षेत्र में अन्वेषण को समृद्ध बनाने वाली तकनीकें वाणिज्यिक दुनिया में तेजी से विकसित हो रही हैं। इनमें से एक उदाहरण है एलन मस्क का स्पेस एक्स, जिसके कई उद्देश्यों में से एक है मंगल मिशन और अंतिम लक्ष्य है मानवता को अंतरग्रही बनाना। जहां नासा का दृष्टिकोण इन अंतरिक्ष परियोजनाओं को लेकर रूढ़िवादी रहा है, वहीं स्पेस एक्स बहुत सारे बदलाव तेजी से करता है और अपनी विफलताओं से जल्दी सीखता भी है। स्पेस एक्स अकेला नहीं है। खासकर अमेरिका में अंतरिक्ष तक पहुंच देने वाले वाणिज्यिक प्रदाताओं का उद्योग काफी तेजी से फल-फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि नासा अपनी परियोजनाओं को बंद कर रहा है। वह सिर्फ वाणिज्यिक प्रदाताओं को जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 20 साल पहले की तुलना में चीजें जिस तरह से बदली हैं, उसे देखते हुए यह कदम अपरिहार्य भी लग रहा था। महंगे अंतरिक्ष मिशनों को सस्ता और ज्यादा कुशल बनाने के लिए भी ऐसी पहलें जरूरी थीं। वाणिज्यिक क्षेत्र की कंपनियों को भी इससे प्रोत्साहन मिला है, जो अंतरिक्ष मिशनों को पूरा करने के लिए लगातार नव-प्रवर्तन कर रही हैं। हालांकि ये अभी बिल्कुल शुरुआती दिन हैं और व्यावसायिक दृष्टिकोण को खुद को साबित करना होगा।

जैसा करीब सौ साल पहले एचजी वेल्स ने अपने उपन्यास *द वार ऑफ वर्ल्ड्स* में भी बताया था, मंगल ग्रह आधुनिक मानस में एक रहस्यपूर्ण और खतरे के स्थान के तौर पर देखा जाता है। इस पर कई फिल्में और टीवी शो भी बन चुके हैं। काफी कुछ लिखा भी जा चुका है। सवाल फिर भी वही है कि क्या मनुष्य को मंगल ग्रह की यात्रा करनी चाहिए? मस्क जरूर ऐसा करना चाहते हैं। 2010 के दशक में नीदरलैंड के एक स्टार्ट-अप मार्स-वन ने इस मामले में जरूर पहल की थी। इस स्टार्ट-अप ने मंगल ग्रह की यात्रा के इच्छुक 100 स्वयंसेवियों का चयन किया और 2019 में दिवालिया होने के पहले लाखों डॉलर कमा लिए। इससे पता चलता है कि समाज का एक ऐसा समृद्ध तबका है, जो मंगल ग्रह पर बसने की इच्छा भी रखता है। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि दूसरे ग्रह को बिगाड़ने की जगह पहले अपने ग्रह को सुधारने की जरूरत है। वर्तमान सोच के साथ इंसान अगर मंगल पर बस भी जाता है, तो उसे भी वह पृथ्वी बनाते देर नहीं लगाएगा।

*(कन्वर्सेशन से)*

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

# आरक्षण विमर्श

सर्वोच्च न्यायालय में आरक्षण पर फिर एक बार बहस छिड़ गई है, जिस पर सभी का ध्यान जाना स्वाभाविक है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की पीठ ने कहा कि भारतीय संविधान यह नहीं कहता कि हाशिये पर रहने वाले समूहों के लोग अक्षम हैं, जबकि अन्य समूहों के लोग सक्षम। पीठ ने यह भी कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लिए आरक्षण सुसंगत है। वाकई, उन्हें आरक्षण की बड़ी जरूरत है और इसे आने वाले अनेक दशकों तक बनाए रखने में ही समाज का व्यापक हित है, किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने जिस दिशा में इशारा किया है, वह भी महत्वपूर्ण है और उस पर कदम उठाना भले आसान न हो, पर विचार का क्रम अवश्य जारी रहना चाहिए। वैसे यह सवाल नया नहीं है कि क्या जिन लोगों को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल चुका है, वे आरक्षण का लाभ छोड़ने के लिए तैयार होंगे? हालांकि, ऐसी किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए ध्यान रखना होगा कि आरक्षण संबंधी कोई भी बिंदु अति संवेदनशील है और उस पर सहजता से कोई भी फैसला मुमकिन नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय में कुछ न्यायाधीशों ने जो टिप्पणियां की हैं, उन पर विशेष रूप से गौर करने की जरूरत है। एक न्यायमूर्ति ने पंजाब के महाधिवक्ता से पूछा कि क्या राज्य सरकार एससी/एसटी वर्ग के भीतर कुछ उन उपजातियों को आरक्षण के लाभ के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में है, जिन्होंने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और बराबरी पर आ गई हैं? क्या ऐसे लोगों को आरक्षण की सुविधा से बाहर आकर सामान्य श्रेणी के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष नहीं करना चाहिए? उनकी जगह, जो लोग पिछड़ों में भी पिछड़े हैं, उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। एक अन्य न्यायमूर्ति ने भी संकेत किया कि एक विशेष पिछड़े वर्ग के भीतर, जब कुछ जातियां एक निश्चित स्थिति तक पहुंच जाती हैं और अगड़ी जातियों के बराबर हो जाती हैं, तो उन्हें आरक्षण के लाभ से बाहर निकल जाना चाहिए। आप इन टिप्पणियों को सलाह कहिए या विचार, इन पर अमल का काम तो संसद या सरकार को ही करना है। अदालतों की अपनी सीमा है, उन्हें कोई भी फैसला कानून के दायरे में ही देना है।

**यह संवेदनशील सवाल नया नहीं है कि क्या जिन लोगों को आरक्षण का भरपूर लाभ मिल चुका है, वे यह लाभ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे?**

भारत के प्रधान न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने एक विषय तो छेड़ा है, मगर माकूल फैसला तो सरकारें अपने सियासी लाभ-हानि पर विचार करके ही लेंगी। बेशक, किसी से आरक्षण की सुविधा वापस लेने का कोई भी प्रबंध बड़े पैमाने पर विरोध की स्थिति पैदा कर सकता है। आरक्षण पाने वालों की स्वेच्छा से ही फैसला हो, तो ज्यादा सही है। इसके कुछ पहलू हैं, जिन पर सरकारों को विचार करना होगा। पहली बात, आरक्षण का लाभ हुआ है। दूसरी बात, यह कोई भी नहीं मानेगा कि उसे आरक्षण का पर्याप्त लाभ हो चुका है। तीसरी बात, यह हर कोई मानेगा कि आरक्षण का लाभ सबको नहीं मिला है, मतलब, आरक्षण से वंचितों की भी अभी ठीक-ठाक संख्या है। अब चौथी बात, दरअसल सवाल भी है कि विगत दशकों में तैयार हुए नए क्रीमी लेयर को आरक्षण छोड़ने के लिए कैसे तैयार किया जाए? विडंबना है कि आरक्षण के विस्तार में ही राजनेता समाधान खोजते रहे हैं और आरक्षण को कागजों से उतारकर एक बड़ी वंचित आबादी तक पहुंचाना अभी भी आसान नहीं है। कुल मिलाकर, आरक्षण की मांग बहुत है और आपूर्ति कम, तभी तो विवाद का रास्ता चौड़ा हो रहा है, जिस पर फूंक-फूंककर कदम बढ़ाना है।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 08 फरवरी, 1949

### रूस और नार्वे

अन्तर्राष्ट्रीय जगत में सुरक्षा के नाम पर आर्थिक और सैनिक गुटबन्दियों की योजनाएं चल रही हैं। विश्व शान्ति के लिए इन योजनाओं को आवश्यक बताया जाता है। संयुक्त राष्ट्रीय संघ का निर्माण विश्व शान्ति की रक्षा के लिए ही किया गया है, किन्तु शान्ति रक्षा करने की उसकी क्षमता में अनेक राष्ट्रों को कोई विश्वास नहीं है। अतः वे आत्मरक्षा के लिए प्रादेशिक योजनायें बनाने में संलग्न हैं। यूरोप के देशों की पुनर्रचना में सहायता देने के लिए अमेरिका ने एक योजना बनाई थी, जो मार्शल योजना के नाम से विख्यात है। इस योजना में पूर्वी यूरोप के देश शामिल नहीं हुए। उससे केवल पश्चिमी यूरोप के देश ही लाभ उठा रहे हैं। पूर्वी यूरोप के देशों को यह शंका पैदा हुई कि आर्थिक सहायता के नाम पर अमेरिका उनकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना चाहता है। इसलिए उन्होंने अपने को 'अमेरिकी आर्थिक साम्राज्यवाद' से अलग रखना ही उचित समझा। उन्होंने रूस की सरपरस्ती में अपने लिए एक अलग आर्थिक योजना बनाई है।

आर्थिक योजनाओं के अलावा सैनिक समझौते करने की भी कोशिश की जा रही है। पश्चिमी यूनियन के बीच एक सैनिक समझौता हुआ है। उसमें ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्ष्मबर्ग शामिल हुए हैं। अब उत्तरी अटलांटिक के देशों के बीच फौजी समझौते की बातचीत चल रही है। इस गुट में अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, हालैण्ड, बेल्जियम और लक्ष्मबर्ग तो शामिल होंगे ही, प्रश्न यह है कि क्या इस गुट में स्केण्डिनेविया के देश भी शामिल होंगे? इन देशों ने रक्षा के लिए अपना एक अलग गुट बनाने की कोशिश की थी, किन्तु वह विफल रही। उनका उद्देश्य यह था कि वे अपने को तटस्थ रखें। किन्तु उन्हें हथियारों की आवश्यकता तो थी ही। अमेरिका से हथियार सुलभ कराने की प्रार्थना की गई। किन्तु उसने उसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिका की उत्पादन शक्ति चाहे जितनी बढ़ी-चढ़ी हो, किन्तु वह हर किसी को हथियार मुहैया करने की स्थिति में नहीं है। वह उन देशों के लिए हथियार सुरक्षित रखना पसन्द करेगा, जो अलग रहने के बजाय किसी रक्षात्मक गुट में शामिल होने को तैयार हैं। इधर रूस और नार्वे के बीच कुछ पत्र-व्यवहार हुआ है, उससे पता चलता है कि नार्वे को उत्तरी अटलांटिक समझौते में शामिल करने का प्रयास किया गया है।

# आज कौन सी राह चुनेगा पाकिस्तान

यहां स्कैन करें

सुशांत सरीन | सीनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

**यदि हम यह मान भी लें कि सेना की मदद से नवाज शरीफ फिर से सत्ता में आ रहे हैं, तब भी पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति बहुत सुधरती हुई नहीं दिख रही है।**

आज (8 फरवरी) पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 266 सीटों के लिए मत डाले जा रहे हैं। यह कुल 336 सदस्यों का सदन है, जिसकी 70 सीटें महिलाओं और गैर-मुसलमानों के लिए आरक्षित रखी जाती हैं। इनका निर्वाचन 9 फरवरी को आ रहे जनादेश में जीतने वाली पार्टियां करेंगी। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इस आम चुनाव से एक नई इबारत लिखने जा रहा है। मगर क्या वास्तव में ऐसा ही है?

देखा जाए, तो यह चुनाव काफी महदूद किस्म का है। देश में सबसे लोकप्रिय इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी को पूरी तरह से अलग-थलग कर दिया गया है। उसके आला नेता या तो जेल में हैं या फिर फौज व पुलिस से बचने के लिए जहां-तहां छिपे हुए हैं। जो थोड़े-बहुत बचे हैं, वे बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां तक कि इस पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को भी किसी न किसी तरह से परेशान किया जा रहा है।

स्पष्ट है कि फौज हर कीमत पर मनमाफिक नतीजे चाहती है। ऐसा वह पूर्व में भी कर चुकी है। मसलन, 1997 के चुनाव में बेनजीर भुट्टो (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) को सत्ता से हटाने के लिए उसने तमाम दांव-पेच खेलकर नवाज शरीफ (पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज) के लिए मैदान खाली करवाया। इस बार भी यही माना जा रहा है कि मियां शरीफ की सदारत में पीएमएल-एन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि फौज ने अन्य दलों का किस हद तक दमन किया।

फिलहाल, चुनाव नतीजों को लेकर तीन तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली, नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत मिल सकता है। हालांकि, तब भी वह बाकी दलों का साथ लेना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की दुश्वारियों को दूर करने में उन्हें कई पार्टियों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी संभावना यह है कि नवाज संभवतः पूर्ण बहुमत न हासिल न कर पाएं। तब उनके सहयोगी वे दल हो सकते हैं, जो फौज के इशारे पर चलते हैं। इनमें इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी, एमक्यूएम, जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम जैसे दल हो सकते हैं। कुछ निर्दलीय सांसद भी नवाज का साथ दे सकते हैं, हालांकि इस बहुमत की डोर भी पूरी तरह से फौज के हाथों में रहेगी।

तीसरी संभावना अप्रत्याशित है, लेकिन असंभव भी नहीं। इससे सारा गणित बिगड़ सकता है। मुमकिन है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पीटीआई के उम्मीदवार इतनी बड़ी संख्या में चुनकर आ जाएं कि सत्ता-समीकरण उनके पक्ष में हो जाए। अगर ये 50-60 की संख्या में भी जीतकर आ जाएं और पीपीपी उम्मीद से कहीं अच्छा (अभी उसके 40-50 सीट जीतने की संभावना है) प्रदर्शन करते हुए 60-70 सीटें जीत ले, तो फौज का पूरा खेल बिगड़ सकता है। इसमें नजर इस पर भी बनी रहेगी कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कैसा प्रदर्शन करती है, क्योंकि पंजाब और सिंध जैसे सूबों में यदि वह एकाध सीटें जीत सकी या नवाज शरीफ के वोट-बैंक में सेंध लगा सकी, तो पाकिस्तान का सियासी समीकरण काफी दिलचस्प बन जाएगा।

इन संभावित चुनावी नतीजों को दरकिनार करके यदि यह मान लें कि नवाज शरीफ सत्ता में आ रहे हैं, तब भी पाकिस्तान की राजनीतिक स्थिति बहुत सुधरती नहीं दिख रही है। इसकी एक बड़ी वजह हालिया गठित स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल, यानी एसआईएफसी भी है। यह एक ऐसी संस्था है, जिसके सदस्य सियासतदान और फौज के अधिकारियों के साथ कुछ विशेषज्ञ हैं। पाकिस्तान की सभी आर्थिक नीतियां यहीं से तय हो रही हैं। चूंकि नवाज शरीफ कुछ समय तक तो फौज के साथ कदमताल मिला सकते हैं, लेकिन उनके इतिहास को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि वह पूरी तरह से फौज की गोद में बैठना चाहेंगे। वह कहीं न कहीं अपनी मर्जी की करना चाहेंगे, जो फौज को गवारा नहीं होगा। ऐसे में, एसआईएफसी का हस्तक्षेप फौज और नवाज शरीफ सरकार के बीच खाई बढ़ाने का काम कर सकता है।

यही वजह है कि इमरान खान अब भी पाकिस्तान की राजनीति में बड़े खिलाड़ी बने रहेंगे। भले ही अभी उनको 14 साल की सजा सुनाई गई है, लेकिन अपील करने पर उनको कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। बेशक, फौज यह चाहती है कि कम से कम 9 मई, 2023 की बगावत के लिए इमरान को सख्त सजा मिले, क्योंकि उस घटना में सैन्य ठिकानों पर इमरान समर्थकों ने धावा बोल दिया था, लेकिन नवाज शरीफ के प्रति अविश्वास के कारण वह इमरान का विकल्प खुला रखना चाहती होगी। हालांकि, इसकी भी तब तक बहुत गुंजाइश नहीं लगती, जब तक फौज की बागडोर असीम मुनीर के हाथों में है।

साफ है, नई सरकार के पास अपनी पसंद का काम करने का बहुत मौका नहीं होगा। इससे पाकिस्तान की दुश्वारियां और बढ़ेंगी। पीएमएल-एन के घोषणापत्र से भी बहुत उम्मीद नहीं जगती। उसमें तमाम तरह के सपने जरूर दिखाए गए हैं, लेकिन उसकी रूपरेखा नहीं बताई गई है। ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ अब भी उसी दौर में जी रहे हैं, जब चीन, अरब देश या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से पाकिस्तान को कई तरह की आर्थिक इमदाद मिल जाती थी। अब नई सरकार को वैश्विक कर्ज माफ करवाने होंगे या उनके भुगतान की मीयाद बढ़वानी होगी, जो कोई आसान काम नहीं।

मुश्किलें घरेलू मोर्चों पर भी आ सकती हैं। नेशनल असेंबली के साथ प्रांतों के भी चुनाव हो रहे हैं। लिहाजा, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में यदि पीएमएल-एन के विरोधी दलों की सरकारें बन गईं, तो पाकिस्तान के सामने विदेश नीति व सुरक्षा के मसले मुंह बाए खड़े रहेंगे। इन सबसे यही लगता है कि पाकिस्तान के मूल ढांचे को ध्वस्त किए बिना इस मुल्क को पटरी पर नहीं लाया जा सकता, लेकिन अभी यह कुव्वत किसी भी दल में नहीं दिख रही।

भारत इसीलिए पाकिस्तान की नई सरकार को लेकर बहुत उम्मीद नहीं बांधेगा। वैसे भी, पीएमएल-एन के घोषणापत्र में भारत से संबंध सुधारने की बात तभी कही गई है, जब नई दिल्ली कश्मीर में अनुच्छेद 370 की पुनर्बहाली करती है। अब ऐसा तो होने से रहा। फिर, कमर जावेद बाजवा से अब तक पाकिस्तानी फौज के रुख में बड़ा बदलाव आ चुका है। लिहाजा, भारत के साथ पाकिस्तान की छोटे स्तर पर बातचीत तो हो सकती है, मगर बड़े मसलों पर शायद ही चर्चा होगी। साल 2022 में बनी शहबाज शरीफ सरकार का कार्यकाल इसका बड़ा संकेत है, जिसमें पाकिस्तान और भारत की आपसी तल्खियां बढ़ी ही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# देश की मुख्यधारा से अभी भी दूर कुछ आदिवासी समूह

यहां स्कैन करें

अशोक भगत | समाजसेवी

देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत भाग आदिवासियों का है। मतलब, देश में 10 करोड़ से ज्यादा आदिवासी हैं, इनमें से लगभग 28 लाख ऐसे हैं, जो आज भी विकास की मुख्यधारा से दूर हैं। आदिवासियों की इतनी बड़ी संख्या भारत के विकास में प्रभावशाली हस्तक्षेप दर्ज नहीं करा पा रही है। एकात्म मानववाद के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में कहें, तो ये भारतीय समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के नागरिक हैं।

आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल 83 चरमपंथी माओवादी आतंकवाद प्रभावित जिलों में से 42 अनुसूचित क्षेत्र के हैं। भारत सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक आंकड़े में बताया गया है कि इन आदिवासियों के कुल 75 समूह हैं, जो देश के 22 हजार गांवों में निवास करते हैं। जानकारों की मानें, तो आदिवासी, जो वन एवं दुर्गम पहाड़ों पर निवास करते हैं, इनके पास व्यावहारिक सोच और सशक्त सांस्कृतिक विरासत है। आधुनिक विकास योजनाओं से देश को लाभ तो हुआ है, पर आदिवासी समाज को इसका सबसे अधिक खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। बांध निर्माण की वजह से सबसे अधिक इसी समाज के लोगों का पलायन हुआ है। एक हालिया आधिकारिक आंकड़े में बताया गया है कि बांध निर्माण में पलायन करने वालों में से 40 प्रतिशत भाग आदिवासी समूहों का है। इस समुदाय की जितनी चिंता हमारी व्यवस्था को करनी चाहिए थी, उतनी नहीं हुई है।

**तेज बढ़ते भारत से दूर करीब 28 लाख आदिवासियों के कुल 75 समूह हैं, जो देश के 22 हजार गांवों में निवास करते हैं।**

ध्यान रहे, विदेशी व विध्वंसक शक्तियां देश के उस भाग को अपना निशाना बनाती हैं, जो कमजोर होता है और उस देश की मुख्यधारा से दूर होता है। हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में विदेशी शक्तियों द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र प्रभावशाली है। इस क्षेत्र के नागरिकों को विश्वास दिलाना होगा कि यह देश उनका भी है। स्थानीय प्रशासन से लेकर केंद्रीय शासन तक में उनका हस्तक्षेप दिखना चाहिए। अभी हम जिन सूक्ष्म आदिवासियों के 75 समूहों पर बात कर रहे हैं, उनको चिह्नित करने के लिए भारत सरकार ने एक मानदंड तय किया है। इसके तहत इन 75 आदिवासी समूहों में वे समूह आएंगे, जिनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। प्रारंभिक सरकारों ने इनके निवास स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में रुचि नहीं दिखाई, फलस्वरूप ये विकास की दौड़ से अछूते रहे और बाहर हो गए। इन क्षेत्रों में मिशनरी गतिविधियां होती रहीं। बाद के दिनों में बड़ी परियोजनाओं के निर्माण में इनकी ही भूमि व निवास स्थल की आहूति दी गई। बची-खुची कसर उग्रवादी संगठनों के विस्तार ने पूरी की, जिन्होंने अपना ठिकाना इन्हीं क्षेत्रों में बनाया। विकास के हर चरण से यह समुदाय सर्वस्व होम करके बहुत लाभ में न रहा।

भारत में जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात होती रही है, उसके मूल में संस्कृति है और उस संस्कृति का मूल यही सूक्ष्म आदिवासी समूह हैं, जिनकी आस्था प्रकृति पूजा पर आधारित है। आज दुनिया जिस जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही है, उसका समाधान भी इसी समाज के पास है।

गीत, संगीत और नृत्य के माध्यम से ये आदिवासी अपना ज्ञान अगली पीढ़ी को देते हैं। इसके लिए इनके पास एक संस्था भी होती है, जिसे घोटुल या धुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। इस शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्था के अलग-अलग नाम हैं। रोजगार और कृषि कार्य की बारीकियों के लिए भी इन आदिवासियों ने अपने खुद के विज्ञान का सृजन कर रखा है। ऐसे में, इस समाज का विकास इनके मूल स्थान से और मूल संस्कृति से काटकर करना संभव नहीं होगा। इन्हें अपने मूल निवास पर रहने दिया जाए और वहीं हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्हें मिटाकर या छोड़कर आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। वैसे, तुलनात्मक रूप से भारत में आदिवासियों का संरक्षण बेहतर ढंग से हुआ है और आबादी में उनका प्रतिशत 1951 की जनगणना के अनुसार 6.23 था, जो अब 8.6 फीसदी को पार कर रहा है। दूसरी ओर, अमेरिका में आदिवासियों की संख्या घटते-घटते तीन प्रतिशत भी नहीं रह गई है। हमें आदिवासियों की ताकत बनकर खड़े रहना चाहिए, वे हमारे देश की शक्ति भी हैं और खूबसूरती भी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# छत पर खोया ऊंट

एक रात महल की छत पर कुछ पदचाप सुनाई पड़े। बादशाह सोने को बिस्तर पर गया ही था। वह सशंकित हो उठा कि पता नहीं चोर है या कोई और? उसने अंदर से ही चिल्लाकर पूछा, 'किसने जुर्रत की है रात में छत पर चढ़ने की?' दूसरी तरफ से आवाज आई, 'क्षमा करें बादशाह, मेरा ऊंट खो गया है, उसे ही खोज रहा हूं।' क्रोधित बादशाह ने कहा : 'क्या पागलपन है यह? छत पर कहीं ऊंट खोता है?' उस व्यक्ति ने जवाब दिया : 'जहांपनाह, आप तो बड़े समझदार हैं। आप समझते हैं कि छत पर ऊंट नहीं खो सकता, नामुमकिन है यह। फिर आपको यह समझ में क्यों नहीं आता कि अहंकार के सिंहासन पर बैठकर कभी कोई शांत नहीं हुआ, और न आनंदित हुआ है? बादशाह बिस्तर से उठकर बाहर भागा, जैसे भूचाल आ गया हो। उसने बहुत ढूंढ़ा, मगर वह आदमी मिला ही नहीं।

बादशाह का नाम इब्राहीम था। अगले दिन वह बहुत उदास था। उसके सिंहासन पर बैठते ही जब दरबार शुरू हुआ, तभी एक व्यक्ति भीतर घुस आया। द्वारपालों ने उसे बहुत रोका, मगर यह कहते हुए कि धर्मशाला में सभी को ठहरने का हक है, वह दरबार में घुस आया और बादशाह के सामने जाकर पूछा, 'जहांपनाह, क्या इस सराय में मैं कुछ दिन ठहर सकता हूं?' बादशाह गुस्से में बोला, 'तुम पागल मालूम होते हो! रात ही एक पागल से मिलना हुआ, ये दूसरे आ गए। सराय नहीं, यह मेरा महल है। अपने शब्द वापस लो, वरना जबान कटवा देंगे।' निर्भीक आगंतुक ने कहा, 'यह सराय नहीं है? कुछ ही दिनों पहले मैं आया था, तब तो इस सिंहासन पर किसी और आदमी से मेरी मुलाकात हुई थी?' बादशाह ने लगभग चीखते हुए कहा, 'वह मेरे पिता थे।'

उस साहसी आदमी ने पूछा, 'अब वह कहां हैं? मैं तो उसके पहले भी आया था, तब कोई और आदमी इस सिंहासन पर बैठा था?' बादशाह ने कहा, 'वह मेरे दादा हुजूर थे।' उस व्यक्ति ने कहा, 'हर बार सिंहासन पर दूसरे आदमी को पाकर ही मैंने सोचा जरूर यह सराय है, यहां पर लोग कुछ दिन ठहरते हैं और चले जाते हैं। तो क्या मैं इस सराय में ठहर सकता हूं?' बादशाह समझ गया था। उसने आगंतुक के पैर पकड़ लिए। उसे लगा, यह वही आदमी है, जो रात छत पर था। उसने पूछा, 'मैंने अपनी पूरी जिंदगी छत पर ऊंट खोजने, और धर्मशाला को महल समझने में गंवा दी, अब मैं क्या करूं?'

**बहुत सारी सराय हैं- कामनाओं की, वासनाओं की : भटकिए, लेकिन जिस दिन ख्याल आ जाए कि यह धर्मशाला है, उस दिन भी वापस लौट आइए अपने घर। घर तो हमेशा आपके साथ है।**

हम सब छत पर ऊंट खोज रहे हैं, सराय को अपना महल समझ रहे हैं। और भी बहुत सारी सराय हैं- आशाओं की, कामनाओं की, वासनाओं की : भटकिए, लेकिन जिस दिन ख्याल आ जाए कि यह धर्मशाला है, उस दिन भी वापस लौट आइए अपने घर। घर तो हमेशा आपके साथ है।

ओशो

आशुतोष राणा | अभिनेता

**आखिर क्यों कहा गया उनको महादेव? प्रतिकूल परिस्थितियों में जो अनुकूल स्थिति पैदा कर दें, उनको ही महादेव कहा जाता है; विसंगति में जो संगति स्थापित कर दें, वही शिव हैं।**

# अखिलेश का एक मजबूत सोशल कार्ड

जोर-शोर से बनाए गए 'इंडिया' ब्लॉक में भले ही उथल-पुथल हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का सामाजिक समीकरण 'पीडीए' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) काफी मजबूत दिख रहा है। अच्छी बात है कि कांग्रेस ने भी इसे मान लिया है, जिस कारण यह कार्ड उत्तर प्रदेश में काफी असर दिखा सकता है। समाजवादी पार्टी ने तो एक सर्वे के हवाले से यह भी कहा है कि 90 फीसदी आबादी इस बार पीडीए के लिए एकजुट होकर वोट करेगी, जिससे एनडीए के सभी समीकरण व फॉर्मूले फेल हो जाएंगे। 90 फीसदी आबादी वाकई में ऐसा करेगी, यह तो अभी साफ-साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन नौजवानों में जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर हताशा है, महिलाएं महंगाई से परेशान हैं, पेंशनधारियों को अपना वाजिब हक नहीं मिल रहा, और नौकरी-पेशा मध्यवर्ग सरकारी नीतियों से जूझ रहा है, उससे यह विश्वास तो होता ही है कि एक बड़ी संख्या इस बार एनडीए के खिलाफ वोट दे सकती है।

पीडीए इसलिए भी बाजी पलट सकती है, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव भावनात्मक तरीके से मतदाताओं के दिलों को छू रहे हैं। वह उस घटना का जिक्र बार-बार कर रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री आवास को गंगाजल से धोया गया था। इससे यादव ही नहीं, पिछड़े व दलित वर्ग के लोग भी उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसा कहकर अखिलेश वास्तव में वंचित तबकों को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कैसे उनको आज भी अपवित्र समझा जाता है! देखा जाए, तो राज्य में दलित, मुसलमान और पिछड़ों की बड़ी संख्या सत्तारूढ़ दल से नाराज चल रही है। साल 2019 के आम चुनाव में एनडीए को मुसलमानों का जितना वोट मिला था, वह 2014 की तुलना में कम था। दलित जरूर मायावती को अपना नेता मानते हैं, लेकिन जिस तरह से बहनजी अब सुस्त पड़ती जा रही हैं, उससे यह वोट-बैंक भी उनसे छूटता जा रहा है। हां, इसका झुकाव कुछ हद तक एनडीए की तरफ दिखता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से दलितों को निशाना बनाया गया है, उससे यह कयास गलत नहीं लगता कि इस बार यह वर्ग विपक्षी दलों का साथ दे सकता है। कुछ यही बात पिछड़े वर्गों के लिए भी कही जा सकती है, क्योंकि एनडीए गठबंधन तो घोषित तौर पर उच्च वर्गों का गठबंधन है। लिहाजा, अखिलेश यादव भी चौधरी चरण सिंह की तरह सफल हो सकते हैं, जिन्होंने अहीर, जाट, गुजर और राजपूत को मिलाकर 'अजगर' समीकरण बनाया था और खुद को मजबूती से स्थापित किया था।

रोहित कुमार, टिप्पणीकार

## अनुलोम-विलोम

### पीडीए

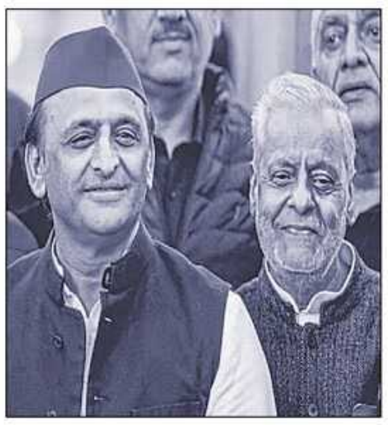

# जमीन पर नहीं दिखता पीडीए का असर

लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में डट गए हैं। उन्होंने एक नया सोशल कार्ड खेला है- पीडीए, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों का गठजोड़। संभवतः वह लालू यादव की तरह सफल होने के सपने देख रहे होंगे, जिन्होंने मुसलमानों और यादवों का 'एमवाई' समीकरण बनाया था, जो बिहार में काफी सफल रहा था। मगर ऐसा करते हुए वह संभवतः भूल गए हैं कि वह दौर बीत चुका है। अब राजनीति और धर्म, दो विपरीत ध्रुव पर नहीं देखे जाते हैं। अब इनका इस कदर समागम हो गया है कि धर्म के बिना राजनीति की कल्पना ही मुश्किल है, और भाजपा इसकी स्वाभाविक माहिर खिलाड़ी है। इस बात का इल्म अखिलेश यादव को भी होगा, क्योंकि 2012 में जिस यादव समुदाय के वोट-बैंक से वह मुख्यमंत्री की कुरसी तक पहुंचे थे, उसका एक हिस्सा अब भाजपा की तरफ झुक गया है। यही बात दलित जातियों के लिए भी कही जा सकती है, जो अब आर्थिक-सामाजिक आरक्षण जैसे मसलों पर शायद ही ध्यान देना चाहेंगी।

वर्ष 2019 का आम चुनाव इसी की तस्दीक करता है। उसमें एनडीए को तमाम वर्गों ने पसंद किया था। आंकड़े बताते हैं कि दलितों की नाराजगी को दूर करते हुए एनडीए, विशेषकर भाजपा ने 2014 की करीब एक-चौथाई (24 फीसदी) वोटों की तुलना में 2019 में एक-तिहाई से अधिक (34 प्रतिशत) दलित वोट हासिल किए। अन्य पिछड़े वर्गों की ऊंची जातियों में भी कुछ ऐसा ही बदलाव हुआ। 2014 की 30 फीसदी की तुलना में भाजपा ने 2019 के आम चुनाव में इस वर्ग के 41 फीसदी मतदाताओं का विश्वास प्राप्त किया। अन्य पिछड़ा वर्ग की ही निचली जातियों ने परंपरागत रूप से भाजपा का साथ दिया, और 2014 की 42 फीसदी की तुलना में 2019 में 48 फीसदी जातियों ने भाजपा पर भरोसा जताया। हां, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने में भाजपा विफल रही, फिर भी, उसे यहां बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। साल 2014 के चुनाव में नौ फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिया था, जबकि 2019 में यह आंकड़ा आठ प्रतिशत था।

रही बात सहयोगी कांग्रेस की, तो 2014 में उसके पास दो सीटें थीं, जो 2019 में घटकर एक रह गई, जबकि विधानसभा चुनावों का तो वह जिक्र भी शायद ही करना चाहेगी। चूंकि कांग्रेस आज भी बेहतर स्थिति में नहीं है और सामाजिक समीकरण अखिलेश के खिलाफ हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीडीए काम करेगा। फिर रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा ने उसकी राह और कठिन बना दी है।

कुणाल भास्कर, टिप्पणीकार

# नए वक्त की मांग है तकनीकी कंटेंट लेखन

**डिजिटल मंचों पर मौजूद बाजार को उपभोक्ता से संवाद करने और उसे अपने मंच तक आकर्षित करने के लिए लेखन के कौशल की भी जरूरत पड़ती है। ये आवश्यकता सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान भी होती है, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी। इसीलिए टेक्निकल कंटेंट राइटर्स की मांग भी बढ़ रही है। बता रही हैं त्रिशा**

तकनीक के बढ़ते प्रसार के साथ ही तकनीकी कंटेंट की जरूरत बढ़ी है। यहां तकनीकी कंटेंट से तात्पर्य प्रोडक्ट डेवलपमेंट की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के बारे में बताते डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, ब्रोशर्स, यूजर मैनुअल से लेकर ब्लॉग्स, रिसर्च पेपर्स तक है। वर्तमान दौर में टेक्निकल कंटेंट राइटर्स के लिए खूब काम बन रहा है। ये लेख लिखे जाने तक लिंक्डइन इंडिया पर टेक्निकल कंटेंट राइटर्स की मांग करते 8000 मौके सामने आए। वहीं स्किल ट्रेनिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आईआईएम स्किल की मानें, तो टेक्निकल कंटेंट राइटिंग का काम अगले दस सालों में मुख्यधारा के करियर में शामिल हो जाएगा।

## क्या है टेक्निकल कंटेंट राइटिंग

तकनीकी कंटेंट राइटर में लेखन के उम्दा कौशल और तकनीकी समझ का बढ़िया तालमेल होता है। वे तकनीकी विशेषज्ञों, जैसे इंजीनियर, साइंटिस्ट, आईटी पेशेवर और उपभोक्ता व कम तकनीकी समझ रखने वालों के बीच एक तरह से अनुवादक की भूमिका निभाते हैं। वे बाजार में किसी ब्रांड की प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता के निर्माण में अपने लेखन कौशल से अहम योगदान करते हैं।

## कितनी तरह का काम

**सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन राइटर :** ये सॉफ्टवेयर के लिए गाइड, मैनुअल और डॉक्यूमेंटेशन बनाने के विशेषज्ञ होते हैं।

**तकनीकी कॉपीराइटर:** तकनीकी उत्पादों या सेवाओं के लिए बढ़िया और आसान मार्केटिंग और एडवरटाइजिंग सामग्री तैयार करते हैं।

**एपीआई डॉक्यूमेंटेशन राइटर :** एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त डॉक्यूमेंट बनाने में कुशल होते हैं। ताकि डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स में एपीआई को आसानी से सिंक करके उपयोग कर सकें।

**यूएक्स राइटर :** किसी डिजिटल प्रोडक्ट को उपयोग के दौरान यूजर के एक्सपीरिएंस को बेहतर बनाने में मदद देने वाला टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे किसी वेबसाइट पर बटन लेबलिंग, एरर मैसेज, ऑनबोर्ड मैसेज आदि।

**मेडिकल और साइंस राइटर :** ये रिसर्च के जटिल निष्कर्षों, चिकित्सा प्रक्रियाओं या वैज्ञानिक अवधारणाओं को आसान भाषा में उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं।

**व्हाइट पेपर राइटर:** शैक्षिक, लीडरशिप या कंपनी के कार्यक्षेत्र के लिए तकनीक और ट्रेंड्स की बात करते डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं।

**सोशल मीडिया टेक्निकल राइटर्स :** ये उपभोक्ता से जुड़ने के लिए ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफार्मों पर लिखते हैं।

## एआई नहीं दे सकती मात

आमतौर से माना जाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद से ऐसे स्किल्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये समझें :

- एआई सभी के लिए एक सामान्य कंटेंट बनाते हैं। जबकि टेक्निकल कंटेंट राइटिंग में लेखन के लिए कंपनी विशेष की जरूरतों को समझना होता है। आंकड़ों की सत्यता के लिए भी एआई पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
- उपभोक्ता को होने वाली समस्याओं को समझते हुए रोचक तरीके से लिखना एआई द्वारा फिलहाल संभव नहीं।

shine.com
Great careers start here

## क्यों चुनें

- अधिकतर कामकाज का डिजिटलीकरण होने के चलते इसकी जरूरत बढ़ रही है।
- ग्लोबल कंपनियों के लिए काम करने का मौका मिलता है।
- स्थायी, रिमोट वर्क, पार्टटाइम मौके भी मिलते हैं।
- तकनीकी दुनिया की हलचलों के बारे में अपडेट रहने से क्षेत्र की समझ स्वत: ही निखरती रहती है।
- फ्रीलांस पोर्टफोलियो बना कर अपने काम का भुगतान खुद तय करने की स्थिति में पहुंच सकते हैं।

## क्या होगा रोडमैप

- ग्रेजुएशन अनिवार्य शर्त नहीं है। लेकिन कम्यूनिकेशन या संबंधित विषय में डिग्री सहायक होगी।
- टेक्निकल कंटेंट राइटिंग के कोर्स करें।
- अंग्रेजी भाषा का स्किल निखारें।
- टेक राइटिंग किस क्षेत्र विशेष के लिए करेंगे, उसे तय करें। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग या हेल्थकेयर आदि।
- छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अनुभव बनाएं।
- आपके लेखन के नमूने प्रदर्शित करने वाला एक पोर्टफोलियो विकसित करें। इसके लिए ब्लॉग पोस्ट, लेख या जो काम किया हो, उसके नमूने इस पर पोस्ट करें।
- पेशेवर संगठनों और अनुभवी टेक राइटर्स से जुड़ें।

## काम आएंगे ये कोर्स

- **IIM SKILLS** का टेक्निकल राइटिंग मास्टर्स कोर्स (ऑनलाइन, सशुल्क)
- **Coursera** पर टेक्निकल राइटिंग के विविध कोर्स
- **Udemy** पर टेक्निकल राइटिंग के विविध कोर्स हैं
- **Information Developers Foundation** का टेक्निकल राइटिंग मास्टरी कोर्स
- **K Buffer** के ऑनलाइन व जॉब ओरिएंटेड कोर्स। कुछ सॉफ्टवेयर टूल्स के बारे में भी सिखाते हैं
- **Blue Dots Consultancy** बेंगलुरू के इस संस्थान में टेक्निकल राइटिंग ट्रेनिंग में ऑनलाइन, वर्चुअल और ऑफसाइट मेथडोलॉजी का प्रयोग होता है
- **Symbiosis Centre for Distance Learning (SCDL)** का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टेक्निकल राइटिंग इन बिजनेस मैनेजमेंट, अवधि दो वर्ष, मोड : ऑनलाइन व डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से। इसके करिकुलम में इंडस्ट्री विशेष से संबंधिक विकल्प भी कवर होते हैं, जैसे टेक्निकल राइटिंग फॉर आईटी, इंजीनियरिंग, फार्मास्युटिकल्स और फाइनेंस

*(आईआईएम स्किल के अनुसार)*

## किन उद्योगों में जरूरत

- आईटी, हेल्थकेयर, ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्री, टेलीकम्यूनिकेशंस, फाइनेंस, इंश्योरेंस
- **सैलरी:** टेक्निकल कंटेंट राइटिंग में शुरुआत में औसत वार्षिक वेतन 4 लाख रुपये है।

## यहां से मिलेंगे मौके

**LinkedIn, Indeed, Glassdoor, FlexJobs, Upwork, Fiverr, Dice, The Write Jobs, Society for Technical Communication (STC)** आदि जॉब बोर्ड्स

- रिमोट काम के लिए: **Working Nomads, Remotify, FlexJobs, Freelancer.com, Guru**
- टेक्निकल कंटेंट राइटिंग सेवा देने वाली कुछ प्रमुख कंपनियां, जिनमें नियुक्तियां भी मिल सकती हैं: **Content Whale, Acadecraft, Ibruk, Apna Writer, Brainwork**

## जॉब/करियर न्यूज

- पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से जूनियर इंजीनियरों के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं।
  **कुल पद :** 544
  **अंतिम तिथि :** 1 मार्च 2024 तक।
  **आवेदन प्रक्रिया:** इच्छुक युवा आधिकारिक वेबसाइट **pspcl.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- साउदर्न रेलवे की ओर से अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
  **कुल पद :** 2860
  **अंतिम तिथि :** 28 फरवरी 2024
  **आवेदन प्रक्रिया :** आधिकारिक वेबसाइट **sr.indianrailways.gov.in** पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं व विस्तार से जानकारी ले सकते हैं।
- पंजाब नेशनल बैंक की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं।
  **कुल पद :** 1025
  **अंतिम तिथि :** 25 फरवरी तक आवेदन कर दें।
  **आवेदन प्रक्रिया :** विस्तार से जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट **pnbindia.in** देखें।
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं।
  **कुल पद :** 606
  **अंतिम तिथि :** 23 फरवरी 2024
  **आवेदन प्रक्रिया :** इच्छुक युवा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट **unionbankofindia.co.in** पर विस्तार से जानकारी देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- बिहार विधानसभा की ओर से असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट केयर टेकर, जूनियर क्लर्क, रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर आदि विविध पदों पर आवेदन आमंत्रित हुए हैं।
  **कुल पद :** 109
  **अंतिम तिथि :** 15 फरवरी 2024
  **आवेदन प्रक्रिया :** **vidhansabha.bih.nic.in** के होमपेज के रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करें और सामने आए रजिस्ट्रेशन पेज आने पर रजिस्टर करें।
- तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन ग्रुप 4 के पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का आयोजन जून में होगा।
  **कुल पद :** 6244
  **अंतिम तिथि :** 28 फरवरी 2024 तक।
  **आवेदन प्रक्रिया :** विस्तार से जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट **tnpsc.gov.in** देखें।
- झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से कॉन्स्टेबल पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा हेतु आवेदन प्रक्रिया की सूचना जारी हुई है।
  **कुल पद :** 4919
  **आवेदन की अंतिम तिथि:** आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2024 है।
  **आवेदन प्रक्रिया:** आधिकारिक वेबसाइट **jssc.nic.in** पर जाकर विस्तार से जानकारी लें व इसके माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
- झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की ओर से झारखंड पैरामेडिकल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2023 के लिए सूचना जारी हो गई है।
  **कुल पद :** 2485
  **अंतिम तिथि :** आवेदन प्रक्रिया 22 फरवरी 2024 को समाप्त होगी।
  **आवेदन प्रक्रिया :** आधिकारिक वेबसाइट **jssc.nic.in** से ज्यादा जानकारी ले सकते हैं।

## भेजें अपने सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें
**nayiraheincareer@gmail.com**

# बीसीए के लिए भी एआईसीटीई की मान्यता जरूरी

**एक्सपर्ट टिप्स**
**आशीष आदर्श**
करियर काउंसलर

- **मैं अभी गणित विषय के साथ 10+2 कर रही हूं और आगे बीसीए में दाखिला लेना चाहती हूं। कृपया पाठ्यक्रम को लेकर मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए, बताएं।**
  **सीमा यादव**

किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए कि उस पाठ्यक्रम को चलाने के लिए केवल विश्वविद्यालय की मान्यता आवश्यक है या किसी एपेक्स बॉडी की भी। एपेक्स बॉडी भारत सरकार की अलग-अलग संस्थाएं होती हैं, जिन्हें देश में अलग-अलग पाठ्यक्रमों के लिए मान्यता देने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, बीएड के लिए एपेक्स बॉडी है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, लॉ के लिए है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसी प्रकार बीसीए यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे वोकेशनल पाठ्यक्रम की मान्यता के संदर्भ में इस वर्ष से कुछ नए बदलाव हो रहे हैं। भारत सरकार की संस्था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई द्वारा इस सत्र से बीसीए एवं बीबीए (बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) जैसे पाठ्यक्रमों के लिए भी मान्यता अनिवार्य कर दी गई है। इसके बाद अब देश में किसी भी संस्थान को बीसीए, बीबीए पाठ्यक्रम चलाने के लिए एआईसीटीई की मान्यता लेनी होगी। अब तक यह केवल बीटेक, एमबीए, एमसीए, डिजाइन, आर्ट एंड क्राफ्ट एवं तकनीकी डिप्लोमा जैसे पाठ्यक्रमों तक सीमित थी। कुछ वर्ष पहले तक एआईसीटीई की परिधि में बीफार्मा, बीआर्क जैसे पाठ्यक्रम भी थे, परंतु बाद में उन पाठ्यक्रमों के लिए अलग एपेक्स बॉडी की स्थापना कर दी गई। मसलन, बीफार्मा के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बन गयी और बीआर्क के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। अतः इस वर्ष से बीसीए में दाखिला लेने से पहले उस संस्थान की एआईसीटीई से मान्यता की जांच अवश्य कर लें।

- **मैं इस वर्ष मैट्रिक की परीक्षा दे रहा हूं और आगे किसी आईटीआई में दाखिला लेना चाहता हूं। मुझे मान्यता प्राप्त आईटीआई की जानकारी कैसे प्राप्त हो सकती है?**
  **मो. इरफान अंसारी**

देश में लगभग प्रत्येक राज्यों में सरकारी व निजी आईटीआई यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, जो विभिन्न ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। इन संस्थानों को एनसीवीईटी यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। एनसीवीईटी भारत सरकार के स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रिन्योरशिप मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। आप अपने नजदीकी मान्यता प्राप्त आईटीआई संस्थान की खोज मंत्रालय की वेबसाइट **www.ncvtmis.gov.in** से कर सकते हैं।

# आगे रहना चाहते हैं, तो अपनाएं ये आदतें

**जॉब टिप्स**

**अगर आप अपने ऑफिस में ऊंचे पद तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको खुद में लीडरशिप के गुण विकसित करने होंगे और जताने भी होंगे। यहां जानिए कुछ सलाहें, जो इसमें करेंगी मदद**

**जब** आप खुद में नेतृत्व क्षमता के गुण विकसित करते हैं, तो वरिष्ठ पदों पर पहुंचने में देर नहीं लगती। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी वर्तमान भूमिका पर ध्यान देना बंद कर दें। दरअसल अपनी वर्तमान भूमिका में अच्छा कार्यप्रदर्शन लीडरशिप की नीव रखता है। यहां जानिए कुछ और गुण, जो विकसित करना आपको आगे के पदों पर ले जाएगा:

**92%**
उच्च कार्य प्रदर्शन करने वाले टीम लीडर्स में पहल करने का गुण पाया गया, एक सर्वे में

**छोटी अवधि के लक्ष्य बनाएं :** जब आपको पता होगा कि आपका अगला लक्ष्य क्या है, तो आप अपने संसाधनों, कौशलों और क्षमताओं का बेहतर उपयोग करके उस ओर बढ़ेंगे। इस प्रक्रिया में आपके नाम कई उपलब्धियां भी होंगी। जैसे कई स्किल्स सीख सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर अनुभव बटोर सकते हैं।

**सक्रिय श्रोता बनें :** यह स्किल आपके वर्तमान साथियों के साथ आपके संवाद को स्पष्ट और अच्छे तालमेल के साथ स्थापित करता है।

**दूसरों के लिए प्रेरणा बनें:** जब आप नए स्किल्स और जानकारी से लैस होंगे, तो आप अपनी टीम को प्रेरित करने में समर्थ होंगे। इस तरह ना सिर्फ आप उनके लिए अगुवा बने रहेंगे, बल्कि एक सक्षम टीम के साथ आप बेहतर कार्य प्रदर्शन का रिकॉर्ड बनाते हैं।

**नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनें :** ऑफिस में आने वाले नए प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने पर आपके कार्य अनुभव का दायरा बढ़ता है। यह आपको बढ़त देता है साथ ही आप अधिकारियों की निगाह में भी आते हैं।

**फीडबैक लें :** अपने बारे में अपने मैनेजर और साथियों से समय-समय पर फीडबैक लेना आपको काम और सॉफ्ट स्किल सुधारने में भी मदद करेगा।

**मेंटर की मदद लें :** कोच या मेंटर से आपको नए स्किल्स, आपके स्किल्स को देखते हुए बेहतर जॉब रोल आदि की सलाहें मिल सकती हैं।

लक्ष्य की ओर बढ़ने में अपना रिव्यू खुद करना बेहद जरूरी है, ताकि समय रहते उनमें सुधार कर सकें। **रिया शर्मा**

# रोजनामचा

**पं. राघवेन्द्र शर्मा**
ज्योतिषाचार्य

**मेष :** पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार के लाभ में वृद्धि।

**वृष :** कारोबार में वृद्धि होगी। परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं।

**मिथुन :** मन प्रसन्न रहेगा। परंतु आत्मविश्वास में कमी हो सकती है। कारोबार के लिए किसी दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

**कर्क :** आत्मसंयत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। यात्रा पर भी जा सकते हैं। किसी मित्र का साथ मिल सकता है। मित्र के सहयोग से धन प्राप्ति संभव।

**सिंह :** मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। शैक्षिक कार्यों में सफल रहेंगे। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

**कन्या :** कारोबारी कार्यों में मन लगेगा। कारोबार के लिए किसी मित्र के साथ यात्रा पर जाना हो सकता है। यात्रा लाभप्रद रहेगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है।

**तुला :** मन प्रसन्न रहेगा। भवन सुख में वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाकर रखें। तरक्की के अवसर मिलेंगे।

**वृश्चिक :** वाणी में सौम्यता रहेगी। कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। कार्यक्षेत्र में वृद्धि होगी। किसी मित्र का सहयोग मिलेगा।

**धनु :** प्रसन्नता रहेगी। वस्त्रों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। लेखनादि बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति होगी।

**मकर :** मन अशांत रहेगा। संयत रहें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। वस्त्रों और वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग।

**कुंभ :** मन प्रसन्न रहेगा। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भवन के रखरखाव पर खर्च बढ़ेंगे।

**मीन :** मन अशांत रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। कारोबार से लाभ में वृद्धि होगी। किसी पैतृक संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

**स्कैन करें**
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

## व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

08 फरवरी, गुरुवार, 19 माघ (सौर) शक संवत् 1945, 26 माघ मास प्रविष्टे (पंजाब पंचांग) 2080, 27, रज्जब सन् 1445, माघ कृष्ण त्रयोदशी (विक्रमी संवत्) प्रात: 11.18 बजे तक पश्चात चतुर्दशी, सिद्धि योग रात्रि 11.09 बजे तक, वणिज करण, चन्द्रमा धनु राशि में प्रात: 10.04 बजे तक उपरांत मकर राशि में। **सूर्य उत्तरायण।** सूर्य दक्षिण गोल। शरद् ऋतु। दोपहर 01.30 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक राहुकालम्। भद्रा प्रात: 11.18 मिनट से रात्रि 09.41 मिनट तक। मेरू त्रयोदशी (जैन)। मासशिवरात्रि व्रत।

## वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

**मुझे मेरे परिवार में कोई कुछ समझता नहीं है। मैं घर में सिर्फ एक कमरे में रहता हूं। क्या वास्तु मेरी कुछ मदद कर सकता है।** – हिमांशु, शिमला

- आप अपने कमरे के अग्नि कोण में प्रेरणात्मक वाक्य लगाएं।
- नहाने के पानी में कॉफी एवं सेंधा नमक मिलाकर नहाएं।
- दक्षिण, दक्षिण पूर्व में थोड़ी देर अवश्य बैठें। अपने सिर के पीछे पहाड़ का चित्र लगाएं। दक्षिण दिशा में एक हनुमान जी का चित्र लगाएं।
- अपने बेड के सिरहाने के पास 11 मोरपंख रखें। बेड को दक्षिणी दीवार पर लगाएं। नित्य सूर्य देव की पूजा करें।

## वर्ग पहेली : 7507

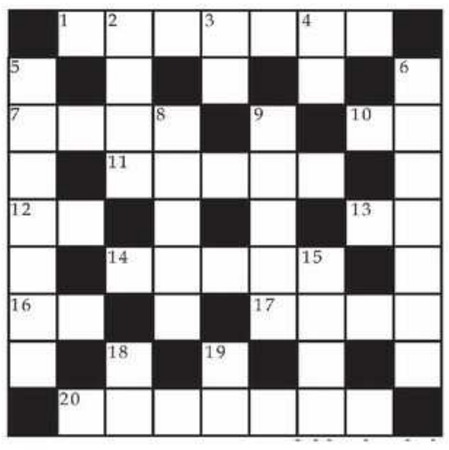

**बाएं से दाएं**

1. पछाड़ना; हराना; कुश्ती में चित कर देना (4,3)
7. बोधिवृक्ष; भृंगी; यक्षावास; वट (4)
10. चक्र; रथ का पहिया; शत्रु (2)
11. दूसरे के सिर पर दोष मढ़ना; हस्तांतरण करना (2,3)
12. बालक; बेटा; पुत्र; अनुभवहीन; नादान (2)
13. श्वास का रोग (2)
14. बड़ा काम करना; युक्ति युक्त कार्य करना; चोट मारना (2,3)
16. कन; टुकड़ा; दाना; सूजी (2)
17. जिसका नाम आदर से लिया जाता हो; अति प्रसिद्ध; नामवर; प्रसिद्ध (4)
20. युद्ध की योजना बनाना; रण की नीति बनाना (4,3)

**ऊपर से नीचे**

2. अगुआ; नेता; मुखिया; सरदार (4)
3. पर्वत; नगीना; मणि; रत्न; अदद (2)
4. अपनी रक्षा करने और शत्रु पर आक्रमण करने के लिए खोदा जाने वाला गड्ढा; खंदक (2)
5. टालते चलना; हीला हवाला करना (2,2,3)
6. चक्कर लगाना; चारों ओर घूमना (4,3)
8. कश लगाना; थकावट दूर होने पर थोड़ी देर रुकना; सुस्ताना (2,3)
9. आक्रमण करना; प्रहार करना; मारना (2,3)
15. अपनाना; मंत्र देना; नामकरण करना (2,2)
18. तीर; शर (2)
19. आचार व्यवहार; व्यवहार का ढंग; कार्यविधि; कार्यपद्धति; योजना (2)

**हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली**
(उत्तर अगले अंक में)

## वर्ग पहेली 7506 का उत्तर

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 म | ह | 2 ल | ब | 3 ना | ना | ■ | 4 अ | ■ |
| न्न | ■ | गा | ■ | क | ■ | 5 म | दा | री |
| 6 त | ना | व | का | र | क | ■ | का | ■ |
| मा | ■ | र | ■ | ना | ■ | 7 च | र | 8 म |
| न | ■ | 9 ख | रा | ■ | 10 ल | ट | ■ | द |
| 11 ना | 12 च | ना | ■ | 13 द | ■ | क | ■ | द |
| ■ | म | ■ | 14 स | म | सा | म | यि | क |
| 15 चू | क | ना | ■ | क | ■ | ट | ■ | र |
| ■ | ना | ■ | 16 ला | ल | च | क | र | ना |

## सुडोकू : 7491

* कठिन

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | | | 9 | | | | |
| | | | 6 | | 8 | | | |
| | | | | | 3 | | 5 | 1 |
| | | 4 | | | 1 | 2 | | |
| 1 | 6 | | | | | | 7 | 5 |
| | | 9 | 5 | | | 3 | | |
| 4 | 8 | | 7 | | | | | |
| | | | 2 | | 6 | | | |
| | | | | 8 | | | | 3 |

**खेलने का तरीका :** दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

## हल : सुडोकू नं.7490

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 2 |
| 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 8 | 9 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 8 | 1 | 9 |

**कल्पमेधा**

*हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है, जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं, जो मायने रखते हैं।*

*– मार्टिन लूथर किंग जूनियर*

## संबंधों में मर्यादा

सहजीवन यानी बिना विवाह के युवा जोड़ों के साथ रहने पर लंबे समय से बहस होती रही है। समाज का एक बड़ा हिस्सा इसे अनुचित मानता है। मगर निजता के संवैधानिक अधिकारों के चलते इस पर कोई कानूनी अंकुश लगाना संभव नहीं है। अब उत्तराखंड सरकार ने सहजीवन को अवैध तो करार नहीं दिया है, पर मर्यादित करने का प्रयास जरूर किया है। समान नागरिक संहिता विधेयक में उसने एक प्रावधान सहजीवन को लेकर भी शामिल किया है। उसके तहत कोई भी प्रेमी युगल अगर सहजीवन में रहता या रहना चाहता है, तो उसे पहले क्षेत्रीय पंजीयक के पास पंजीकरण कराना होगा। अगर उन दोनों में से किसी की उम्र इक्कीस वर्ष से कम है, तो पंजीयक उसके माता-पिता को भी इस संबंध में सूचना देगा। उनकी मंजूरी के बाद ही संबंधित जोड़े के सहजीवन में रहने का पंजीकरण हो सकता है। अगर कोई जोड़ा पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे तीन महीने की कैद या दस हजार रुपए जुर्माने का दंड या दोनों भोगना पड़ सकता है। इसे लेकर विपक्षी दल स्वाभाविक रूप से एतराज जता रहे हैं। वे इस प्रावधान पर कुछ ठहर कर विचार करने की मांग कर रहे हैं।

सहजीवन को मर्यादित बनाने के पीछे सरकार की मंशा समझी जा सकती है। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में बिना विवाह के साथ रह रहे प्रेमी युगल के बीच अनबन और विच्छेद की अनेक ऐसी अप्रिय घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे निपटना प्रशासन के लिए मुश्किल साबित हुआ। कई लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। बहुत-सी लड़कियां सहजीवन में रहने के बाद ठगी महसूस करती हैं। ऐसे मामलों में घरेलू हिंसा, संपत्ति का अधिकार, भरण-पोषण के दावे आदि के कानूनी प्रावधान लागू नहीं होते। इसलिए ऐसे अनेक मामलों में अदालत में गुहार लगाने के बाद भी लड़कियों को न्याय नहीं मिल सका है। उत्तराखंड सरकार इन्हीं समस्याओं से पार पाने के इरादे से यह कानून लागू करना चाहती है। सहजीवन संबंधी प्रावधान में स्पष्ट उल्लेख है कि पंजीकरण के बाद साथ रहने वाले प्रेमी युगल के संबंधों को कानूनी रूप से वैध माना जाएगा और महिला को वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे, जो विवाह के बाद प्राप्त होते हैं। उनसे पैदा हुए बच्चे को उत्तराधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। अगर लड़का किन्हीं स्थितियों में लड़की को छोड़ देता है, तो लड़की उससे भरण-पोषण पाने की हकदार होगी।

एक तरह से यह कानून सहजीवन को कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। कई बार कुछ जोड़े तय कर चुके होते हैं कि वे विवाह करेंगे, इसके लिए उनके परिवार वालों की भी मंजूरी होती है, मगर पढ़ाई-लिखाई, रोजगार आदि की विवशताओं के चलते वे विवाह को टाल देते हैं। विवाह से पहले साथ रहने लगते हैं। ऐसे जोड़ों को पंजीकरण से शायद ही कोई दिक्कत हो। मगर जो युवा चोरी-छिपे, बस शारीरिक सुख के लिए साथ रहने लगते हैं, उनमें विवाद की गुंजाइश सदा बनी रहती है। ऐसे ही जोड़ों को मर्यादित करने के लिए ऐसे कानून की जरूरत महसूस की गई होगी। मगर निजता के समर्थक कुछ लोगों को यह कानून नैतिक निगरानी रखने का प्रयास लग सकता है। निजता के अधिकार की रक्षा अवश्य होनी चाहिए, मगर इस अधिकार की आड़ में या इसका बेजा फायदा उठाते हुए अगर कुछ लोग समाज और व्यवस्था के सामने मुश्किलें पैदा करते हों, तो उन्हें अनुशासित करने की जिम्मेदारी से भला कोई राज्य कैसे बच सकता है।

## जानलेवा जगहें

पटाखा निर्माण सदा जोखिमभरा काम होता है। ऐसी जगहों पर काम करने वालों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की दरकार होती है। मगर हमारे यहां अधिकतर पटाखा कारखाने अव्वल तो अवैध रूप से चलाए जाते हैं और जो पंजीकृत हैं, उनमें भी सुरक्षा के भरोसेमंद उपाय नहीं किए जाते। यही वजह है कि छोटी-सी चिनगारी भी उन जगहों पर बड़े हादसे का रूप ले लेती है। मध्यप्रदेश के हरदा में पटाखा कारखाने में लगी आग इसका ताजा उदाहरण है। इस घटना में ग्यारह लोगों की मौत हो गई और एक सौ चौहत्तर लोग घायल हो गए। सरकार ने घायलों के इलाज का प्रबंध कराया और मृतकों के परिजनों को मुआवजे की घोषणा करके जांच का आदेश दे दिया, जैसा कि ऐसे हर हादसे के वक्त देखा जाता है। मगर यह सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि पटाखा कारखानों में होने वाले ऐसे हादसों को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम कब होंगे। पहले दिवाली के समय किसी लापरवाही के चलते ऐसे हादसे हो जाया करते थे, अब साल भर ऐसी घटनाओं की खबरें आती हैं।

दरअसल, पटाखा बनाने का कारोबार काफी बड़े पैमाने पर होने लगा है, इसलिए कि इसकी खपत वर्ष भर बनी रहती है। शादी-ब्याह से लेकर अनेक पर्व-त्योहारों, क्रिकेट आदि के खेलों के समय भी पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी का चलन बढ़ता गया है। पहले कुछ जगहों पर पटाखे बनते थे, जहां से पूरे देश में उनका वितरण हुआ करता था, अब हर राज्य में पटाखों के कारखाने खुल गए हैं। पिछले वर्ष बिहार में पटाखा कारखाने में भयावह विस्फोट हुआ था, जिससे आसपास के मकान भी ढह गए। वह कारखाना थाने से सटी जगह पर अवैध रूप से चलाया जा रहा था। कायदे से पटाखे बनाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है, मगर ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि चोरी-छिपे पटाखे बनाए जाते हैं। उनके लिए इतने बड़े पैमाने पर बारूद और दूसरी सामग्री किस प्रकार उपलब्ध होती है, इस पर शायद नजर नहीं रखी जाती। दिवाली के मौके पर पटाखे से फैलने वाले प्रदूषण को लेकर चिंता जताई जाती है, मगर बाकी समय इसे लेकर प्रायः चुप्पी ही बनी रहती है। जब तक पटाखा निर्माण को लेकर कोई व्यावहारिक उपाय नहीं किया जाता, ऐसे हादसों पर अंकुश लगाना कठिन बना रहेगा।

# हरित इस्पात से पर्यावरण सुरक्षा

**दुनिया भर में इस्पात उद्यमियों को पर्यावरण तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नए हरित इस्पात उत्पादन की अवधारणा ने जन्म लिया है।**

**रामानुज पाठक**

भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्पात प्रमुख क्षेत्रों में से एक है। वित्तवर्ष 2021-22 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में इस्पात उद्योग की भागीदारी दो फीसद रही। भारत वर्तमान में कच्चे इस्पात का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, जहां मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तवर्ष के दौरान बारह सौ लाख टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। देश में इसका अस्सी फीसद से अधिक भंडार ओड़िशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में है। वर्ष 2021 में भारत तैयार इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता (106.23 मीट्रिक टन) रहा। विश्व इस्पात संगठन के अनुसार, चीन सबसे बड़ा इस्पात उपभोक्ता है।

इस्पात को पुनर्चक्रित किया जा सकता है। भूगर्भ में 5.6 फीसद लौह तत्त्व विद्यमान है, इसलिए इसके कच्चे माल का आधार भी मजबूत है। इस्पात का उत्पादन अन्य सभी अलौह पदार्थों के कुल उत्पादन से बीस गुना अधिक है। सब मिलाकर इस्पात की लगभग दो हजार किस्मों का विकास हुआ है, जिसमें डेढ़ हजार प्रकार के इस्पात उच्च श्रेणी के हैं। अभी विभिन्न प्रकार के गुणधर्म वाले इस्पात की नई श्रेणियों के विकास की असीम संभावनाएं हैं। इस्पात एक महान सहयोगी है, जो वृद्धि और विकास को आगे बढ़ाने के लिए अन्य सभी चीजों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था को एक स्वस्थ इस्पात उद्योग की आवश्यकता होती है, जो रोजगार प्रदान करे और विकास को आगे बढ़ाए। प्रति व्यक्ति औसत विश्व इस्पात उपयोग 2001 में 150 किलोग्राम से लगातार बढ़ कर 2020 में लगभग 230 किलोग्राम तक पहुंच चुका है, जिससे दुनिया अधिक समृद्ध हुई है।

इस्पात का उपयोग हर महत्त्वपूर्ण उद्योग में किया जाता है; ऊर्जा, निर्माण, वाहन निर्माण और परिवहन, बुनियादी ढांचा, पैकेजिंग और मशीनरी। 2050 तक हमारी बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस्पात का उपयोग वर्तमान स्तर की तुलना में लगभग बीस फीसद बढ़ने का अनुमान है। आवास और निर्माण क्षेत्र आज इस्पात का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो उत्पादित इस्पात का पचास फीसद से अधिक उपयोग करता है। विश्व स्तर पर, साठ लाख से अधिक लोग इस्पात उद्योग के लिए काम करते हैं। हमने इस्पात उत्पादन तकनीक में उस स्तर तक सुधार किया है, जहां विज्ञान की सीमाएं ही हमारी क्षमता को सीमित करती हैं। हमें इन सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

चूंकि दुनिया अपनी पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान ढूंढ़ रही है, यह इस्पात पर भी निर्भर है। इस्पात उद्योग में उपयोग होने वाले लगभग नब्बे फीसद पानी को साफ, ठंडा किया जाता और स्रोत में वापस कर दिया जाता है। पिछले पचास वर्षों में एक टन इस्पात का उत्पादन करने के लिए उपयोग की जाने वाली ऊर्जा में लगभग साठ फीसद की कमी आई है। इस्पात दुनिया में सबसे अधिक पुनर्नवीकृत सामग्री है, 2021 में लगभग 6800 लाख टन का पुनर्चक्रण किया गया।

बावजूद इन सबके कार्बन डाइआक्साइड के उत्पादन में इस्पात उद्योग तीन सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। इस्पात निर्माण किसी भी अन्य भारी उद्योग की तुलना में अधिक कार्बन डाइआक्साइड का उत्सर्जन करता है, जिसमें कुल

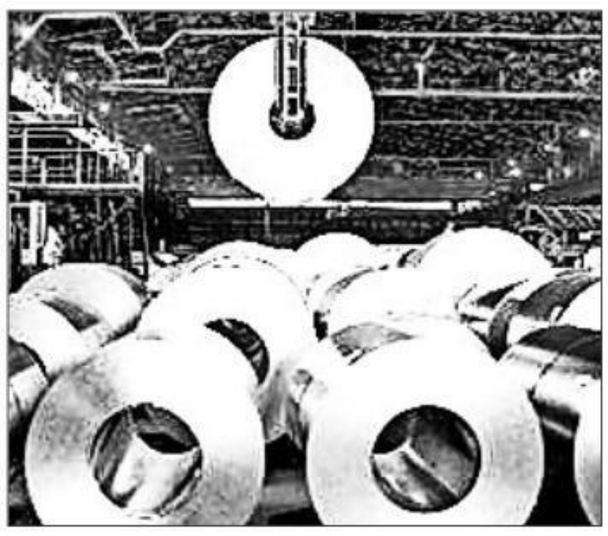

वैश्विक उत्सर्जन का लगभग आठ फीसद शामिल है। नतीजतन, दुनिया भर में इस्पात उद्यमियों को पर्यावरण तथा आर्थिक दोनों दृष्टियों से अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में नए हरित इस्पात उत्पादन की अवधारणा ने जन्म लिया है। हरित इस्पात का आशय जीवाश्म ईंधन के उपयोग के बिना इस्पात के निर्माण से है। इसमें कोयले से चलने वाले संयंत्रों के पारंपरिक कार्बन-गहन निर्माण के बजाय नवीकरणीय या निम्न कार्बन ऊर्जा स्रोतों, जैसे हाइड्रोजन गैस या बिजली का उपयोग कर इस्पात का निर्माण करना है। अधिक स्वच्छ विकल्पों के साथ प्राथमिक उत्पादन प्रक्रियाओं को प्रतिस्थापित करना कम कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का प्रयोग, लौह अयस्क के विद्युत अपघटन के माध्यम से प्रत्यक्ष विद्युतीकरण हरित इस्पात उत्पादन के अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सीओपी-26 में की गई प्रतिबद्धताओं के तहत भारतीय इस्पात उद्योग को वर्ष 2030 तक अपने उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है।

> **अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने हेतु अधोसंरचना का विकास अति-आवश्यक है। इसलिए इस्पात उद्योग का विकास अपरिहार्य है। इस्पात बनाने में पचास फीसद कबाड़ उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका कारण है कि कबाड़ और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु के विनिर्माण में प्रदूषण कम फैलता है। यह हरित इस्पात निर्माण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार कबाड़ का उपयोग न केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम, बल्कि इस्पात विनिर्माण में कार्बन उत्सर्जन में पच्चीस फीसद की कटौती करता है।**

वैसे भी यूरोपीय संघ एक जनवरी, 2026 से इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, उर्वरक, हाइड्रोजन और विद्युत की प्रत्येक खेप पर कार्बन कर (कार्बन सीमा समायोजन तंत्र) एकत्र करना शुरू कर देगा। यह भारत द्वारा यूरोपीय संघ को लौह, इस्पात तथा एल्यूमीनियम उत्पादों, जैसे धातुओं के निर्यात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा, क्योंकि इन्हें इन उत्पादों को यूरोपीय संघ के 'सीबीएएम' तंत्र के तहत अतिरिक्त जांच प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। सीबीएएम, 'फिट फार 55 इन 2030 पैकेज' का हिस्सा है। यह यूरोपीय संघ की एक योजना है, जिसका उद्देश्य यूरोपीय जलवायु कानून के अनुरूप वर्ष 1990 के स्तर की तुलना में वर्ष 2030 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को लगभग 55 फीसद तक कम करना है।

हरित इस्पात उद्योग के लिए कई सरकारी पहलें की गई हैं जैसे, राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी) 2017, इस्पात कबाड़ पुनर्चक्रण नीति, चौथी औद्योगिक क्रांति को अपनाना (उद्योग 4.0), भारत का इस्पात अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मिशन, ड्राफ्ट फ्रेमवर्क नीति, विशेष इस्पात के लिए पीएलआइ योजना, सम्मलित हैं। मगर भारत ऐतिहासिक रूप से इस्पात क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास में निवेश करने में पीछे रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे अतिरिक्त लागत में वृद्धि होती है। पुरानी तथा प्रदूषणकारी प्रौद्योगिकियां इस क्षेत्र को कम आकर्षक बनाती हैं। आधुनिक इस्पात निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए निवेश एक बड़ी बाधा है।

कम मांग की अवधि के दौरान इस्पात संयंत्रों की आय और लाभ न्यूनतम हो जाते हैं, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ता है। कई मामलों में विनिर्माण कार्य बंद और स्थगित भी करना पड़ता है। इन सब अवरोधों के बाद भी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने हेतु अधोसंरचना का विकास अति-आवश्यक है। इसलिए इस्पात उद्योग का विकास अपरिहार्य है। इस्पात बनाने में पचास फीसद कबाड़ उपयोग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसका कारण है कि कबाड़ और अन्य अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से धातु के विनिर्माण से प्रदूषण कम फैलता है। यह हरित इस्पात पहल की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम होगा। विशेषज्ञों के अनुसार कबाड़ का उपयोग न केवल प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को कम, बल्कि इस्पात विनिर्माण में कार्बन उत्सर्जन में पच्चीस फीसद की कटौती करता है।

कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हरित इस्पात का उत्पादन करने के लिए भविष्य में अधिक कबाड़ की आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्यावरण अनुकूल औपचारिक कबाड़ केंद्रों की जरूरत होगी। आज देश में लगभग 2.5 करोड़ टन कबाड़ का उत्पादन होता है और लगभग पचास लाख टन का आयात किया जाता है। आगे हरित इस्पात उत्पादन में देशी कबाड़ का सौ फीसद उपयोग किए जाने की संभावना है।

# चिट्ठी आई है

**बुलाकी शर्मा**

बड़े दिनों के बाद चिट्ठियों की स्मृतियों को संजोने वाला एक मर्मस्पर्शी गीत सुनते हुए मेरा मन भी बड़े दिनों के बाद चिट्ठी-पत्री की दुनिया की यायावरी करने लगा।

संचार-क्रांति के जमाने से पहले चिट्ठी-पत्री की दुनिया बहुत समृद्ध थी। चिट्ठी-पत्री के माध्यम से ही हमें दूर बैठे अपने परिजनों-मित्रों-शुभचिंतकों के सुख-दुख के समाचार मिला करते थे। तब फोन की सुविधा भी अति-संपन्न लोगों के घरों में ही हुआ करती थी। हम सभी को डाकिये का इंतजार रहता। डाकिया आएगा, संदेशा लाएगा। नव-विवाहिताएं दूर-दिसावर में बैठे अपने 'पीवजी' के राजी-खुशी के समाचार जानने की उत्कंठा में घर के मुख्य द्वार पर कान लगाए रहतीं कि कब डाकिये की पुकार सुनाई दे जाए। वृद्ध मां-बाप अपने कमाऊ बेटे के राजी-खुशी के समाचारों के साथ मनीआर्डर की आस में डाकिये का इंतजार करते रहते। हारी-बीमारी की स्थिति में सैकड़ों कोस दूर कमाने गए अपने बेटे को जल्दी घर आने की चिट्ठी लिखते, तब यह जरूर लिखते कि 'इस चिट्ठी को तार मानते हुए तुरंत पहली गाड़ी से रवाना हो जाना।'

चिट्ठी-पत्री के जमाने में किसी पोस्टकार्ड का कोना किसी की गलती से भी फट जाता तो उसे किसी की मृत्यु का शोक समाचार जान लोग आशंकित हो जाते, क्योंकि तब पोस्टकार्ड का एक कोना फाड़कर शोक समाचार भेजने की प्रथा थी। किसी के घर 'तार' आने पर तो एकबारगी पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाता कि कहीं कोई अनहोनी खबर न हो। तब भयभीत करने वाले ऐसे 'भक्तों' के बेनामी पोस्टकार्ड भी महीने-दो महीने में आ जाया करते थे, जिनमें किसी देवी-देवता के चमत्कारों का हवाला देते हुए ऐसे ही ग्यारह या इक्कीस पोस्टकार्ड अन्य लोगों को भेजने की हिदायत होती और यह धमकी भी कि अगर ऐसा नहीं किया तो घर-परिवार में जान-माल की हानि हो सकती है, व्यापार चौपट हो सकता है। धर्म भीरु लोग ऐसी हिदायतों से डरकर पोस्ट कार्ड लिखते भी थे।

लेखकों की जमात तो अपने हलके के डाकिये से मित्रवत व्यवहार रखा करती थी। उन्हें अपनी रचनाओं की स्वीकृति की प्रतीक्षा लगी रहती थी। स्वीकृति-पत्र मिलने पर वे दिनों तक अपने लेखक-मित्रों को दिखाते हुए स्वयं गर्वित होते और उन्हें दुखी करते। पत्र-पत्रिकाओं में जब कोई रचना अस्वीकृत होकर लौटती थी, तब एक पर्ची नत्थी हुआ करती थी कि हम इस रचना का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेखकों को सुझाव भी दिए जाते थे। तब लेखकों के बीच भी चिट्ठी-पत्री के माध्यम से स्वस्थ संवाद बना रहता था। उन पत्रों में औपचारिकता नहीं, आत्मीय भाव होता था। उनमें घर-परिवार की बातें भी साझा की जातीं और वैचारिक मुद्दों पर चर्चाएं भी रहतीं। उन हस्तलिखित पत्रों को बार-बार पढ़ने की ललक मन में बसी रहती है। आज भी कई मशहूर साहित्यकारों और विभूतियों से प्राप्त पत्रों को पढ़ते हुए साहित्य-प्रेमी नव-लेखकों और अन्य लोगों के बीच ऊर्जा और ऊष्मा का संचार हो जाता है। साहित्यकारों के पत्रों से हमें उनकी मनःस्थिति का भी पता चलता है, हम उनके भावों-विचारों के साथ उनके व्यक्तित्व से भी परिचित होते हैं।

दरअसल, पत्र-साहित्य हमारी साहित्यिक धरोहर है। अन्य भाषाओं के साथ हिंदी के कई दिग्गज साहित्यकारों की चिट्ठियां तत्कालीन समय और समाज से हमारा साक्षात कराते हुए आपसी रिश्तों की खुशबू से हमें महकाती हैं। कई स्वनामधन्य साहित्यों और विचारों के बीच हुए पत्र-व्यवहार और चिट्ठियों के जरिए हुई बहसों को कई संग्रहों के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत कर हमें अहसास कराया गया है कि तब लेखकों के मध्य कितने जीवंत रिश्ते हुआ करते थे।

अब आपसी संवाद का माध्यम चिट्ठी-पत्री की जगह वाट्सएप, मैसेंजर, ई-मेल आदि ने ले लिया है। देश-विदेश में कहीं भी बैठे किसी भी व्यक्ति से संचार माध्यमों के जरिए तत्काल संवाद की सुविधा जरूर हो गई है, लेकिन इस संवाद में आमतौर पर औपचारिकता का भाव अधिक रहता है, आत्मीय आनंद की अनुभूति कम हो पाती है। हस्त लिखित चिट्ठियां पढ़ते हुए वे बोलती हुई-सी लगती थीं। तब पत्रों में मेहनत से शब्दों को सजा कर लिखा जाता था और वह लिखावट सम्मोहित करती थी। अब वैसा आनंद कहां! पत्र-पत्रिकाओं द्वारा लेखकों को डाक से मानदेय भेजने की परंपरा लुप्तप्रायः हो गई है, फिर भी कहीं रचना प्रकाशित होने पर मानदेय दिया जाता है, तो वह बैंक खाते में सीधे ही जमा हो जाता है। निश्चित तौर पर यह आज की सुविधा है, जो पारिश्रमिक देने और लेने वाले के लिए आसान लगती है और अब लोग इसे लेकर सहज हो रहे हैं। मगर पहले जब चिट्ठी के साथ चेक मिला करता था, तब लेखक रोमांचित होकर चेक को निरखा करता था। अब वैसे रोमांचक पल दुर्लभ होते जा रहे हैं।

आधुनिक और तेजरफ्तार जिंदगी में कागज पर हाथ से लिखी गई चिट्ठियों की स्मृतियों को आज एक पुरानी पड़ चुकी भावनाओं के तौर पर देखा जा सकता है, मगर यह भी याद रखने की जरूरत है कि यहां तक आने का रास्ता हमारा वही रहा है। आखिर क्यों ऐसा है कि संचार क्रांति के आधुनिक संसाधनों में डूबे हम मनुष्यों के भीतर से संवेदना का तत्त्व गौण होता दिखता है? हम खुश और दुखी तो होते हैं, मगर उतनी ही तेजी से उथल-पुथल के दौर से भी गुजरने लगते हैं। इस तरह की अस्थिरता की वजह क्या है, इसका सिरा कहां जुड़ा हो सकता है?

पहले रोज चिट्ठियां आती थीं, अब तो बड़े दिनों के बाद भी चिट्ठी नहीं आती, उन दिनों की याद जरूर आती रहती है।

## दुनिया मेरे आगे

> **कभी भी किसी ईमानदार आदमी को अपने स्वभाव और काम का प्रचार नहीं करना पड़ता। उसकी प्रशंसा अपने आप फैलती रहती है और लोग उसकी कद्र करते हैं। ईमानदार इंसान आसानी से लोगों का भरोसा जीत लेता है।**

## चौपाल

### चिंता से आगे

बच्चों की आत्महत्या की घटनाएं विकसित समाजों में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारे समाज में इस चुनौती से निपटने के लिए उचित नैतिक समाजिक जागरूकता पर ध्यान देने का समय आ गया है। आत्महत्या करने वाले बच्चों की चिह्नित कमजोरियों को समझने के लिए हमें यह योजना बनानी चाहिए कि कैसे हम समाज में इस बदलते परिप्रेक्ष्य का सामना कर सकते हैं। सामाजिक दबाव, परिवार से आते तनाव और शिक्षा में दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए उत्तरदाताओं को समझना होगा। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को सही दिशा में बदलने के लिए एक सशक्त समाजिक उपाय की आवश्यकता है। सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन की दिशा में हमें उच्चतम शिक्षा और अभिभावकों में संज्ञानपूर्ण परिवर्तनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को सफलता के मानक से बाहर देखने के लिए हमें उन्हें प्रोत्साहन और प्रेरणा देना चाहिए, ताकि वे अपने मूल्यों को महत्त्वपूर्ण मान सकें। हमें एक समाज में एक नया दृष्टिकोण प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें हम सभी बच्चों को उनकी विशेषता को समझने और उनका समर्थन करने के लिए उन्हें प्रेरित करते रहें।

*– अवनीश कुमार गुप्ता, आजमगढ़, उप्र*

### संयुक्त राष्ट्र की सीमा

सुरक्षा परिषद में समूचे विश्व का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने से संयुक्त राष्ट्र लगभग अप्रासंगिक बन गया है। केवल पांच महाशक्तियों के आगे विश्व का जनमत बेबस नजर आता है। ये महाशक्तियां अपना हित साधने के लिए संयुक्त राष्ट्र के फैसलों को प्रभावित करती हैं। वैश्विक शांति, आतंकवाद जैसी किसी भी समस्या के निपटारे में अपनी प्रभावी भूमिका न निभा पाना इस वैश्विक संस्था के महत्त्व को कम करता है। कैसी विडंबना है कि भारत अफ्रीकी संघ और अरब देश जैसे जनसंख्या बहुल और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले देश सुरक्षा परिषद जैसी नीति नियंता संस्था से बाहर हैं। सुरक्षा परिषद के चार सदस्यों सहित विश्व के अनेक देश और खुद महासचिव अंतोनियो गुतारेस जैसी वैश्विक हस्तियां भी भारत की दावेदारी का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन चीन की दुर्भावना और अड़ियल रुख के चलते यह संभव नहीं हो पा रहा है। पूर्व में कोरोना काल हो या वर्तमान में लाल सागर में असुक्षा से निपटने की समस्या, अन्य देशों की अपेक्षा भारत अग्रणी रहा है।

*– विमलेश पगारिया, बदनावर, मप्र*

### मतदाता के साथ

अवसरवादिता के इस युग में कुर्सी बचाने की खातिर थोक रूप में पार्टियों के सदस्य अपना दल बदल लेते हैं। यह प्रक्रिया किसी सिद्धांत या आस्था के कारण नहीं, बल्कि लालच, धन और सत्ता बचाने की खातिर होती है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटना इसी का एक उदाहरण है। इस क्रम में आम जनता ठगी जाती है, जिसने किसी पार्टी और उसके उम्मीदवार को किसी सिद्धांत के आधार पर वोट दिया होता है। देश के मतदाता जब तक अपने मताधिकार का महत्त्व नहीं समझेंगे और जागरूकता का परिचय नहीं देंगे, इस प्रकार की राजनीति पल्लवित और पोषित होती रहेगी। राजनेताओं का जनता के प्रति बढ़ता विश्वासघात लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं है।

*– ललित महालकरी, इंदौर*

### जलवायु में छीजन

मनुष्य को जीवन जीने के लिए संसाधन की आवश्यकता होती है, लेकिन उस संसाधन से होने वाले प्रदूषण ही पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। मानव अपने भौतिक सुख के लिए जल, जंगल, जमीन आदि को धीरे-धीरे उसके प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नदियों का पानी हो या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। उससे भी ऊपर जमीन पर बनने वाले कंक्रीट के जंगल आदि। आज जलवायु परिवर्तन के नाम पर बड़े-बड़े कार्यक्रम होते हैं, मगर उसका हासिल कुछ नहीं होता। जबकि पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन से परेशान है। सही समय पर बारिश का न होना, सही समय पर ठंड का न पड़ना एक चिंता का विषय है। यूरोप के कुछ देशों में ठंड न के बराबर है। भारत में भी ठंड तो पड़ी, लेकिन बर्फबारी न के बराबर हुई। इससे नदियों के लिए जलस्रोत पर गहरा असर पड़ेगा।

*– सचिन पांडेय, इलाहाबाद विवि*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

www.readwhere.com
Chandigarh

**तथ्य**

एक सर्वेक्षण के मुताबिक कनाडा में रहने वाले 18 फीसद गैर प्रवासी भारतीय (एनआरआइ) जोखिम लेने से नहीं चूकते हैं। वहीं, ब्रिटेन में रहने वाले 16 फीसद और सिंगापुर में रहने वाले 12 फीसद एनआरआइ ही जोखिम लेने को तैयार होते हैं।

**गृह विज्ञान के क्षेत्र में वेतन**

गृह विज्ञान में स्नातक करने के बाद नौकरी शुरू करने पर आप को दो से तीन लाख रुपए सालाना वेतन मिल सकता है। एक साल के अनुभव के बाद यह वेतन चार से पांच लाख रुपए तक हो सकता है। वहीं, शोध, शिक्षण या खान-पान क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का अच्छा खासा वेतन मिलता है।

*जानें-सीखें*

# 'कैनवा' से खोलिए नौकरी का दरवाजा

आज के डिजिटल युग में नौकरियों में और उनको पाने के लिए कौशल में तेजी से बदलाव आ रहा है। पहले जहां वीडियो संपादन या प्रकाशन जैसे के क्षेत्रों में जाने के लिए कई तरह के कोर्स करने, कई तरह के साफ्टवेयर और टूल सीखने होते थे। लेकिन एक-दो टूल के जरिए ही इन कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। बहुत से युवा 'कैनवा' जैसे टूल को सीखकर अच्छी खासी नौकरी भी कर रहे है।

कैनवा एक वेब-आधारित 'ग्राफिक डिजाइन टूल' है जो उपयोगकर्ताओं को सोशल मीडिया, पोस्टर जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए डिजाइन बनाने की सहूलियत देता है। सुविधाओं के एक विस्तृत भाग के साथ, कैनवा व्यवसायों, मार्केटर और डिजाइनरों के लिए समान रूप से एक जरूरी उपकरण है। कैनवा के जरिए आप यूट्यूब, सोशल मीडिया समेत बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिए डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं।

कैनवा की तरह ही 'ग्राफिक डिजाइन' के तमाम टूल आजकल युवाओं के लिए नौकरी का अवसर बन रहे हैं। कैनवा का उपयोगकर्ता के अनुकूल 'इंटरफेस' एक बड़ा कारण जो यह यह डिजाइनरों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। उपयोगकर्ता 'ड्रैग-एंड-ड्राप' सुविधा के साथ, तत्वों का चयन करके और उन्हें कैनवास में खींचकर आसानी से डिजाइन बना सकता है। कैनवा को इस तरह बनाया गया है कि उपयोगकर्ता को इसे उपयोग करने के लिए व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है।

कैनवा के पास डिजाइन के नमूनों की एक बड़ी लाइब्रेरी उपलब्ध है जिसे उपयोगकर्ता जल्दी से डिजाइन बनाने के लिए चुन सकते हैं। इन नमूनों को आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है। इन नमूनों को उपयोगकर्ता डिजाइन के हिसाब से बदल सकते हैं और उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित कर सकते हैं। इतना ही नहीं कैनवा के पास फोटो की भी एक बड़ी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी में लाखों उच्च-गुणवत्ता वाली तस्वीरें और चित्र हैं, जिससे उपयोगकर्ताओं को अपने डिजाइनों में उपयोग करने के लिए सही छवि खोजना आसान हो जाता है। कैनवा की सहयोगी डिजाइन सुविधा उपयोगकर्ताओं को किसी कार्य पर टीम के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है। यह सुविधा उन टीमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो दूरस्थ रूप से या विभिन्न स्थानों पर काम करती हैं। टीम के सदस्य एक साथ एक डिजाइन पर काम कर सकते हैं। कैनवा का मोबाइल एप एक अन्य उत्कृष्ट सुविधा है जो उपयोगकर्ताओं को चलते-फिरते डिजाइन बनाने की अनुमति देती है। एप के साथ, उपयोगकर्ता अपने डिजाइनों तक पहुंच सकते हैं और उन्हें कहीं से भी संपादित कर सकते हैं। इससे यह उन लोगों के लिए एक आदर्श उपकरण बन जाता है जो घर से काम करते हैं।

प्रस्तुति : युवा शक्ति डेस्क

# घर के अंदर भविष्य का द्वार

*विशेषज्ञ की कलम से*

गृह विज्ञान जैसा कि इसके नाम से पता चलता है 'घर का विज्ञान', जिसे अंग्रेजी में 'होम साइंस' कहते हैं। वर्तमान में यह विषय घर को सजाने और संवारने की कला मात्र तक सीमित नहीं है। गृह विज्ञान विषय असल में घर और अन्य संसाधनों के प्रबंधन की कला है। इसमें संसाधनों के प्रबंधन, परिवार के पोषण, मानव पर्यावरण, बाल विकास आदि की जानकारी दी जाती है। बारहवीं पास करने के बाद गृह विज्ञान छात्राओं के पसंदीदा पाठ्यक्रमों में से एक है। इस पाठ्यक्रमों को करने के लिए छात्राएं गृह विज्ञान के पांच प्रमुख धाराओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं।

**योग्यता और पाठ्यक्रम**

अगर आप 12वीं के बाद गृह विज्ञान में अपना करिअर बनाना चाहते हैं और बीएमसी करने की सोच रहे हैं, तो आपको भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में 50 फीसद अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा पास करनी होगी। कई ऐसे संस्थान हैं, जो गृह विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, शारीरिक विज्ञान में वोकेशनल पाठ्यक्रम करने वालों को भी दाखिला देते हैं। गृह विज्ञान से विद्यार्थी गृह विज्ञान में डिप्लोमा, बीएससी (गृह विज्ञान), बीएससी (आनर्स) गृह विज्ञान, बीएचएससी व बीएससी (आनर्स) खाद्य एवं पोषण, बीएससी (आनर्स) मानव विकास, एमएससी गृह विज्ञान, पीएचडी और पोस्ट डाक्टरेट पाठ्यक्रम कर सकते हैं। इसके अलावा गृह विज्ञान में स्नातक के बाद फैशन डिजाइनिंग, समाज कार्य, डाइटिटिक्स, परामर्श, विकास अध्ययन, आंत्रप्रन्यारशिप आदि विषयों में भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम किया जा सकता है।

**नौकरियां**

गृह विज्ञान के माध्यम से पढ़ाई करने के बाद छात्राएं नौकरी एवं स्वरोजगार दोनों ही प्रकार के अवसर प्राप्त कर सकती हैं। इन दोनों ही जगहों पर रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। क्योंकि वर्तमान में गृह विज्ञान सिर्फ कढ़ाई, बुनाई और भोजनकला (पाककला) के रूप तक ही सीमित नहीं रहा है। यह एक व्यापक विषय के रूप में दुनिया भर में फैल चुका है। हजारों छात्राएं बतौर विषय के रूप में इसे लेकर व्यापक स्तर पर इसमें शिक्षा ग्रहण कर चुकी हैं। गृह विज्ञान स्नातक के लिए सरकारी नौकरियों की कई संभावनाएं हैं। छात्राएं सरकारी शोध संस्थानों में शोध सहायक, खाद्य वैज्ञानिकों और प्रदर्शनकारियों के रूप में तकनीकी नौकरियां प्राप्त करते हैं। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र इस निम्न हैं:-

**उत्पादन** : इस क्षेत्र में खाद्य संरक्षण, खाना बनाना, परिधान बनाना आदि आते हैं तथा इसमें स्नातक छात्र होटल एवं खाद्य उद्योग, कपड़ा व्यापार के फैशन डिजाइनिंग में काम कर सकते हैं। इसके अलावा शोध के क्षेत्र में यहां से संबंधित प्रयोगशालाओं में शोधकर्ता, विज्ञानी के रूप में काम किया जा सकता है।

**बिक्री एवं सेवा** : ब्रिकी के क्षेत्र में खाद्य उत्पादों का बेचने, उनके प्रचार संबंधित कार्य होता है, खासकर बच्चों के खाने का। इसमें अनुभव और जानकारी की दृष्टि से गृह विज्ञान के स्नातक उपयुक्त होते हैं। वहीं, सेवा के क्षेत्र में स्नातक छात्र किसी होटल, पर्यटक रिजार्ट, रेस्तरां, कैटरिंग सेंटर में ह्यहाउस कीपिंग डिपार्टमेंटह्न में एवं देखरेख संबंधी कार्य कर सकते हैं।

**शिक्षण** : गृह विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री वालों के पास शिक्षण का क्षेत्र भी अच्छा विकल्प होता है। पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद विद्यार्थी किसी भी स्कूल में शिक्षक बन सकते हैं। वहीं, पीएचडी की डिग्री होने पर कालेज में प्रोफेसर की नौकरी मिल सकती है।

**प्रमुख कालेज**

*लेडी* इरविन कालेज, दिल्ली
*माउंट* कैमरेल कालेज बंगलुरु
*इंस्टिट्यूट* आफ होम इकोनामिक्स, दिल्ली
*बीएमएन* कालेज होम साइंस, महाराष्ट्र
*निरमालागिरी* कालेज, केरल
*क्वीन* मैरी कालेज, चेन्नई

लेडी इरविन कालेज की निदेशक अनूपा सिद्धू का कहना है कि गृह विज्ञान विषय में आप पांच विषयों को मूल रूप में पढ़ते हैं। इसमें आप बीएससी, एमएससी एवं पीएचडी तक कर सकते हैं। इसमें नौकरियों की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। गृह विज्ञान अब केवल भोजन तक ही सीमित नहीं रहा है, वर्तमान में यह बहुत गतिशील पाठ्यक्रम बन चुक है। गृह विज्ञान के पांच मुख्य विषयों में पीजी डिप्लोमा आहार विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण (एक वर्ष), पीजी डिप्लोमा खाद्य एवं पोषण, मानव विकास एवं बाल अध्ययन, कपड़ा एवं परिधान विज्ञान, विकास संचार, संसाधन प्रबंधन और डिजाइन एप्लिकेशन शामिल हैं।

– **सुनील कुमार** *(शिक्षक, डीयू)*

*सूचनापट्ट*

## आइपीयू, दिल्ली

*गुरु* गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (आइपीयू) ने नए सत्र में दाखिले के लिए सभी पाठ्यक्रम में आवेदन की आनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन विश्वविद्यालय के आनलाइन पोर्टल किया जा सकता है। पोर्टल पर स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी में आनलाइन आवेदन के लिए अलग- अलग टैब हैं। आइपीयू ने आवेदकों की सहूलियत के लिए आनलाइन आवेदन फार्म का सरलीकरण किया गया है। इसे तकनीकी रूप से इतना सरल बनाया गया है कि कोई आवेदक अपने मोबाइल फोन से भी आवेदन फार्म भर सकता है। पिछले साल की तरह इस साल भी दाखिले में पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के स्कोर को दी जाएगी। उसके बाद विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षाओं और सीयूईटी स्कोर को प्राथमिकता दी जाएगी।

**अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2024**

## इग्नू, दिल्ली

*इंदिरा* गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), दिल्ली ने जनवरी 2024 सत्र में विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विश्वविद्यालय में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीजी डिप्लोमा में दाखिला लिया जा सकता है। इग्नू के दाखिला पोर्टल के माध्यम से प्रवेश के लिए आनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले उम्मीदवार को अपना पंजीकरण करना होगा। जहां उन्हें अपना ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान आनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। अगर एक ही आवेदन के लिए आपने ने गलती से दो बार भुगतान कर दिया है तो एक बार का भुगतान की राशि वापस आ जाएगी। आवेदन शुल्क के भुगतान के बाद फार्म का प्रिंटआउट लेना न भूलें।

**अंतिम तिथि : 15 फरवरी, 2024**

## जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

*जवाहरलाल* नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के अटल बिहारी बाजपेयी प्रबंधन एवं उद्यमिता स्कूल (एबीवीएसएमई) द्वारा संचालित किए जाने वाले 'मास्टर आफ बिजनेस ऐडमिनिस्ट्रेशन' (एमबीए) में इस साल (बैच 2024-26) दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक युवा जेएनयू की वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत उम्मीदवारों को पहले पंजीकरण करना होगा और फिर आबंटित एप्लीकेशन नंबर व पासवर्ड के माध्यम से लाग-इन करके उम्मीदवार अपना आवेदन आनलाइन जमा कर सकेंगे। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान आनलाइन माध्यमों से करना होगा, जो कि सामान्य, ईडब्लूएस और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2000 रुपए है। जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह आवेदन शुल्क 1000 रुपए ही है।

**अंतिम तिथि : 28 फरवरी, 2024**

## संयुक्त प्रवेश परीक्षा-मुख्य

*संयुक्त* प्रवेश परीक्षा-मुख्य के दूसरे सत्र के लिए आवेदन शुरू हो गए है। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम करने के इच्छुक उम्मीदवार जो जेईई मुख्य-2024 अप्रैल सत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण फार्म जमा करना होगा। परीक्षा तिथियों के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) एक से 15 अप्रैल तक बीई, बीटेक, बीआर्क पेपर एक और दो आयोजित करेगी। एनटीए के मुताबकि जेईई (मुख्य)- 2024 के आनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के दौरान पुष्टिकरण पृष्ठ की एक प्रति के रूप में माता-पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर और ई-मेल प्रदान करना अनिवार्य है, अंतिम स्कोर कार्ड उन्हें भी भेजा जाएगा। केवल वे उम्मीदवार जिन्होंने 2022, 2023 में कक्षा 12 उत्तीर्ण की है, या जो 2024 में कक्षा 12 की परीक्षा में उपस्थित हो रहे हैं, वे जेईई मुख्य 2024 में उपस्थित होने के पात्र हैं।

**अंतिम तिथि : 2 मार्च, 2024**

# कुछ बहाने जो हमें सफल होने से रोकते हैं

*परामर्श*

हम कई बार महसूस करते हैं कि किसी कार्य को शुरू करने से पहले ही हम बहाने बनाने लगते हैं। यही बहाने हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हमारी सफलता में बाधक बनते हैं। ऐसे बहानों को जितनी जल्दी छोड़ सकते हैं, छोड़ दें।

**मेरे पास वक्त नहीं है** : हर व्यक्ति के पास हर दिन चौबीस घंटे ही उपलब्ध होते हैं। इसके बाद भी कुछ लोग बुलंदियों पर तो कुछ लोग रसातल पर होते हैं। इसका कारण है कि वे अपने वक्त का सही से प्रबंधन नहीं करते हैं और कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है। इसलिए जितना भी समय मिले, जब भी मिले हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ाना चाहिए।

**मुझे इसकी जानकारी नहीं है** : कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस संसार में सबकुछ सीख कर आया हो। हमें यहीं पर आकर सबकुछ सीखना होता है। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो उसे सीख लीजिए। उसके बारे में जानकारी लीजिए और आगे बढ़िए लेकिन इस बहाने से बचिए कि आपको जानकारी नहीं है।

**अगर में विफल हो गया तो** : किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ज्यादातर लोगों के सामने यही मुद्दा होता है। सफलता और विफलता की बात तो तब आएगी जब आप कार्य को शुरू करेंगे। कार्य को शुरू करने से पहले ही सफलता या विफलता के बारे में सोच लेना सही नहीं हैं। इसका आकलन करना जरूरी है। लेकिन इस बहाने से बचकर ही लोग सफलता के शिखर तक पहुंचते हैं।

*दीदार*

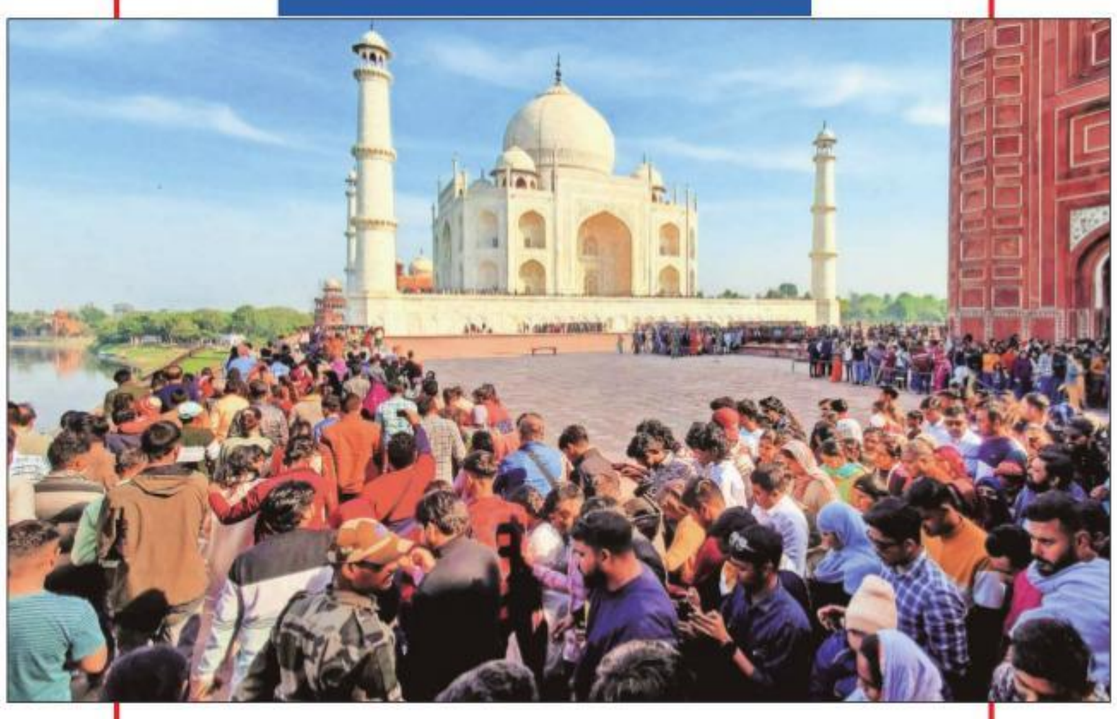

आगरा में बुधवार को शाहजहां के 369वें उर्स के मौके पर ताजमहल को देखने पहुंचे पर्यटक।

# आइआइटी मद्रास ने दाखिले में खेल कोटे को शामिल किया

*जरूरी जानकारी*

देश में पहली बार कोई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) स्नातक दाखिलों में खेल कोटा लागू करने जा रहा है। आइआइटी मद्रास ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 बीटेक पाठ्यक्रम में खेल कोटा शुरू करने की घोषणा की है। बीटेक पाठ्यक्रम में सीट संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) एडवांस की योग्यता के आधार पर ही मिलेगी। ह्यस्पोर्ट्स एक्सीलेंस एडमिशनह्न (एसईए) के तहत स्नातक पाठ्यक्रमों में दो अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। इसमें प्रति स्नातक पाठ्यक्रम में एक सीट लड़कियों के लिए होगी। खेल कोटे में केवल भारतीय नागरिकों को ही सीट मिलेगी। आइआइटी मद्रास के बीटेक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए सबसे पहले जेईई एडवांस 2024 की योग्यता में सफल होना जरूरी होगा। जेईई एडवांस 2024 की योग्यता सूची के बाद खेल कोटे की सूची तैयार होगी। इसके तहत चार साल में किसी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता में कम से कम एक पदक जीता हो। खेल कोटे की सीट सभी आइआइटी में दाखिले के लिए आनलाइन सीट आबंटन करने वाले ह्यजोशा पोर्टलह्न के माध्यम से नहीं मिलेगी। इसके लिए अगल से आइआइटी मद्रास पोर्टल बनाएगा। यहां एक-एक अलग 'स्पोर्ट्स रैंक लिस्ट' (एसआरएल) तैयार की जाएगी। उम्मीदवारों को खेलों की एक विशिष्ट सूची में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाएगा।

**आइआइटी गांधीनगर ने 'डेटा साइंस फार डिसीजन मेकिंग' शुरू किया**

आज की तेजी से विकसित हो रही डिजिटल दुनिया में, उच्च प्रभाव वाले निर्णय लेने के लिए डेटा अब वैश्विक व्यापार के केंद्र में है। तेजी से बढ़ रहे इस अहम क्षेत्र और कुशल डेटा वैज्ञानिकों की बढ़ती मांग के अनुरूप, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) गांधीनगर ने 'डेटा साइंस फार डिसीजन मेकिंग' के रूप में अपना दूसरा ई-मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम शुरू किया है और मई 2024 से शुरू होने वाले इसके पहले बैच के लिए प्रवेश पोर्टल खोला है। आइआइटी गांधीनगर ई-मास्टर्स का बारीकी से डिजाइन किया गया पाठ्यक्रम समावेशी, अभिनव और व्यावहारिक है। दो-वर्षीय कार्यक्रम को एक लचीली, कार्यकारी-अनुकूल संरचना के साथ डिजाइन किया गया है ताकि उम्मीदवारों को अपनी कार्य प्रतिबद्धताओं को समवर्ती रूप से समायोजित करने में सक्षम बनाया जा सके। इसमें शाम और सप्ताहांत में 'लाइव इंटरैक्टिव' सत्र होंगे और रणनीतिक रूप से सीखने और चचाओं के लिए स्व-गति शिक्षण माड्यूल के साथ सहायता मिलेगी। कामकाजी पेशेवर और संबंधित क्षेत्र (जैसे सांख्यिकी/ गणित/ कंप्यूटर विज्ञान/ इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी/ विज्ञान/ अर्थशास्त्र/ वाणिज्य) में स्नातक डिग्री वाले छात्र कार्यक्रम पोर्टल पर अपने आवेदन आनलाइन जमा कर सकते हैं।

**मई परीक्षा के लिए आइसीएआइ ने आवेदन शुरू किए**

इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आइसीएआइ) ने सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल मई परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को आइसीएआइ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। आइसीएआइ सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल मई परीक्षा 2024 के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। आवेदन में संपादन या बदलाव तीन से नौ मार्च तक किया जा सकेगा। समूह-एक के लिए सीए इंटर परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क 1,500 रुपए और दोनों ग्रुपों के लिए 2,700 रुपए. फाइनल कोर्स परीक्षा के समूह-एक के लिए शुल्क 1,800 रुपए और दोनों ग्रुपों के लिए 3,300 रुपए है। सीए फाउंडेशन परीक्षा के लिए पंजीकरण शुल्क 1500 रुपए है। विलंब शुल्क 600 रुपए के साथ आनलाइन आवेदन फार्म जमा करने की अंतिम तिथि दो मार्च, 2024 है। कार्यक्रम के अनुसार आइसीएआइ सीए फाउंडेशन परीक्षा 20, 22, 24 और 26 जून को आयोजित की जाएगी। वहीं, समूह-एक के लिए सीए इंटरमीडिएट कोर्स परीक्षा तीन, पांच और सात मई 2024 को और समूह-दो के लिए परीक्षा नौ, 11 और 13 मई, 2024 को आयोजित की जाएगी। समूह-एक के लिए फाइनल कोर्स परीक्षा दो, चार और छह मई, 2024 को और समूह-दो के लिए आठ, 10 और 12 मई, 2024 को आयोजित की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 16 अंक 303

# ऊर्जा सुरक्षा आवश्यक

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने बुधवार को यह अनुमान जताया कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में कितना इजाफा हो सकता है। आईईए के मुताबिक मांग में इजाफे की सबसे बड़ी वजह भारत होगा जो सबसे बड़े तेल आयातक के रूप में चीन को पछाड़कर शीर्ष पर आ जाएगा। इस समय भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और अनुमान है कि 2023 से 2030 के बीच यहां तेल की मांग में करीब 12 लाख बैरल प्रति दिन का इजाफा होगा। इस प्रकार इस अवधि में कच्चे तेल की मांग में कुल इजाफा 32 लाख बैरल प्रति दिन होगा। यानी वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग वृद्धि में भारत करीब एक तिहाई का हिस्सेदार होगा। इस लिहाज से 2030 तक भारत में प्रतिदिन तेल की खपत 66 लाख बैरल हो जाएगी। आईईए के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन ईंधन के लिए मांग का बढ़ना जारी रहेगा जबकि अन्य देशों में यह या तो स्थिर है या इसमें गिरावट आ रही है।

मांग में इस बढ़ोतरी को पूरा करने के लिए भारत का विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर होना उसकी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील विषय है। तेल कीमतों में वैश्विक वृद्धि के कारण बाहरी खाते और राजकोषीय स्थिति में अव्यवस्था की स्थिति बन सकती है। इससे मुद्रास्फीति में इजाफा होगा, वृद्धि में धीमापन आएगा और राजनीतिक उथल पुथल भी मच सकती है।

इस बीच जीवाश्म ईंधन की आपूर्ति श्रृंखलाएं पश्चिम एशिया में भूराजनीतिक तनाव के लिए जोखिम बनी हुई हैं। ऐसे में सरकार ने जीवाश्म ईंधन के विकल्पों पर जोर देकर सही किया है। आईईए ने अनुमान जताया है कि नए इलेक्ट्रिक वाहन तथा मौजूदा ऊर्जा संसाधनों का किफायती इस्तेमाल देश में मांग वृद्धि में करीब पांच लाख बैरल की कमी लाएंगे। सरकार सौर और पवन ऊर्जा क्षमताओं की स्थापना पर भी जोर दे रही है। परंतु इसके बाद भी भारत निकट भविष्य में तेल और गैस पर निर्भर रहेगा।

इस समस्या को कम करने में दो ही बातें मदद कर सकती हैं। पहली बात, अगर घरेलू संसाधनों का सही ढंग से पता लगाया जाए और उनका समुचित इस्तेमाल किया जाए। दूसरा, अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिए देश की बड़ी तेल एवं गैस कंपनियां खनन क्षेत्रों की खरीद कर सकती हैं। दोनों ही मोर्चों पर कुछ प्रगति हो रही है लेकिन वह पर्याप्त नहीं है।

मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 20 बहुराष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से बातचीत की। इनमें बीपी, वेदांत और एक्सॉनमोबिल शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य तेल की खोज में निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाने का है। बहरहाल, इस नीति में पहले किए गए प्रयासों का इरादा सरकार का राजस्व बढ़ाने का था और निवेशकों के जोखिम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। यह इस क्षेत्र के लिए सही तरीका नहीं है और हाल में इसमें सुधार के लिए किए गए प्रयासों को जारी रखा जाना चाहिए।

ऐसी कई वजह हैं जिनके चलते देश में तेल खनन बढ़ाया जाना चाहिए। नीति निर्माताओं को इस वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए कि कहीं निजी क्षेत्र इससे बहुत अधिक लाभ न अर्जित कर ले। इसके अलावा भारतीय तेल कंपनियों को विदेश में भी प्रयास करने चाहिए। इस सप्ताह खबर आई कि ऑयल इंडिया लिमिटेड लीबिया में वहां की सरकारी तेल कंपनी के साथ मिलकर दोबारा परिचालन शुरू करने को लेकर चर्चा कर रही है। लीबिया अगले तीन से पांच वर्षों के दौरान तेल उत्पादन में प्रतिदिन 75,000 बैरल का इजाफा करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला में ऐसे अन्य प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए वित्तीय और कूटनीतिक समर्थन मुहैया कराया जाना आवश्यक है। भविष्य की प्रतिस्पर्धी क्षमता और भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिरता ऊर्जा की टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर है। ऐसे में घरेलू सुधार और विदेशी पहुंच दोनों सरकार की प्राथमिकता होने चाहिए।

# सोलर दीदी को सशक्त बनाने की कवायद के मायने

**महिलाओं को सौर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का कार्यक्रम गरीबी कम करने के साथ ही ग्रामीण परिवारों को सशक्त बनाने में मददगार साबित हो सकता है। बता रहे हैं जयंत सिन्हा**

भारत में कोयला खनन करने वाले राज्यों को ग्रामीण महिलाओं के लिए विशेष सौर कार्यक्रम से बहुत लाभ मिल सकता है। झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में ऐसे ही 'सोलर दीदी कार्यक्रम' लागू किए जा सकते हैं जिससे नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव लाना सुनिश्चित हो सकेगा।

इस कार्यक्रम के तहत दो से तीन करोड़ महिलाओं को बिजली ग्रिड से जुड़ने वाले 10 किलोवॉट सौर पैनल खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा सकेगा। राज्य वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करेगी जो बाजार मूल्य से अधिक होता है। सौर पैनल से प्रत्येक सोलर दीदी को 2,000 रुपये से अधिक की मासिक आमदनी होगी और इसके साथ-साथ उन्हें 100 यूनिट मुफ्त बिजली भी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जाने वाले सौर पैनलों के निर्माण, उसे लगाने और उससे जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनियों के साथ-साथ लाखों लोगों को रोजगार देने वाला एक संपूर्ण तंत्र तैयार किया जाएगा।

भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो कोयले की अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। ऐसे में अगर हम शून्य कार्बन उत्सर्जन की व्यवस्था को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते हैं तब इन राज्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इन राज्यों के ग्रामीण परिवार मुश्किल से अपना जीवन-यापन कर पाते हैं और वे सीधे या परोक्ष रूप से कोयला खनन से मिलने वाली आय पर निर्भर हैं। कई किसानों के पास सिंचाई की सुविधा वाले खेत भी नहीं होते हैं और ऐसे में उन्हें अपनी आजीविका के लिए गैर-कृषि आमदनी पर निर्भर होना पड़ता है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अधिकांश समुदायों के पास अपना कोई खेत नहीं है और वे ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के रूप में काम करते हैं या पारंपरिक शिल्पों के जरिये अपनी आजीविका जुटाते हैं। ग्रामीण महिलाओं को अपनी घरेलू खेती से होने वाली आमदनी के अलावा भी बकरी और गाय पालने, देसी शराब बेचने और बांस की टोकरियों जैसे हस्तशिल्प तैयार करने जैसी विभिन्न गतिविधियों में जुटे रहना पड़ता है ताकि आजीविका की भरपाई हो सके। निरंतर श्रम करने के बावजूद, झारखंड जैसे राज्यों में औसत ग्रामीण घरेलू आय लगभग 6,000-7,000 रुपये प्रति माह है।

ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी कम करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। महिलाओं को पारंपरिक कपड़े, आभूषण बनाने, मशरूम या अन्य विदेशी सब्जियों की खेती करने के लिए सहकारी समितियों में नामांकित कराया गया है। दुर्भाग्य से इनका ताल्लुक सीधे बाजार से नहीं हो पाता है, इसलिए ऐसे उत्पाद तैयार करना मुश्किल होता है जिनकी लगातार बिक्री हो सकती है। नतीजतन, इन कार्यक्रमों के तहत एक स्थिर मासिक आमदनी देना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए, राज्य सरकारों ने सीधी नकद सहायता देनी शुरू कर दी है जैसे कि मध्य प्रदेश में 'लाडली बहना योजना' के तहत प्रति माह 1,250 रुपये का भुगतान किया जाता है।

सोलर दीदी योजना इन समस्याओं का समाधान करेगी। राशन कार्ड रखने वाला प्रत्येक ग्रामीण परिवार इस योजना का लाभ पाने का पात्र होगा। सौर पैनल का स्वामित्व महिलाओं के पास होगा और इससे होने वाली कुल आमदनी सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाएगी।

आंकड़े कारगर होते हैं। लगभग 5 लाख रुपये की लागत वाले एक 10 किलोवॉट का सोलर पैनल लगाने पर प्रति वर्ष लगभग 12,000 किलोवॉट-घंटे (यूनिट) बिजली पैदा होती है। पूरे भारत में, बिजली वितरण कंपनियां आमतौर पर 4 रुपये प्रति यूनिट (इसमें कोई पूंजीगत सब्सिडी नहीं है) की दर पर दीर्घकालिक सौर बिजली की खरीद करने के लिए तैयार हैं। प्रति माह खुद इस्तेमाल की जाने वाली 100 यूनिट बिजली घटाने के बाद, सौर पैनलों से होने वाली वार्षिक आमदनी का आंकड़ा लगभग 43,000 रुपये है। कार्बन क्रेडिट के माध्यम से प्रति वर्ष 5,000 रुपये और मिल सकते हैं जिससे कुल वार्षिक राजस्व लगभग 48,000 रुपये हो जाता है। सौर पैनल की किस्त (25 साल के लिए और शून्य ब्याज दर के लिहाज से) 20,000 रुपये प्रति वर्ष है। इसके अलावा इसके रखरखाव का खर्च 2,000 रुपये प्रति वर्ष के दायरे में है। बाकी 26,000 रुपये का भुगतान ग्रामीण परिवारों को मासिक आधार पर किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इन परिवारों को 2,000 रुपये से अधिक की मासिक घरेलू आमदनी होती है। यदि इस कार्यक्रम से 2 करोड़ परिवार जुड़ते हैं तब यह भारत की बिजली जरूरतों के लगभग 10 प्रतिशत की आपूर्ति करेगा।

निःशुल्क बिजली कई सकारात्मक प्रभाव ला सकती है। सबसे पहले, घर में बिजली की व्यवस्था होगी। दूसरा, खाना पकाने के लिए इंडक्शन स्टोव का इस्तेमाल किया जा सकता है गैस सिलिंडर की आवश्यकता खत्म हो सकती है। ऐसे में हर घर प्रतिमाह 500 रुपये से अधिक की बचत कर सकते हैं। तीसरा, ग्रामीण परिवार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को अपना सकते हैं, जिससे उनकी पेट्रोल खपत कम हो जाएगी। डीजल/पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के कम इस्तेमाल से भारत बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन आयात कम कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, घरों के लिए बैटरी बैकअप की सुविधा दे सकते हैं जिससे 24 घंटे बिजली आपूर्ति संभव होगी।

ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से सोलर दीदी जैसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन मिलेगा। सौर पैनलों के लिए सब्सिडी की तुलना में ये ऋण, कुशल नीतिगत हस्तक्षेप साबित होंगे क्योंकि यह इसकी एक इकाई के लाभ-लागत का बेहतर आकलन होगा। जैसे-जैसे सौर पैनल के मूलधन का भुगतान किया जाता है, ब्याज भुगतान सब्सिडी कम हो जाती है। यह सब्सिडी विकास वित्तीय संस्थानों, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से मिले-जुले रूप में दी जा सकती है।

निःशुल्क ब्याज वाले ऋण, केंद्र और राज्य की नवीकरणीय विकास एजेंसियों के माध्यम से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। बिजली वितरण कंपनियों को पहले से ही वितरित सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बाजार आधारित शुल्क देने और स्मार्ट मीटर देने का आदेश दिया गया है। इस तरह बिजली वितरण कंपनियां भी पैसा बचाएंगी क्योंकि ग्रामीण परिवार अपनी खुद की बिजली पैदा करेंगे और इसलिए बिजली वितरण कंपनियों को उन्हें मुफ्त यूनिट वाली बिजली की आपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय वितरण नेटवर्क को भी मजबूत करना होगा ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादित सौर ऊर्जा की खपत कर सकें।

संभव है कि एक बार ब्याज मुक्त ऋण जब स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होगा तब उसके बाद, बाजार की ताकतें सामने आएंगी और सोलर दीदी योजना से जुड़ा एक पारिस्थितिकी तंत्र तैयार होगा। सौर पैनल निर्माता किफायती और पैकेज वाले इंस्टॉलेशन मॉड्यूल तैयार करना शुरू कर देंगे क्योंकि उन्हें फिर स्थिर और बढ़ती मांग का आश्वासन मिलेगा। इसके अलावा वायरिंग और मीटर देने वाले भी अपनी पेशकश को इसके अनुकूल बनाएंगे ताकि सौर पैनल आसानी से ग्रिड में प्लग इन हो सकें। बिजली उत्पादन की निगरानी करने के साथ-साथ सुदूर इलाके में इसके रखरखाव करने के लिए इन क्षेत्रों में दूर से ही प्रबंधन करने के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाएंगे। इस तरह की इंस्टॉलेशन कंपनियां सौर इकाइयों को लगाने की होड़ में होगी ताकि वे सौर पैनल लगाने के शुल्क के जरिये पैसा कमा सकें। घर के लिए लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न भंडारण तकनीक तैयार किए जाएंगे। ऐसे में कम कीमत वाली बिजली के चलते जल्द ही दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का विद्युतीकरण होगा।

सोलर दीदी योजना कई तरह के लाभ देती है। इससे भारत के सबसे गरीब परिवारों को एक स्थिर मासिक आमदनी मिलने के साथ ही मुफ्त बिजली भी मिलेगी। साथ ही सौर पैनल निर्माताओं, मीटर उपकरण कंपनियों, सॉफ्टवेयर प्रदाताओं, इंस्टॉल करने वाली कंपनियों और इनकी फंडिंग करने वाली कंपनियों का एक बड़ा तंत्र खड़ा होगा। भारत के पास अर्थव्यवस्था वृद्धि को ताकत देने के लिए स्वच्छ ऊर्जा वाली पर्याप्त बिजली होगी। पैकेज्ड सौर इकाइयां दक्षिण एशिया के लिए एक बड़ा निर्यात उद्योग बन सकती हैं और भारत अपने सबसे कमजोर नागरिकों के लिए न्यायसंगत बदलाव सुनिश्चित करते हुए तेजी से शून्य उत्सर्जन की दिशा में आगे बढ़ेगा।

*(लेखक संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति के अध्यक्ष और हजारीबाग से लोकसभा सदस्य हैं। लेख में उनके व्यक्तिगत विचार हैं)*

# प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बढ़त पर अमेरिका

नीति नियम

मिहिर शर्मा

**कुछ** लोगों के लिए यह याद करना मुश्किल हो सकता है लेकिन महज दो दशक पहले अमेरिका और यूरोप का बड़ा हिस्सा प्रति व्यक्ति आय के मामले में तुलनात्मक रूप से एक समान था। यह समानता उनके उत्पादों की प्रतिस्पर्धा तथा उनकी कंपनियों की वैश्विक कद में नजर आती थी। वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान पश्चिमी दुनिया के इन दोनों हिस्सों में अंतर बढ़ने लगा और उसके बाद यूरो क्षेत्र के ऋण संकट ने हालात और मुश्किल बना दिए। महामारी ने इसमें और इजाफा किया और यूक्रेन युद्ध के बाद के दो वर्षों में हालात विकट हो गए।

वर्ष 2008 में यूरो क्षेत्र और अमेरिका के उत्पादन में करीब 50 हजार करोड़ डॉलर का अंतर आ गया। दोनों का आकार 14 लाख करोड़ डॉलर और 15 लाख करोड़ डॉलर के बीच था। 2023 तक यूरो क्षेत्र करीब 15 लाख करोड़ डॉलर पर ही अटका है जबकि अमेरिका ने अपने वार्षिक उत्पादन में करीब 12 लाख करोड़ डॉलर और जोड़ दिए हैं। दुनिया की बडी कंपनियों में यूरोप की कंपनियां बहुत कम रह गई हैं। इनमें एलवीएमएच जैसे लक्जरी ब्रांड और नोवार्टिस जैसी औषधि कंपनियां शामिल हैं।

यह अंतर क्यों आया? कई लोग अमेरिकी डॉलर की शक्ति को दोष देते हैं जो अमेरिका को यह अवसर देता है कि वह शेष विश्व से ऋण लेकर अपने उपभोक्ताओं और कंपनियों की घरेलू मदद कर सके। निश्चित तौर पर यूरोपीय संघ के सख्त राजकोषीय नियमों के कारण संकट के बाद की कटौती ने उसे और प्रभावित किया। जर्मनी जो दो दशक में यूरोप का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, वह भी मंदी के हालात से जूझ रहा है। उसके कर्ज पर रोक लग गई है और वह उसकी अनदेखी करने के मामले में राजनीतिक समर्थन नहीं जुटा पा रहा।

परंतु इसकी और वजहें भी हैं। पहली, तकनीकी नवाचार को लेकर नियमन हैं, दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनियां सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां हैं। ये सभी अमेरिकी कंपनियां हैं और अमेरिकी शेयर बाजार में हालिया तेजी के पीछे भी यही हैं। इनमें से कुछ इसलिए सीमित हैं कि उनकी पहुंच चीन के विशाल उपभोक्ता बाजार तक नहीं है। ऐपल अभी भी चीन में कारोबार कर रही है लेकिन गूगल और फेसबुक नहीं। ऐपल के राजस्व का 20 फीसदी चीन से आता है। परंतु अधिकांश बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियां इस बाधा से उबर चुकी हैं और उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रौद्योगिकी नियमन को लेकर यूरोप का रुख बहुत रूढ़िवादी है और ऐसा लगता है कि उसने सिलिकन वैली जैसा कुछ बनाने की कोशिश त्याग दी है।

परंतु शायद इस अंतर में सबसे अधिक योगदान ऊर्जा की लागत में अंतर का है। वित्तीय संकट के बाद के 15 वर्षों में अमेरिका एक बार फिर संसाधनों की महाशक्ति बन गया है। यह भूलना आसान है कि एक सदी पहले तेल समेत सस्ते संसाधनों से उसके उत्थान में अहम भूमिका निभाई थी। यह संभव है कि जॉन डी रॉकफेलर की स्टैंडर्ड ऑयल (सन 1911 में अमेरिकी सरकार के आदेश पर तोड़े जाने के पहले) आधुनिक युग की सबसे बड़ी तेल कंपनी थी और उसका जो दबदबा था, उसकी कभी कोई बराबरी नहीं कर सका। उस समय संसाधनों का बाजार इतना एकीकृत नहीं था। आर्थिक इतिहासकारों की बात करें तो गेविन राइट ने लिखा है, '1879 से 1940 की अवधि में अमेरिकी विनिर्माण निर्यात का सबसे अहम गुण था तेल एवं लौह अयस्क समेत ऐसे प्राकृतिक संसाधनों की तीव्रता जिन्हें बार-बार उत्पन्न नहीं किया जा सकता था।' यह वर्चस्व तब टूटा जब आसानी से निकलने वाले संसाधनों का इस्तेमाल शुरु हुआ और विश्व स्तर पर बाजार एकीकृत हुए।

बीते एक दशक में अमेरिका में शेल गैस क्रांति ने रुझान उलट दिया और अमेरिका एक बार फिर पहले विश्व युद्ध से पहले की स्थिति में आ गया। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में स्वतंत्रता हासिल हुई और अब अमेरिका ऊर्जा का निर्यात कर रहा है तथा ईंधन कीमतों के प्रबंधन की मदद से अपने प्रतिद्वंद्वियों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को प्रभावित कर रहा है।

यूरोप रूस की प्राकृतिक गैस की मदद से कुछ हद तक प्रतिस्पर्धी बना रहा। परंतु यूक्रेन के बाद वह विकल्प भी कारगर नहीं रहा। 2023 के अंत तक यह अपने यहां आने वाली तरल प्राकृतिक गैस पर निर्भर हो गया। तरल प्राकृतिक गैस को समुद्र के रास्ते ढोया जाता है जिससे कीमत पर असर पड़ना तय है। अब जबकि यूरोप रूसी पाइपलाइन के बजाय तरल प्राकृतिक गैस पर अधिक निर्भर है तो यूरोप की लागत अमेरिका की तुलना में 3.5 गुना तक हो सकती है।

कुछ निंदक कह सकते हैं कि रूस पर प्रतिबंधों का डिजाइन अमेरिका की तुलना में यूरोप को अधिक नुकसान पहुंचाने वाला है। उदाहरण के लिए प्रतिबंध तेल एवं गैस पर केंद्रित हैं लेकिन रूसी यूरेनियम अब तक इससे बाहर है। यह यूरेनियम अमेरिका के उन 90 से अधिक नाभिकीय रिएक्टरों को ईंधन देता है जो उसकी 20 फीसदी ऊर्जा के लिए जवाबदेह है।

वे इस बात पर भी ध्यान दे सकते हैं कि अमेरिका अपने यूरोपीय प्रतिस्पर्धियों पर लगातार दबाव बना रहा है। गत सप्ताह अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि वह तरल प्राकृतिक गैस के नए टर्मिनल की फंडिंग रोक देगा ताकि दुनिया भर में निर्यात के लिए अमेरिकी गैस का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसे पर्यावरणविदों को रियायत के रूप में प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि प्राकृतिक गैस ढांचे से मीथेन का रिसाव होता है। अमेरिकी प्रशासन और पर्यावरण समर्थकों दोनों ने कहा कि इससे अमेरिका में प्राकृतिक गैस की घरेलू कीमत कम बनी रहेगी। यूरोप, जो कि अपनी ऊर्जा कीमतों में कमी के लिए अमेरिका पर निर्भर था, उसे सस्ती ऊर्जा पर निर्भर अमेरिकी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धी घाटा सहना जारी रखना होगा।

यह समझना आसान है कि अमेरिका की आर्थिक नीतियों के बाह्य प्रभाव के कारण उसके ज्यादातर सहयोगियों को संदेह होने लगा है कि वह अपने प्रतिबंधात्मक शासन और पर्यावरण नीति के पीछे पुराने समय के आर्थिक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहनता है। कोरिया और जापान जैसे उसके पूर्वी एशियाई सहयोगियों की शिकायत है कि अमेरिकी कानून उन पर दबाव बनाता है कि वे चीनी आपूर्ति को अपनी मूल्य शृंखला से अलग करें जबकि अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों को उसी कानून के तहत रियायत दी जाए। इन्फ्लेशन रिडक्शन ऐक्ट अमेरिकी कंपनियों को भारी भरकम सब्सिडी देता है जो स्वच्छ हाइड्रोजन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को अमेरिका में भारी सब्सिडी तभी मिलती है जबकि कार अमेरिका में बनी हों।

एक व्यापक दावा यह किया जा सकता है कि मानव प्रयासों से जुड़े तमाम क्षेत्रों में अमेरिका उस स्थिति से पीछे हट रहा है जिस पर उसने 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभ में अपने उभार के दौरान दबदबा बनाया था। वह भूराजनीति में अलगाववादी रुख बरकरार रखते हुए आर्थिक प्रभुत्व बनाए रखने के लिए अपने प्राकृतिक संसाधनों तथा बंटे हुए वैश्विक बाजारों का लाभ ले रहा है। ऐसे में वे सभी देश जो बीती एक सदी में एक बाजार, पूंजी के स्रोत और सुरक्षा प्रदान करने वाले देश के रूप में अमेरिका पर यकीन करते आए हैं उन्हें नई योजनाएं तैयार करनी पड़ सकती हैं।

## आपका पक्ष

### व्यापार के लिए आसियान का महत्त्व

लेख 'भारत के लिए आसियान की अहमियत' दक्षिण पूर्व के देशों के इस संगठन के साथ भारत के वैश्विक व्यापार की बहुत गंभीर चर्चा करता है। हाल में हुए जी 20 समूह के देशों के सफल आयोजन ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत किया है। ब्रूनेई, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम के आसियान संगठन की सकल जीडीपी 2.9 ट्रिलियन डॉलर और 64 करोड़ की जनसंख्या वैश्विक व्यापार के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। जनसांख्यिकीय लाभ के अनुसार इन देशों में जापान और अन्य विकसित देशों ने मैन्युफैक्चरिंग का आधार निर्मित किया है जो भारत के लिए चुनौती है। वैश्विक स्तर पर भारत की भागीदारी बढ़ाने, नेतृत्व स्थापित करने व अग्रसर रखने के प्रयास गंभीरता से इससे पहले कभी नहीं हुए और भारत चीन, अमेरिका और यूरोपीय देशों का पिछलग्गू बना रहा। पिछली सरकारों ने पहली बार लुक ईस्ट की नीति पर विचार किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्ट ईस्ट की नीति पर काम किया। आसियान और क्षेत्रीय समूहों में चीन का विशेष प्रभाव है इसलिए भारत को विश्व के हर उस मंच पर व समूह में अपनी भागीदारी और प्रभाव स्थापित करने की जरूरत है जहां चीन का प्रभाव है।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

**हाल में हुए जी 20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन ने वैश्विक स्तर पर भारत की साख को मजबूत किया है**

### उद्यमशीलता व रोजगार को भी बढ़ावा

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम से सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अभी योजना में 3 किलोवॉट तक के सोलर पैनल से बिजली बनाने पर 40 फीसदी मिलेगी। सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। इससे उनकी खुद की बिजली की जरूरत तो पूरी होगी ही, साथ ही वे अतिरिक्त बिजली बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग में भी मदद करेगी। सौर इकाइयों की स्थापना के लिए बड़ी संख्या में विक्रेताओं के लिए उद्यमशीलता और तकनीकी कौशल वाले युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

*रोली श्रीवास्तव, नई दिल्ली*

### किफायती बनाने की जरूरत

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से पहले सन रूफटॉप योजना चल रही थी। अब नाम बदलकर इसे रीलॉन्च किया गया है। यह योजना सरकार के सब्सिडी देने के बावजूद एक खर्चीली है जिसे और किफायती बनाना चाहिए तभी यह योजना सफल होगी। इस योजना की भी सीमाएं हैं जैसे ये छत वाले घरों में ही निष्पादित हो पाएगी, मध्य वर्ग के पास इतनी बचत नहीं है कि वह इसे अपना सके।

*डॉ. प्रमेंद्र विक्रम सिंह, जौनपुर*

### कार्बन उत्सर्जन में कमी

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना से गरीब वर्ग, मध्य वर्ग और जरूरतमंद लोगों के हितों की रक्षा की जाएगी। घरों की छत पर सोलर पैनल से बिजली पैदा करने से पैसों की बचत हो सकेगी। साथ ही कार्बन उत्सर्जन भी रोका जा सकेगा। इसके लिए बिजली उपभोक्ताओं को जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

*प्रदीप गौतम सुमन, रीवा*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

**राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पद संभालने के बाद पहली बार बुधवार को दिल्ली मेट्रो में सफर किया। राष्ट्रपति ने मेट्रो की वॉयलेट लाइन पर यात्रा के दौरान स्कूली छात्राओं से बातचीत भी की।**

## धन्यवाद प्रस्ताव

### मोदी का आत्मविश्वास

**संसद में 'धन्यवाद प्रस्ताव'** पर भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास सामने आया। राष्ट्रपति के संबोधन पर 'धन्यवाद प्रस्ताव' पर हुई बहस का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जोरदार जवाब दिया। अपने भाषण में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाईं तथा भविष्य के लिए दृष्टिकोण रेखांकित किया। इस प्रक्रिया में उन्होंने राष्ट्र को आकर्षित करने वाली साहसी घोषणा कर डाली कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को 'कम से कम 370 सीटें' मिलने जा रही हैं। उनकी यह घोषणा समर्थकों और पार्टी सदस्यों के लिए मधुर संगीत की तरह है। मोदी ने अपनी यह प्रतिबद्धता पुन: दुहराई कि वे भारत को विश्व शक्ति बना देंगे। प्रतिबद्धता तथा आशावाद से भरे इस भाषण में राष्ट्र की पूरी क्षमतायें उजागर करने के प्रयास जारी रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। 'कम से कम 370 सीटों' पर प्रधानमंत्री का जोर देना प्रशासन में पार्टी का विश्वास तथा उसकी नीतियों का जनता द्वारा समर्थन प्रकट करता है। यह आंकड़ा मनमाना नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने की ओर संकेत से इसका ऐतिहासिक महत्व है। यह रणनीतिक संदर्भ स्थापना के समय से ही अपने प्रमुख सिद्धान्तों के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता तथा नीतिगत एजेंडे का सफल क्रियान्वयन है। यह सच है कि मोदी के नेतृत्व में भाजपा के पास एक अजेय चुनाव मशीनरी है जो एक के बाद दूसरे चुनाव में जीतती तथा विपक्ष को कमजोर करती जा रही है। भाजपा ने अपने दो मुख्य वादे- अनुच्छेद 370 की समाप्ति व अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पूरे कर लिए हैं, जबकि समान नागरिक संहिता तथा 'एक देश एक चुनाव' की ओर वह आगे बढ़ रही है। इसलिए वह तार्किक रूप से मतदाताओं के पास यह दावा करते हुए जा सकती है कि उसने अपने वादे पूरे किए हैं। इस प्रकार मोदी का आशावाद गलत नहीं कहा जा सकता है और सीटों की गिनती लफ्फाजी न होकर वास्तविक हो सकती है।

स्वाभाविक रूप से मोदी की इस घोषणा ने राजनेताओं में उथलपुथल पैदा कर दी है। विपक्षी नेताओं ने इतनी भारी विजय की संभावना पर सवाल उठाते हुए जोर दिया है कि शासन के मुद्दों पर ज्यादा गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए। कांग्रेस और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अनेक मोर्चों पर भाजपा को चुनौती दी है जिनमें आर्थिक नीतियों से लेकर सामाजिक मुद्दे तक शामिल हैं। इसकी प्रतिक्रिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जनता के जनादेश और भाजपा नेतृत्व पर विश्वास प्रकट किया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि उनकी पार्टी मतदाताओं से जुड़ने तथा उनके सरोकारों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में सक्षम है। मोदी की साहसी घोषणा के पीछे सावधानी से बनाई गई चुनावी रणनीति है। भाजपा सचेतन रूप से अपनी जड़ें मजबूत करने पर काम कर रही है, उसने तकनीक का लाभ उठाया है तथा नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की सफलता ने उसका विश्वास बढ़ाया है। 370 सीटों के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के प्रति उसका विश्वास अपने एजेंडे के प्रति यह विश्वास है कि वह बहुसंख्य मतदाताओं की भावनायें अभिव्यक्त करता है। हालांकि, इस समय उसे दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें समावेशी आर्थिक विकास व रोजगार सृजन को सर्वोच्च स्थान मिलना चाहिए। भारत की जनता ने राष्ट्र की बेहतरी के लिए भाजपा को अपना पूरा समर्थन तथा प्रबल जनादेश दिया है। ऐसे में भाजपा की जिम्मेदारी है कि वह इसका सम्मान करे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शब्दों से इसी जिम्मेदारी तथा जनादेश के प्रति प्रतिबद्धता की भावना प्रकट होती है।

# क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के दांवपेंच

**क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपनी कार्यविधि पूरी तरह पारदर्शी, विचार-विमर्श आधारित तथा वस्तुनिष्ठ बनानी चाहिए ताकि वे सटीक रूप से सही तस्वीर पेश कर सकें।**

**गोविंद भट्टाचार्जी**
(लेखक, आर्थिक नीति विशेषज्ञ हैं)

पिछले 15 वर्षों में भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तथा इसी कालखंड में वह अन्य देशों की तुलना में दूसरी सबसे तेज वृद्धि दर प्राप्त कर सका है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे निचला निवेश ग्रेड मिला है। अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों-सीआरए में से फिच व एसएंडपी ने उसे बीबीबी तथा मूडी ने बीएए3 रेटिंग दी है। निवेश ग्रेड का अर्थ कर्ज भुगतान पर कम जोखिम तथा कम रेटिंग का अर्थ अधिक जोखिम या 'स्पीकुलेटिव ग्रेड' है। भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति तथा इसके बढ़ते अंतरराष्ट्रीय सम्मान का सीआरए पर कोई असर नहीं पड़ा है।

मुख्य आर्थिक सलाहाकार द्वारा हाल ही में जारी संग्रह 'रि-इक्जामिनिंग नेरेटिव्स: अ कलेक्शन आफ एस्सेज़' के पहले निबंध में सीआरए को अपने भीतर सुधार की आवश्यकता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि संप्रभु रेटिंग प्रक्रिया को ठीक से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का जोखिम परिभाषित करना चाहिए। इससे वे फंडिंग खर्च में अरबों डालर की बचत कर सकते हैं जो उनके विकास के लिए जरूरी है। सीआरए विश्व बैंक व आईएमएफ के ब्रेटन वुड्स संस्थानों के पहले से हैं। वे सरकारों को कर्ज देने की क्षमता का विश्लेषण कर उनकी 'सावरेन रेटिंग्स' निर्धारित करते हैं। इनसे दुनिया भर के निवेशकों को सरकारों द्वारा कर्ज लेने की 'इच्छा' तथा कर्ज अदा करने में उनकी 'सामर्थ्य' का पता चलता है। इसके आधार पर ही वैश्विक कर्जदाताओं से कर्ज लेने की उनकी क्षमता तथा ब्याज दरें निर्धारित होती हैं।

अच्छी रेटिंग से कर्ज सस्ता मिलता है तथा विदेशी निवेश आकर्षित होता है। संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उपायों से न केवल किसी देश की समग्र आर्थिक स्थिति का पता चलता है, बल्कि इससे विदेशी, सार्वजनिक व निजी कर्ज की मात्रा, शेयर बाजारों में पारदर्शिता, आरक्षित मुद्रा भंडार तथा राजनीतिक स्थिरता व आर्थिक स्थायित्व का पता भी चलता है। यह राजनीतिक लेनदेन में भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सीआरए के वस्तुनिष्ठ आंकलन तथा क्रियाविधियां पारदर्शी नहीं हैं।

सीआरए पश्चिमी सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों की तरह हैं जिनमें से कुछ की विश्वसनीयता और क्षमता सवालों के घेरे में है। वे देशों की रैंकिंग ऐसे मुद्दों के आधार पर करती हैं जिनमें लोकतंत्र, प्रशासन, भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जेंडर समानता, मानवाधिकार, सरकारों का खुलापन, आदि शामिल हैं। इसके लिए वे बहुत छोटे नमूनों या 'विशेषज्ञों' की राय पर आधारित होती हैं जिनकी चयन प्रक्रिया पूरी तरह अपारदर्शी है। वे ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग करती हैं जिनमें वस्तुनिष्ठता का अभाव होता है, उनकी क्रियाविधियों में पारदर्शिता की कमी होती है तथा वे देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतामूलक चरित्र को अनदेखा करती हैं। वे अपनी प्रक्रियाओं के बारे में उन देशों से विचार-विमर्श तक नहीं करती हैं। इन एजेंसियों के माध्यम से कमजोर हो रहे पश्चिमी देश अपना 'सांस्कृतिक उपनिवेशवाद' चलाते हैं तथा पश्चिमी अवधारणाओं, पश्चिमी मूल्यों व पश्चिमी दृष्टिकोणों को विकसित देशों पर थोपने का प्रयास करते हैं। पश्चिमी देश अब भी विकासशील देशों को समान मानने के बजाय स्वयं को उनसे 'श्रेष्ठ' मानते हैं और इस प्रकार वे विकासशील देशों पर अपने मानक गलत तरीके से थोपने का प्रयास करते हैं। इन सबके साथ असली समस्या तब पैदा होती है जब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान अक्सर अपने निर्णय इन रैंकिंगों के आधार पर करते हैं। अक्सर अंतरराष्ट्रीय तुलना अनुचित होती है और इन रैंकिंगों में संदिग्धता को कम से कम 'अवैज्ञानिक' जरूर कहा जा सकता है। हालांकि, चीन और भारत के उभार के बाद स्थितियां बदल रही हैं। चीन अब उनको पूरी घृणा के साथ देखता है, लेकिन वह अपनी तानाशाही व्यवस्था के प्रति खामोशी बरतता है। अब भारतीयों ने भी उनकी विधियों पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं तथा उनकी कमजोरियां, विरोधाभासों और बड़बोलेपन को उजागर कर रहे हैं। दूसरे देश भी देर-सवेर ऐसी ही रणनीति अपनाएंगे। वर्तमान समय में दुनिया बहु-ध्रुवीय तथा चेतना-संचालित है, ऐसे में उसे केवल पश्चिमी विमर्श स्वीकारने के बजाय अनेक विमर्शों को अपने भीतर समाहित करना चाहिए।

वैश्विक क्रेडिट रेटिंग उद्योग एक प्रकार का एकाधिकार है जिसमें केवल तीन प्रमुख एजेंसियां-मूडी, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स तथा फिच शामिल हैं। सावरेन रेटिंग के लिए सीआरए विभिन्न मानकों का प्रयोग करती हैं जिनमें वृद्धि, मुद्रास्फीति, सरकारी कर्ज, अल्पकालीन बाहरी कर्ज तथा राजनीतिक स्थिरता शामिल हैं। गुणात्मक आयाम भी क्रेडिट रेटिंग तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सीईए रिपोर्ट के अनुसार, 'संस्थागत गुणवत्ता मुख्यत: विकासशील अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग तय करने में अपनी भूमिका अदा करती है जिसका निर्धारण विश्व बैंक के वैश्विक प्रशासनिक सूचकांक-डब्लूजीआई करते हैं। यह अपने आप में समस्या है क्योंकि ये आयाम गैर-पारदर्शी, दृष्टिकोण-आधारित तथा छोटे विशेषज्ञ समूहों द्वारा निर्धारित होते हैं। ये संप्रभु द्वारा भुगतान करने की इच्छा का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं।'

वित्तीय संकट तथा 2007-09 की महामंदी के बाद सीआरए और नियामक व्यवस्था आलोचना का शिकार हुए। तर्क दिया गया कि उन्होंने बंधक-आधारित सिक्यूरिटीज़ के बारे में गलत सूचनायें दी थीं और उनको सर्वोच्च एएए रेटिंग दी गई थी। इससे खराब निवेशों की मात्रा बहुत बढ़ गई थी। उन पर अपने मुनाफे बढ़ाने तथा शेयर बाजारों में गलत रेटिंग के कारण निवेशकों को आकर्षित करने के आरोप लगे जिससे सबप्राइम बंधक बाजार ध्वस्त हो गया और इसने वित्तीय संकट को और गहरा बना दिया। अमेरिका में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में सुधार के लिए कानून बनाया गया। इसी तरह अन्य देशों ने भी इन पर नियमन के प्रयास किए जिनमें यूरोपियन सिक्यूरिटीज़ एंड मार्केट्स अथारिटी तथा भारत की सेबी शामिल हैं। लेकिन रेटिंग एजेंसियों की क्रियाविधियों में कमियों के खुलासे के बावजूद उनकी पारदर्शिता या वस्तुनिष्ठता में कोई सुधार नहीं हुआ।

सुधार के ये प्रयास भी केवल 'प्रतीकात्मक' बने रहे क्योंकि इनके कारण रेटिंग एजेंसियों के कामकाज में अपारदर्शिता की एक और सतह जुड़ गई। अनेक तत्व अब भी गुणात्मक आंकलन पर आधारित हैं जिनके चलते सीआरए विभिन्न देशों के बारे में अपनी अवधारणायें बनाती हैं। इन तत्वों में राजनीतिक स्थिरता और क्षमता, वित्तीय क्षेत्र के जोखिम, मैक्रोआर्थिक नीति की विश्वसनीयता व लचीलापन, पांच सालों के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान, मैक्रोइकोनोमिक स्थायित्व, राजकोषीय वित्तीय लचीलापन, सार्वजनिक कर्ज का टिकाऊपन तथा राजकोषीय ढांचा शामिल हैं। रेटिंग एजेंसियों की क्रियाविधि अंतिम रेटिंग में इन गुणात्मक आयामों को दिए जाने वाले महत्व पर खामोश है। यहां तक कि डब्लूजीआई भी अनेक अन्य संकेतकों का प्रयोग करता है जिसमें वैश्विक प्रतियोगिता क्षमता, स्वतंत्रता, कानून का शासन, भ्रष्टाचार, नियमन की गुणवत्ता, आदि शामिल हैं। इनका निर्धारण भी अलग-अलग एजेंसियों द्वारा किया जाता है जो मोटे तौर से दृष्टिकोण-आधारित हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडी दो गुणात्मक मानकों-आर्थिक शक्ति व राजकोषीय शक्ति को दो गुणात्मक आयामों-संस्थागत व प्रशासनिक शक्ति तथा जोखिम के अवसर की संभावना से जोड़ देती है। इस प्रकार अंतिम रेटिंग तय करने में डब्लूजीआई आईएंडजीएस को 40 प्रतिशत महत्व देती है। एसएंडपी 'लचीलेपन व प्रदर्शन प्रोफाइल' को 'संस्थागत व आर्थिक प्रोफाइल' से जोड़ कर एक 'संकेतक रेटिंग स्तर' तय करती है। लेकिन इन मानकों को दिया जाने वाला स्थान न तो पूर्व निर्धारित है और न इसका कोई मानक है। वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के इन गलत आंकलनों का प्रभाव कर्ज लेने वाले देशों पर पड़ता है जिससे विकासशील देश सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। समय आ गया है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अपनी कार्यविधि पूरी तरह पारदर्शी, विचार-विमर्श आधारित तथा वस्तुनिष्ठ बनानी चाहिए ताकि वे सटीक रूप से भारत समेत अन्य विकासशील देशों की सही तस्वीर पेश कर सकें।

# विकास संकेतक सुधार में एनजीओ की भूमिका

**फौज़िया ख़ान**
(लेखिका, संसद सदस्य हैं)

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) सामाजिक विकास के अभिन्न वास्तुकार बन गए हैं, जो प्रमुख विकास संकेतकों पर एक अमिट छाप छोड़ रहे हैं और सामुदायिक विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। एनजीओ परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, परिवर्तन में अंतराल को संबोधित करते हैं, हाशिए पर रहने वाले समूहों का समर्थन करते हैं, आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं और बेहतर नीतिगत निर्णय लेते हैं। उनके कार्यों में एक व्यापक स्पेक्ट्रम शामिल है, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल से लेकर महिला सशक्तिकरण और पर्यावरणीय स्थिरता तक शामिल है।

भारत में, गैर सरकारी संगठनों ने परिवर्तनकारी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है, जिससे विकास संकेतकों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। शिक्षा-केंद्रित पहल साक्षरता दर बढ़ाने में योगदान करती हैं; स्वास्थ्य देखभाल परियोजनाओं से मातृ एवं शिशु मृत्यु दर कम होती है; और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम लैंगिक समानता पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशिया (पीआरआईए) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 2021 तक, 26.5 प्रतिशत एनजीओ धार्मिक गतिविधियों में लगे हुए हैं, जबकि 21.3 प्रतिशत सामुदायिक और/या सामाजिक सेवाओं में काम करते हैं। लगभग पांच में से एक एनजीओ शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, जबकि 17.9 प्रतिशत खेल और संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय हैं, और केवल 6.6 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करते हैं।

इसके अतिरिक्त, स्वच्छ जल, स्वच्छता और टिकाऊ पर्यावरणीय प्रथाओं तक पहुंच भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ग्रेट प्लेस टू वर्क इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 80त्न गैर सरकारी संगठन मुख्य रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने और गरीबी उन्मूलन की दिशा में काम करने पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं।

इसके अलावा, भारतीय लोकतंत्र के जटिल परिदृश्य में, लगभग 3.4 मिलियन गैर सरकारी संगठन राज्य की पहलों द्वारा छोड़ी गई कमियों को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपदा राहत से परे, गैर सरकारी संगठन मानवाधिकारों से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के मुद्दों को संबोधित करते हुए विविध गतिविधियों में संलग्न हैं। कोविड-19 संकट के दौरान, उन्होंने तत्काल जरूरतों को पूरा करने में अपनी चपलता का प्रदर्शन करते हुए, कमजोर आबादी को आवश्यक सहायता प्रदान की। समर्थक के रूप में कार्य करते हुए, गैर सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूहों के साथ सहयोग करते हैं, जिससे जमीनी स्तर की पहल का प्रभाव बढ़ता है। वे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाते हैं, उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग करने और शासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाते हैं।

गैर सरकारी संगठनों ने सहभागी शासन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है, 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम सहित ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण में योगदान दिया है। सामाजिक मध्यस्थों के रूप में कार्य करते हुए, गैर सरकारी संगठन सामाजिक स्तरों पर हस्तक्षेप करते हैं, प्रचलित मानदंडों को चुनौती देते हैं और जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। अंधविश्वास, आस्था और रीति-रिवाज में डूबे समाज में, वे परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं, दृष्टिकोण और व्यवहार को आकार देते हैं। अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, एनजीओ सीमित फंडिंग, परिचालन बाधाओं और टिकाऊ मॉडल की आवश्यकता जैसी चुनौतियों से जूझते हैं। इन चुनौतियों पर काबू पाने के लिए लचीलेपन और नवीनता की आवश्यकता होती है क्योंकि गैर सरकारी संगठन उन समुदायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक समाधान तलाशते हैं जिनकी वे सेवा करते हैं।

एक अध्ययन से पता चलता है कि भारतीय गैर सरकारी संगठनों को अपनी प्रभावशीलता में बाधा डालने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ख़राब वित्तीय नियोजन सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में बाधा डालता है, जिसके लिए मजबूत वित्तीय रणनीतियों की आवश्यकता होती है। मानकीकृत कानूनी मॉडल की अनुपस्थिति वित्तीय कमजोरी को बढ़ाती है, स्थिरता को खतरे में डालती है। मानव संसाधनों में अपर्याप्त निवेश, कर्मचारियों को बनाए रखने में लापरवाही के साथ, परियोजना प्रबंधन पर अल्पकालिक फोकस से उत्पन्न होता है। कर्मचारी प्रतिधारण चुनौतियाँ और प्रोत्साहन के लिए अपर्याप्त धन मनोबल पर प्रभाव डालते हैं। कमजोर मानव संसाधन प्रबंधन, संसाधन कुप्रबंधन और शासन सिद्धांतों की सीमित समझ गैर सरकारी संगठनों में और बाधा डालती है। इन्हें संबोधित करने के लिए, केंद्र सरकार को अनुदान नियमों को उदार बनाना चाहिए। गैर सरकारी संगठनों को मानव संसाधन दिशानिर्देश स्थापित करने चाहिए, धन के दुरुपयोग को रोकना चाहिए और राजनीतिक हस्तक्षेप से बचना चाहिए। समुदाय-निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने से भारत में एनजीओ का प्रभाव बढ़ सकता है। गैर सरकारी संगठनों के लिए अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सहयोग महत्वपूर्ण है। सरकारी निकायों, कॉर्पोरेट संस्थाओं और अन्य गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी पहल की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाती है। सफल सहयोग प्रत्येक भागीदार की ताकत का लाभ उठाते हैं, जिससे जटिल सामाजिक मुद्दों का व्यापक और टिकाऊ समाधान प्राप्त होता है। प्रौद्योगिकी को अपनाना, सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देना और क्षमता निर्माण में निवेश करना गैर सरकारी संगठनों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं में से एक है। उदाहरण के लिए, ग्रो फंड ने चल रहे क्षमता-निर्माण और संगठनात्मक विकास सत्र शुरू किए हैं, जिससे एनजीओ को निगरानी, विक्रेताओं के साथ व्यवस्थित जुड़ाव और डेटा एनालिटिक्स के महत्व को समझने में सशक्त बनाया जा सके। इसने संगठनात्मक शक्तियों की समग्र समझ को बढ़ावा देने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गैर सरकारी संगठनों के लिए तलाशने का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र समुदाय-आधारित संस्थानों को विकसित करना और स्थानीय प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह गैर सरकारी संगठनों को स्थानीय चुनौतियों के लिए नवीन समाधानों को बढ़ावा देने, विकासात्मक परियोजनाओं की प्रभावी ढंग से योजना बनाने, लागू करने और मूल्यांकन करने का अधिकार देता है। समुदाय-संचालित दृष्टिकोण अपनाकर, गैर सरकारी संगठन स्थानीय संसाधनों तक पहुंच सकते हैं और जिन लोगों की वे सेवा करते हैं, उनसे अधिक समर्थन प्राप्त कर सकते हैं।

## आप की बात

### योगी का आह्वान

**संत कबीरनगर** में कबीर मगहर महोत्सव में योगी आदित्यनाथ ने लोगों से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के उच्च लक्ष्य प्राप्त कर रहा है तथा आत्मनिर्भर भारत व नए भारत की अवधारणा हर जगह नजर आ रही है। देश-प्रदेश में भयमुक्त माहौल से दुनिया भर के लोग यहां निवेश करने आ रहे हैं। समारोह में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कबीर के बिना मगहर बंजर जमीन व खारी पानी के कारण नरक था। लेकिन कबीर के आगमन ने क्षेत्र को स्वर्ग बना दिया। इसी प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास के मार्ग में आने वाली बाधायें दूर कर, विकास व सर्वजन हिताय की भावना से अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाकर तथा लोगो को कोरोना महामारी के दौरान भी हर सम्भव मदद दे कर नई प्रगति का मार्ग दिखाया है। उन्होंने कहा कि मोदी के विकास कार्यो की गूंज सारी दुनियां में सुनाई पड़ी तथा भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मोदी आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व लोकप्रिय नेताओं में एक हैं। योगी आदित्यनाथ के आह्वान का जनता ने स्वागत किया है। देखना होगा कि मोदी के शब्दों में आम चुनाव में भाजपा सचमुच 370 पार होगी या नहीं।

– **कुलदीप मोहन त्रिवेदी,** उन्नाव

### पटाखों पर लगाम

**हरदा** में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के बाद हड़कंप मच गया है। कहा जाता है कि अवैध फैक्ट्री में करीब 15 टन विस्फोटक रखा हुआ था जिसमें आग लगने से तेज धमाके होने लगे। हादसे में कई लोगों की जान गई तथा लगभग 60 घरों जल गए। राजधानी भोपाल के निकट स्थित शहर में भारी मात्रा में विस्फोटकों के साथ अवैध फैक्ट्री चलना कुछ भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत की ओर संकेत करता है। पहले भी प्रदेश के कई शहरों में पटाखों के कारण बड़े हादसे हुए हैं। वर्तमान भयानक विस्फोट से आशंका होती है कि कहीं पटाखों के नाम पर यहां अवैध बम तो नहीं बनाए जा रहे थे। पटाखों और आतिशबाजी के कारण अनेक अग्निकांड होते हैं, अनेक लोगों की जानें जाती हैं तथा पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। पटाखों के नाम पर अवैध रूप से बम बनाने वालों या पटाखा बमों का आपराधिक प्रयोग करने वालों को मौका मिल जाता है। इसे देखते हुए पटाखों के निर्माण, व्यापार और प्रयोग पर लगाम लगानी चाहिए तथा कुछ त्योहारों, आदि के अवसर पर पर्यावरण प्रदूषण का ध्यान रखते हुए ही आतिशबाजी के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। इस व्यवसाय में लगे लोगों को वैकल्पिक रोजगार मिलने चाहिए।

– **सुभाष बुड़ावन वाला,** रतलाम

### जनसंख्या समस्या

**कुछ देश** आज बढ़ती आबादी के कारण परेशान हैं। इसके साथ ही कई देश अपने यहाँ लगातार घट रही जन्मदर से अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहे हैं। कभी सर्वाधिक आबादी वाला चीन अब दूसरे नंबर पर आ गया है। जापान, इटली, ग्रीस, हंगरी, पोलैंड, पुर्तगाल, क्यूबा व दक्षिण कोरिया आदि घटती आबादी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दक्षिण कोरिया में कॉर्पोरेट सेक्टर जन्मदर बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित कर रहा है। कहा जा रहा है कि अगर अगले 20 वर्षों तक जन्म दर ऐसे ही घटती रही तो दक्षिण कोरिया के लिए अस्तित्व का संकट पैदा हो जायेगा। दक्षिण कोरिया समेत पश्चिमी देशों में घटती जनसंख्या उन देशों के लिए चेतावनी है जो कठोर कानूनों के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण करना चाहते हैं। विज्ञान व तकनीक की प्रगति से सुख-सुविधायें बढ़ने के बावजूद अनेक समृद्ध युवा विवाह कर बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं क्योंकि उनके पालन-पोषण का खर्च बहुत अधिक है तथा इसे वे अपनी स्वतंत्रता में बाधा भी मानते हैं। ऐसे में समाज को बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा व देखभाल की ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे नौजवान विवाह कर बच्चे पैदा करने को बोझ न समझें।

– **जंग बहादुर सिंह,** जमशेदपुर

### ट्रैफिक जाम

**ट्रैफिक जाम** की समस्या अब पूरे देश में जैसे महामारी की तरह फैल रही है। महानगरों के बाद अब तो छोटे-छोटे कस्बों तक में ट्रैफिक जाम लगने लगे हैं। इस बढ़ती समस्या के अनेक कारण हैं। बढ़ती हुई आबादी की तरह ही साल दर साल सड़कों पर नए वाहनों की बड़ी खेप उतरती है जिनमें बड़ी-बड़ी चौपहिया कारों की संख्या भी कम नहीं है। इसके साथ ही अनेक दूकानदार सड़क तक अपना सामान फैलाने तथा आने वाले दोपहिया वाहनों के लिए भी स्थान न छोड़ने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानने लगे हैं। इसके अलावा फुटपाथ पर व ठेलों पर सामान बेचने वाले सड़कों पर अतिक्रमण कर लेते हैं। इससे वाहन निकलना क्या, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। प्रशासन को अब सभी अतिक्रमण पूरी तरह हटाकर और अधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी करके यातायात को व्यवस्थित करना चाहिए। अत्यधिक भीड़ वाले क्षेत्रों में चौपहिया ले जाने पर रोक लगनी चाहिए। सार्वजनिक परिवहन में पर्याप्त वृद्धि कर भी सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या नियंत्रित की जा सकती है। ठेलों-खोमचों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

**पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से**
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
**पर भी भेज सकते हैं।**